The birth place of CIVILIZATIONS
India and Middle - East

Dr. Dharmendra Kumar Shukla,
Dr. Pallavi, Kirti Kumar Pandey

BlueRoseONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Dr. Dharmendra Kumar Shukla, Dr. Pallavi,
Kirti Kumar Pandey 2025

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication,
please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7018-354-4

Cover Design: Aman Sharma
Typesetting: Pooja Sharma

First Edition: October 2025

Disclaimer

Some of the images included in this book have been sourced from various websites and search engines such as Google. These images are used for illustrative purposes only. All copyrights and trademarks are acknowledged and remain the property of their respective owners.

Dr. Dharmendra Kumar Shukla born in Amethi district of Uttar Pradesh. His early education takes place in Gonda, UP. He has done his graduation in Military science, Psychology, and Sociology as subjects from Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda and done his post graduation in Military science from Kamtanath Sunderlal Saket P.G. College, Ayodhya. Also has Phd. from Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya. He has participated in more than 30 national and international seminars and also published not less than 7 research journals in UGC listed. He has written chapters in 4 different books . Currently he is working as Assistant professor in Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, in department of Defence and strategic studies, Gonda since 2003. He has more than 22 years of teaching experience. He has very deep knowledge on Defence related topics. Due to his teaching experience of so many years in this subject and also his research activities he gives a unique insight about issues related to his subject.

Kirti Kumar Pandey was born in Prayagraj, Uttar Pradesh. He completed his primary education in his home district, Prayagraj. He then obtained his graduate degree in Political Science, Medieval History, and Economics from Allahabad Central University. He pursued a postgraduate degree in Political Science from Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, and earned a degree in Education (B.Ed.) from Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya. He has also qualified UGC-NET in Political Science.

He has taught in secondary and inter colleges for more than ten years. He has attend various national and international seminars. During his academic journey, he has received numerous awards. Currently, he is working as an Assistant Professor (Political Science) at Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya, and is posted at Mahavidyalaya Sant Tulsi Das P.G. College, Kadipur, Sultanpur. He is counted among the dedicated educators.

Dr. Pallavi is currently working as Assistant Professor in Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda (Uttar Pradesh), in the department of Geography. She has done Ph.D in Geography with topic "Integrated Rural Development: A case study of Poora Block", also done MA in Geography. Dr Pallavi UGC – Net/JRF in 2009, and has also done BEd. She had worked as Principal in G.I.C. Bhaduali , Poora, Ayodhya for one 4 years years (2017-2021). She has deep knowledge in Geography and has a passion of teaching this can be traced through her educational background as She has done Ph.D. in her subject as well as B.Ed. she is keen in teaching Geography subject in a simpler form as to take away fear of Geography from students. Dr. Pallavi has published more than 15 research papers in national and international magazines, she is regular in publishing these research papers. Dr. Pallavi has attended various seminars and conferences related to Geography subject.

Contents

इजराइल फिलिस्तीन–विवाद की एतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान वातावरणः 1

India and the Middle East: A Bond developed by Geography..32

मध्य पूर्व के देशों की सामान्य जानकारी.............................. 42

'मध्य–पूर्व के देशों का भूगोल': *Geography of Middle East Countries*..52

China and the Middle East..62

'ईरान और मध्य पूर्व': 'Iran & The Middle East'.................74

IMEC-India Middle East-Europe Economic Corridor.......85

'अरब स्प्रिंग': 'Arab Spring' 96

इजराइल–फिलिस्तीन का संघर्ष एवं पश्चिमी एशिया पर उसका प्रभाव– 107

मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका: United State of America & Middle East...116

I2U2: A Game Changer of the Middle East and The Global Politics..127

रूस–मध्य और पूर्व संबंधः भू–राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण.. 137

मध्य–पूर्व के भविष्य की संभावनाएं 147

जलवायु परिवर्तनः मध्य पूर्व की चुनौतियाँ.......................... 156

भारत–इजराइल संबंध अतीत से वर्तमानः चुनौतियाँ और संभावना 166

रूस–यूक्रेन युद्ध का भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव 175

इजराइल फिलिस्तीन-विवाद की एतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान वातावरणः

डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला

असिस्टेंट प्रोफेसर,

रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज,

गोण्डा (उ0प्र0)

पश्चिम एशिया में बसे दो–देश इजराइल और फिलिस्तीन जिनका क्षेत्रफल क्रमशः इजराइल का क्षेत्रफल 22070 कि0मी0 स्क्वायर और फिलिस्तीन का क्षेत्रफल 6020 किमी0 स्क्वायर है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दोनों देश बहुत बड़े नहीं है इनकी तुलना अगर भारत के क्षेत्रफल से की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 3287263 किमी0 स्क्वायर है जो कि विश्व का 2.4 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो फिलिस्तीन की आवादी 55 लाख है और इजराइल की आबादी 90 लाख से कुछ अधिक है। दोनों देशों की आबादी की तुलना पडोस के देश मिस्र से की जाए तो मिस्र की आबादी 11 करोड़ से अधिक है। यदि देखा जाए तो न ही क्षेत्रफल की और न ही आबादी की दृष्टि से दोनों देश मिलकर भी उतने प्रभावशाली है, फिर भी चाहे 20वीं शताब्दी हो या 21वीं शताब्दी हो दोनों देशों ने विश्व को दो खेमों में बाँट कर रखा है। सामान्य लोगों की दृष्टि में विवाद की शुरुआत 1948 से होती

है लेकिन अगर गहनता से देखा जाए तो 1948 इस विवाद का मात्र एक पड़ाव भर ही है। इस विवाद का इतिहास हजारों साल पुराना है, यह विवाद मात्र जमीन के अधिकार तक सीमित न होकर, एक अत्यंत पेंचीदा विषय है, जिसमें तीन अलग–अलग धर्मों की सहभागिता है। यह इसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म के इतिहास और धार्मिक पवित्र स्थलों के अधिकारों हेतु वर्चस्व की लड़ाई है।

वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच लगातार एक साल से अधिक सैन्य संघर्ष चल रहा है जिसमें करीब 40 हजार से अधिक अभी तक अपनी जान गवा चुके हैं। अगर इन दोनों देशों के विवाद को समझना है और सुलझाना है तो हमें हजारों वर्षों के इतिहास को जानने और समझने की आवश्यकता है।

संघर्ष का इतिहास–

इस संघर्ष को पूर्णतया जानने व समझने के लिए हमें इसाई यहूदी और इस्लाम धर्मों के बारे में जानने की आवश्यकता हैः–

यहूदी–

यहूदी धर्म, इन तीनों धर्मों में सबसे प्राचीनतम धर्म है। वर्तमान में यहूदी धर्म को मानने वालों की आबादी 1.5 करोड़ है जो कि विश्व जनसंख्या की 0.02 प्रतिशत है। इजराइल ही एक मात्र ऐसा देश है, जहाँ पर यहूदी धर्म मानने वाले लोग बहुसंख्यक है। इस धर्म को मानने वाले सिर्फ एक ईश्वरीय सत्ता को मानते है जो इनके अनुसार पूरी सृष्टि चला रहा है। इनके धर्म में मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं किया जाता है। यहूदी लोग अपने ईश्वर को याहुवे Yahweh या कहीं–कहीं यहोवा भी जो कि एक प्राचीन लेवेंटाइन देवता था जो इजराइल और यहूदा के इजराइली राज्यों का राष्ट्रीय देवता था हालांकि देवता की उत्पत्ति के बारे में कोई आम सहमति मौजूद नहीं है, विद्वान आमतौर पर तर्क देते हैं कि यहोवा सेइर, एदोम, पारान और लेमान से जुड़ा हुआ है और बाद में कनान के साथ उनकी पूजा की उत्पत्ति कम से कम लौह युग की शुरुआत तक पहुँचती है और सम्भवतः कांस्य युग के अंत तक, हालाँकि बेबीलोन को कैद से पहले इजराइलियों का धर्म वहुदेव वादी था, यहोवा का देवता वाद में यहूदी धर्म और सामरीवाद में भगवान की अवधारणाओं में विकसित हुआ जो सख्ती से एकेश्ररवादी धर्मों में से एक हैं यहूदी धर्म की शुरुआत प्रॉफेट अब्राहम से मानी जाती है। यहूदी धर्म की जड़े इजराइलियों के साथ जुड़ी हुई हैं।

प्रमुख पैगम्बर/नबी

1. इब्राहिम
2. इसहॉक
3. जैकब
4. मूसा
5. हारून
6. जोशुआ
7. पिन्चस/पिन्चस
8. एल्काना

प्रमुख धर्म ग्रन्थ–

हिबरु बाइबिल

इसाई–

तीनों धर्मों में दूसरा सबसे प्राचीन धर्म इसाई है वर्तमान मे इसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग सम्पूर्ण विश्व में 240 करोड है, जो कि विश्व जनसंख्या का 31 प्रतिशत है। करीब 125 देशों में इसाई बहुसंख्यक है. इसाई लोग अपने ईश्वर को गॉड (GOD) नाम से पुकारते हैं। इसाई धर्म के अनुनायी भी एक ही ईश्वरीय सता में विश्वास रखते है कि ईश्वर के पुत्र के रूप में इसाई लोग अपने भगवान को ईशा मसीह नाम के रूप में मानते हैं.। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसम्बर, 6 ईसा

पूर्व को हुआ था। इसी वजह से हर साल 25 दिसम्बर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है हालांकि वाइबल में ईसा

मसीह के जन्म की तारीख का जिक्र नहीं हुआ है। फिलहाल ईसा मसीह का जन्म रोमन साम्राज्य के वेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह के माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के जन्म से एक दिन पहले मरियम और जोसेफ के सपने में स्वर्ग के दूत ग्रेबियल आए थे। ईसा मसीह की धर्म शिक्षा को ही ईसाई धर्म कहा जाता है। ईसा मसीह की मृत्यु क्रूस पर चढ़ाए जाने से हुई थी।

प्रमुख पैगम्बर/नवी–

इब्राहिम

इस्माईल

जैकव

आइसेक (Isaac)

नोह (Noah) आदि

प्रमुख ग्रन्थ–बाइबिल (Bible)

इस्लाम–

इस्लाम धर्म की शुरुआत सतवीं शताब्दी से मानी जाती है तीनो धर्मों में यह धर्म सबसे आधुनिकतम धर्म है। वर्तमान में इस्लाम धर्म को मानने वाले लागों की संख्या लगभग 190 करोड़ है यह विश्व आबादी का लगभग 25 प्रतिशत है। करीब 49 देशों में इस्लाम को मानने वाले लोग बहुसंख्यक है। ये लोग भी सिर्फ एक ही सत्ता को मानते है, कि कोई एक ही ईश्वरीय शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ईश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं।

प्रमुख पैगम्बर/नवी

1. पैगम्बर मुहम्मद
2. इब्राहिम
3. इस्माइल
4. याकूब
5. मूस्र
6. दाउद्र
7. सुलेमान
8. हारून
9. युसुफ

प्रमुख ग्रन्थ–कुरान (धर्म ग्रन्थ)

इब्राहिम–

कुछ ऐसे पैगम्बर व नबी है जिनको तीनों धर्मो के लोग अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख नाम इब्राहिम का है। इब्राहिम का जन्म 2150ई0 पू० में सुमेर इराक में माना जाता है इनकी मृत्यु 1975 ई. पू० हिब्रॉन, इजराइल में हुई थी इनके दो प्रमुख पुत्रों में पुत्रों के नाम इस्माइल, आइसैक या इसहॉक था। इस्माइल की ही परम्परा में आगे जाकर मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसहॉक की परम्परा में आगे जाकर जूडोह या यहूदा का जन्म हुआ था। इब्राहिम के इन दोनों पुत्रों से क्रमशः इस्लाम और यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। इस्लाम धर्म के पवित्रतम स्थान काबा का निर्माण इब्राहिम और इस्माइल द्वारा कराया गया था। इसहॉक के पुत्र का नाम याकूब इजराइल था इनके 12 पुत्रों से इजराइल में 12 अलग–अलग जनजातियाँ बनी जिनमें सबसे अहम जनजति जूडाह को याकूब के बेटे यहूदा, जुडाह ने बनाया था।

हजरत मूसा–

12 जनजातियों में आगे चलकर आपस में विवाद शुरू हो गये है। इनमें से कुछ जनजातियों ने मिस्र में शरण ली। वहाँ पर भी यहूदी काफी प्रताड़ित किए गए। उन्हें वहाँ पर गुलाम बनाकर रखा जाता था। इसकी वजह की बात की जाए तो शरण पाने के कुछ ही समय वाद यहूदी लोग बड़ी ही तेजी से आर्थिक और सामाजिक रूप से मूल मिस्र के निवासियों से काफी आगे निकल गए। जिसके कारण इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगा और इन्हे इनको खूब प्रताड़ित किया गया। इसी प्रताड़ना के दौरान एक ऐसा दौर आया जब मिस्र के राजा ने सभी यहूदी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। इसी समय हजरत मूसा भी एक यहूदी बालक थे। इनको इनकी माता जी

ने बचाया, और कालान्तर में मिस्र के शाही परिवार ने इन्हें अनजाने में गोद ले लिया आगे चलकर और बिना यह जाने की यह यहूदी है। हजरत मूसा मिस्र के शाही परिवार में पले–पढ़े और लालन–पालन हुआ। बड़े होकर उन्होंने एक दिन एक मिस्र के अधिकारी की हत्या कर दी जो कि यहूदी गुलामों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। इस कारण इनकी यहूदी पहचान सबके सामने आ गयी। इस घटना के बाद हजरत मूसा लाल सागर पार करके मदीना में चले गये कुछ दिन वही अपना जीवन यापन किए। मदीने में हजरत मूसा को याहवे का संदेश भी प्राप्त हुआ याहवे ने सभी यहूदियों को पुनः मिस्र लौटने को कहा और मिस्र के राजा से इजाजत लेकर अन्य यहूदी गुलामों को आजाद कराने का आदेश दिया इस आदेश के पश्चात् हजरत मूसा मिस्र पहुँचे और वहाँ पर मिस्र के राजा से याहवे के संदेश के बारे में चर्चा की, परन्तु मिस्र के राजा ने याहवे की बातों को पूरी तरह से नकार दिया। इस मुलाकात के कुछ समय पश्चात् मिस्र में एक के बाद एक दस प्लेग (महामारी) आई, जिनमें हजारों लोगों ने अपनी जान गवाँ दी। आखिरकार इन परिस्थितयों को देखकर मिस्र के राजा, याहवे के आदेशों को मानने के लिए बाध्य हो गए और उन्होंने सभी यहूदी गुलामों को आजाद कर दिया। इस आदेश के बाद हजरत मूसा सभी यहूदियों को लेकर मिस्र से सिनाई की ओर निकल गए और वहीं पर बस गये। कुछ समय के बाद हजरत मूसा को यहूदियों के भगवान से एक बार फिर संदेश प्राप्त हुआ।

उस संदेश में यहूदियों के भगवान ने दस आज्ञाए दी और हजरत मूसा को इन 10 आज्ञाओं को लिख कर हमेशा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश दिया। 40 सालों तक विचरण करने के बाद हजरत मूसा ने माउन्टनीबो (जॉर्डन) में अन्तिम सांस ली। जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली, मान्यता

है कि उस समय उनका मुख आज के इजराइल की ओर था उनके ईश्वर याहवे ने यहूदियों को अपना देश देने का वादा इब्राहिम जैकब, और हजरत मूसा समेत अन्य पैगम्बरों से किया है। उसी स्थान पर आज का इजराइल बसा हुआ है। जिसे यहूदी The Promised Land कहते हैं।

राजा सौल (King Saul, Devid), सोलोमन और संयुक्त राज्य इजराइल (यूनाइटेड किंगडम आफ इजराइल आज के ही इजराइल के स्थान पर यूनाइटेड किंगडम आफ इजराइल नामक एक राज्य हुआ करता था, जहाँ पर, कुछ यहूदी राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। इनमें राजा सौलोमन सबाने अहम राजा थे। इन्हीं के ही शासन काल के दौरान यरुशलम में पहला यहूदी मंदिर वनाया गया और इसी मन्दिर में यहूदी ईश्वर की बताई हुई 10 भाषाएं राजा द्वारा रखवायी गई और यरुशलम का यह मन्दिर आस्थाओं और मान्यताओं का केन्द्र बन गया राजा सोलोमन की मृत्यु के बाद यूनाइटेड किंगडम आफ इजराइल दो भागों में बंट गया और धीरे–धीरे बिखरता चला गया। बाहरी आक्रमण भी मुख्य कारण रहे जिसके कारण यहूदी राज्य का विघटन हो गया। प्रमुख आक्रमणों में मेसोपोटामियाँ और बेबीलोनिया का आक्रमण माना जाता है। इसी वेवीलोनिया के आक्रमण में यहूदियों द्वारा यरुशलम में बनाए गए मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। वेवीलोनिया के आक्रमण के बाद कई यहूदी अपना देश छोड़कर अन्य देशों में शरण ले लिए इस दौरान कुछ यहूदी पहली बार भारत भी आए।

कुछ वर्षों पश्चात् पर्शिया के राजा ने वेवीलोनिया साम्राज्य को हरा दिया जिससे यहूदियों ने राहत की साँस ली और येरुशलम के उसी स्थान पर दूबारा मन्दिर बनाया गया।

रोम साम्राज्य और यरुशलम–

63 ई0–पू0 में रोमन साम्राज्य ने यरुशलम पर विजय प्राप्त कर ली और पूरा इजराइल रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया हालांकि कुछ शर्तों के साथ इजराइल के राजा काफी हद तक स्वतंत्र ही रहे। इसी दौरान राजा हेरोड ने इजराइल पर शासन किया। उन्होंने यहूदी मान्यताओं के कई क्षेत्रों को विकसित किया जिनमें टेंम्पल माउन्ट और हिब्रॉन की गुफा भी शामिल है। राजा हेरोड यहूदी साम्राज्य के महानतम राजाओं में से एक थे। जहाँ तक यरुशलम का प्रश्न है तो यह मृत सागर के पास दक्षिणी लेंवट में स्थित एक शहर है यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है? यह शहर यहूदी पंथ, ईसाई पंथ और इस्लामी पंथ तीनों की पवित्र नगरी है।

ईसा मसीह–

ईसा मसीह का जन्म 4 ई0पू0 में हेरोडियन साम्राज्य में हुआ था उनका जन्म तब के इजराइल साम्राज्य के वैथलेहम नामक शहर में हुआ था जन्म से ईसा मसीह एक यहूदी थे। वाल्या अवस्था से ही उनका टेंम्पल माउण्ट में आना जाना हुआ करता था। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इसाई धर्म मुख्यतः तीन प्रमुख संप्रदाय में विभाजित है– कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स तथा इनका धर्मग्रन्थ बाइबिल है। ईसामसीह को पहले से चला रहे प्रॉफेट की परम्परा का एक प्रॉफेट माना जाता है। इन्होंने दुनिया को एक नया नियम दिया और लोगों को प्रेम करना सिखाया। इन्होंने धीरे–धीरे भाषण देना शुरु किया और कई चमत्कार भी किए। उन्हीं कारणों से इनकी प्रसिद्धि धीरे–धीरे तमाम इजराइल के इलाकों तक पहुँच गई।

ईसा मसीह/यरुशलम में–

जब ईसा मसीह यरुशलम पहुँचे तो लोगों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत हुआ यरूशलम शहर पहुँचकर वे टेम्पल माउण्ट में गए और वहीं पर साफ सफाई की और तमाम बुरे लोगों को वहाँ से निकाला जिस कारण मन्दिर प्रबन्धन के लोग उनसे काफी नाराज हो गए और मन्दिर के सुरक्षा कर्मियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के पहले ही रात को इन्होंने सुप्रसिद्ध अन्तिम भोज ग्रहण किया था जिसे ईसाई Last Supper भी कहते हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें यहूदियों की धार्मिक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ पर उन्हें मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गयी हलाँकि यहूदियों के राजा इस सजा के खिलाफ थे लेकिन उन्होंने धार्मिक सभा के फैसले को लेकर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। सजा के कुछ समय के पश्चात् ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया।

सूली पर चढ़ाए जाने के तीन दिन पश्चात् ही वे पुनः जीवित हो गए थे जीवित होने के पश्चात् बड़ी तेजी से उन्होंने अपने तमाम भाषणों से अपने विचारों को फैलाया। अपने जीवन काल में उनके द्वारा किए गए तमाम चमत्कारों के कारण लोग उनसे बड़ीं तेजी से आकर्षित होते गए। अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के बाद वे पुनः स्वर्ग को चले गए। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार वे पुनः धरती पर आयेंगे और दुबारा अपना बलिदान देकर सभी मनुष्यों को मुक्त कर देगें और उन्हें स्वर्ग को पुनः ले जाएगें। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह का दूसरा जन्म भी इजराइ ल में ही होगा, इन सब कारणों की वजह से ईसाई मान्यताओं में इजराइल का एक अहम स्थान है।

रोमन साम्राज्य/यहूदी टकराव–

ईसा मसीह के स्वर्ग में जाने के उपरान्त धीरे–धीरे ईसाई धर्म एक धर्म के रुप में उभरने लगा ईसाई विचार का प्रसार रोमन साम्राज्य में तीव्र गति से फैलने लगा और काफी लोग ईसाई धर्म को मानने लगे बीतते वर्षों के साथ यह संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। ईसाई धर्म के फैलने के साथ–साथ ही यहूदी धर्म के लोगों के प्रति नफरत भी रोमन साम्राज्य में फैलने लगी रोमन साम्राज्य में रहने वाले काफी लोग यहूदी धर्म के लोगों को ही ईसा मसीह का हत्यारा मानते थे। रोमन साम्राज्य की जनता के दबाव के कारण रोमन साम्राज्य के राजा इजराइल पर हमला करने के लिए मजबूर हो गये। चूँकि तब इजराइल रोमन. साम्राज्य के ही अधीन था पर यहूदी राजाओ को काफी स्वतंत्रता थी किन्तु ईसाई–यहूदी विचार के टकराव के कारण, धीरे–धीरे रामेन साम्राज्य और इजराइल राज्य के सम्बन्ध खराब होने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि तमाम दबाओं के कारण रोमन 66 AD से 73 AD तक लगातार हमले किए। इन्हीं हमलों के दौरान रोमन साम्राज्य ने टेंम्पल माउन्ट को पुनः तोड़ गया और येरुसलम के शहर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। 135 AD आते–आते रोमन साम्राज्य ने लगभग सभी यहूदियों को इजराइल से बाहर निकाल दिया और इजराइल को एक नया नाम फिलिस्तीन दे दिया।

यहूदियों के लिए इजराइल/यरुशलम का महत्व–

यहूदी विचार पूर्ण रूप से धर्म में इजराइल में ही परिवर्तित हुआ था मूसा की मृत्यु के समय मूसा का मुँह इजराइल की ही ओर था। यहूदी प्रवक्ताओं की माने तो ईश्वर ने उन्हें जिस स्थान का वादा किया था वह स्थान इजराइल ही है जो कि The Promised Land भी कहा जाता है और इसके

अलावा यहूदी ईश्वर के द्वारा जो दस आदेश हजरत भूसा को बताए गए थे वे भी लिखकर यरुशलम में ही रक्खे गये थे, हिब्रॉन जहाँ पर हजरत इब्राहिम समेत उनके परिवार की कब्रगाह है वो भी यहूदियों के धार्मिक स्थलों में से एक है, टेम्पल माउण्ट भी यरुशलम में ही स्थिति है। इन तमाम कारणों की वजह से यहूदियों के लिए इजराइल और यरुशलम का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। महत्ता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरे दुनिया के यहूदी जब प्रार्थना करते हैं तब उनका मुख यरुशलम की ओर ही होता है।

ईसाई रोमन साम्राज्य के दौरान फिलिस्तीन और यरुशलम–

306 AD राजा कॉन्स्टेंटाइन रोमन साम्राज्य के राजा बन गए उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन ईसाई धर्म को दे दिया इनके शासन काल के दौरान यहूदी काफी प्रताणित किए गए। और बचे यहूदी भी इजराइल छोड़कर दूसरे साम्राज्यों में जाने हेतु विवश हो गए। 380 AD आते–आते रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता दे दी गई। रोमन साम्राज्य के आधिकारिक और पूर्वी रोमन साम्राज्य का शासन 638 AD चला इन वर्षों में इजराइल से यहूदी लगभग नगण्य या समाप्त हो गए। एक समय यह भी था कि यूहदियों को पूरे यरुशलम के शहर से ही प्रतिबन्धित कर दिया गया था।

इस्लाम–फिलिस्तीन और यरुशलम–

पैगम्बर मोहम्मद के जीवन काल से इस्लाम एक धर्म के रूप में आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ और अन्य देशों में तीव्र गति से फैलाने लगा। पैगम्बर मोहम्मद के अनुसार इब्राहिम, मूसा, ईसा मसीह समेत अन्य सभी पैगम्बर मुस्लिम ही थे। पैगम्बर मोहम्मद के जीवन का ज्यादातर हिस्सा मक्का और मदीना में ही व्यतीत हुआ। शुरुआती दिनों में मक्का और मदीना ही इस्लाम धर्म के केन्द्र के रुप में उभरे। पैगम्बर

मोहम्मद और यरुशलम के सम्बन्ध की बात करें तो इसकी चर्चा हदीस में मिलती है। इसका जिक्र कुरान में नहीं है। हदीस के अनुसार 621 AD के आस–पास पैगम्बर मोहम्मद ने एक रात्रि को यरुशलम की यात्रा की थी। पैगम्बर मुहम्मद फरिश्ते सि जेब्राइल द्वारा लाए गए बुर्राक नामक एक अलौकिक पंखो वालों घोड़े जैसे प्राणी के माध्यम से यरुशलम की यात्रा की। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगम्बर मुहम्मद ने टेम्पल माउण्ट अल–अक्सा मस्जिद में प्रार्थना की प्रार्थना के बाद वहीं से स्वर्ग की यात्रा की और स्वर्ग जाकर इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इम्ब्राहिम, मूसा समेत अन्य पैगम्बरों से मुलाकात की। इसके बाद पुनः लौट कर धरती पर आ गए। इस मान्यता के कारण इस्लाम धर्म के लिए भी यरुशलम एक महत्वपूर्ण स्थान है और फिलहाल अल–अक्सा मस्जिद का नियंत्रण इस्लाम धर्म के पास ही है, यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों के पास पश्चिमी दीवार की पूजा करने का ही अधिकार है। हिब्रॉन शहर जहाँ पर इब्राहिम समेत परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रगाह है वह स्थान भी इस्लाम धर्म के पवित्रतम स्थानों में से एक है।

फिलिस्तीन और यरुशलम में इस्लामिक शासन–

इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर जो 634 AD लेकर 644 AD तक खलीफा के पद पर रहे। इनके शासन के दौरान 638 AD में उमर खलीफा ने यरुशलम को अपने अधिकार में ले लिया और शहर जाकर टेम्पल माउन्ट में जाकर प्रार्थना की। खलीफा उमर ने यहूदियों को यरुशलम में रहने की और प्रार्थना करने की इजाजत दे दी। यह इजाजत मिलने के बाद कई यहूदी पुनः इजराइल आकर बस गए। हालाँकि इन वर्षों के दौरान यह स्थान फिलिस्तीन के नाम से ही जाना जाता था और फिलिस्तीन में इस्लाम धर्म ही बहुसंख्यक धर्म के रूप

में स्थापित था यहूदी धर्म के लोग फिलिस्तीन में काफी कम सख्या में थे। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के बाद से लेकर ओटोमन साम्राज्य के समय तक इस्लाम और यहूदी धर्म में अच्छे सम्बन्ध थे। और इस समयावधि के दौरान ईसाई और यहूदी धर्म के सम्बन्ध मुख्यतः सामान्य ही रहे। कुछ मौकों पट यहूदी और इसाई धर्म के बीच टकराव भी देखा गया।

यूरोप में यहूदी विरोधी भावना का प्रसार–

लगभग 850 AD के समय से यूरोप में यहूदी विरोधी विचार धारा फैलने लगी। इनके के प्रमुख कारणों में से ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की घटना और यहूदी धर्म के लोगों का अन्य की अपेक्षा आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होना था।

यूरोप में यहूदी विचार फैलने के कारण कई यहूदी 1881 से 1903 के बीच में यूरोप से पलायन करके पुनः फिलिस्तीन की ओर वापस लौटे। सन 1904 से 1919 के बीच रूस से भी कई यहूदियों ने पलायन किया।

प्रथम विश्व युद्ध व बाल्फोर घोषणा–पत्र –

बाल्फोर घोषणा पत्र 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया एक सार्वजनिक बयान था जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र की स्थापना के लिए अपने समर्थन की घोषणा की गई थी। 1918 में ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य को हराकर फिलिस्तीन पर अपना कब्जा स्थापित किया जिस कारण बाल्फोर घोषणा–पत्र को लागू करने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई। सन 1922 में लीग आफ नेशन संगठन ने ब्रिटेन को यह बाल्कोर घोषणा–पत्र लागू करने की जिम्मेदारी सौपी साल 1920 के ही समय से यहूदी और इस्लाम धर्म के टकराव ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इसी दौरान फिलिस्तीन में काफी

दंगे हुए। इन टकरावों के कारण ब्रिटेन वाल्फोर घोषणा–पत्र लागू करने में असफल रहा। 1919 से 1923, 1924–1929 और 1930 के समय अवधि में लारवों की सख्या में यहूदी अलग–अलग देशों से फिलिस्तीन में आकर बस गए। इस विश्वास से की एक दिन उन्हें अपना राष्ट्र इजराइल पुनः वापस मिल जाएगा।

अरब विद्रोह और ब्रिटेन की नीति में बदलाव

फिलिस्तीन में अरब नागरिकों ने 1936 से 1939 के दौरान एक बड़ा विद्रोह आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यहूदियों को फिलिस्तीन आने से रोकना और फिलिस्तीन में रह–रहे यहूदियों को फिलिस्तीन से बाहर करना था। इस विद्रोह के दौरान कई यहूदियों की और ब्रिटेन के कई सौनिकों की मृत्यु हो गयी. इस विद्रोह के कारण ब्रिटेन पर भारी दबाव पड़ा। जिससे ब्रिटेन ने इजराइल को लेकर अपनी नीति परिवर्तित कर ली और 1939 में एक स्वेत पत्र जारी किया जिसमें बाहरी देशों से आने वाले यहूदियों को फिलिस्तीन में घुसने से प्रतिबन्धित कर दिया।

तमाम प्रतिबन्धों के वावजूद यहूदी अन्य देशों से गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन पहुँचना जारी रखा ।

सन 1918 से लेकर 1947 तक फिलिस्तीन क्षेत्र पर ब्रिटेन का ही कब्जा रहा और इस दौरान यहूदियों की आबादी फिलिस्तीन में लगातार बढ़ती रही इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 1922 में यहूदियों की आबादी फिलिस्तीन ने में मात्र 11 प्रतिशत थी जो कि बढ़ते–बढ़ते 1945 में 31 प्रतिशत तक पहुँच गई।

द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945–

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अरब और यहूदियों से युद्ध में सहायता करने को कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों ने ब्रिटेन का बढ़–चढ़कर समर्थन किया, जबकि फिलिस्तीन में रह–रहे इस्लाम को मानने वाले लोगों ने जर्मनी का समर्थन किया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ही जर्मनी में करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट नाजी सरकार हिटलर द्वारा उतार दिया गया था।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र विजयी हुए इस विजय में यहूदियों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् यहूदी पूर्णतया आस्वस्थ थे कि युद्ध में उनके द्वारा की गई मदद के बदले ब्रिटेन उन्हें अपना राष्ट्र बनाकर देगा।

1946–1947 यहूदी विद्रोह –

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात् भी यहूदियों को अपना देश न मिलता देख हिंसा की ओर बढ़ चले और कई उग्रवादी संगठन यहूदियो द्वारा बनाए जाते रहे। इसी विद्रोह के दौरान एक यहूदी संगठन ने फिलिस्तीन में ब्रिटेन के मुख्यालय पर बम धमाके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 91 ब्रिटिश नागरिक मारे गये यहूदियों द्वारा हिंसक विद्रोह के कारण ब्रिटेन ने फिलिस्तीन छोड़ने का मन बना लिया। इसके बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में मौजूद मुस्लिम और यहूदियों से वार्ता करके समाधान निकालने का प्रयास किया परन्तु वह अन्ततः विफल रहा। इसके बाद ब्रिटेन ने फरवरी 1997 को यह मामला नवगठित संयुक्त राष्ट्र संघ को सौप दिया।

सितम्बर 1947 को ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह फिलिस्तीन को 15 मई, 1948 के पहले छोड़ देगा। 29 नवम्बर,

1947 को यूनाइटेड नेशन के अधिनियम संख्या 181 के तहत आम सभा में (जनरल असेम्बली) में निम्न प्रस्ताव रखे गये–

1. एक स्वतंत्र यहूदी राज्य।
2. एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य।
3. यरुशलम का शहर संयुक्त राष्ट्र संघ के नियन्त्रण में रहेगा।

इन प्रस्ताओं के समर्थन में 33 देशों ने मतदान किया, विरोध में 13 देशों ने मतदान किया व 10 देश अनुपस्थित रहे। भारत एक मात्र गैर अरब देश था जिसने इस प्रस्ताओं का विरोध किया।

यहूदियों ने इन प्रस्ताओं का स्वागत किया और अरबों ने इसका विरोध किया। कुछ विशेषज्ञों की माने तो कुछ दिनों में इसको पास करवाने के लिए मोटी रकम और तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया प्रस्ताव के पास होने के अगले ही दिन हिंसा की शुरुआत हो गई।

इजराइल की नींव–

14 मई 1948 को इजराइल देश के रूप में सैकडों सालों के बाद एक यहूदी राज्य के रूप में पुनः अपने अस्तित्व में सामने आया डेविड बेन गुरियन ने इसकी घोषणा अधिकारिक रूप में की। यह देश संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव से बना जिसे अमेरिका तब के सोवियतसंघ (USSR) समेत अन्य देशों ने देश के रूप में तत्काल मान्यता प्रदान कर दी। भारत ने सन 1950 में इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकारा। आज भी विश्व के ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अब तक इजराइल को देश एक देश के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की है उनमें पाकिस्तान समेत अरब के कुछ देशों का नाम प्रमुख है।

1948–1949 का युद्ध–

इजराइल के बनने के अगले ही दिन 4 देशों की सेना जिनमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, और इराक की सेनाएं एशामिल थी। चारों देशों कह सेनाएं इजराइल के बनने के बाद फिलिस्तीन में प्रवेश किया और इसी प्रकार इजराइल और अन्य देशों के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध करीब 1 साल तक चला। फिलिस्तीन को परदे के पीछे से सउदी अरब, यमन, समेत देशों ने समर्थन किया। वहीं इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन, और सौवियत संघ ने समर्थन दिया था। अरब देशों का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन में एक यहूदी देश बनने से रोकना था जबकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और इस अस्तित्व की लड़ाई को इजराइल ने जीता। इस युद्ध में अरब देशों की एक बड़ी हार हुई। इसी युद्ध के दौरान इजराइल ने फिलिस्तीन के 60 प्रतिशत इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया इस युद्ध में जॉडर्न देश की सेना ने वेस्ट बैक और पूर्वी यरुशलम पर अपना कब्जा जमाया। और मिश्र ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमा लिया।

इजराइल 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक सदस्य बना। डेविड बेन गुरियन इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1948 में इजराइल में यहूदियों की संख्या मात्र 7 लाख थी जो 1958 आते–आते 20 लाख तक पहुँच गई। आधिकारिक रूप से एक देश बनने के बाद इजराइल में यहूदी तमाम देशों से पहुॅचने लगे और इसी कारण धीरे–धीरे इजराइल में यहुदी आबादी काफी बढ़ने लगी। इजराइल के शुरुआती वर्षों में गाजा की (तरफ) से इजराइल की ओर लगातार हमले होते रहे जिसका जबाव भी इजराइल समय–समय पर देता रहा।

स्वेज नहर और दूसरा युद्ध (1956)–

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल नसीर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीय करण 1956 में किया इसके जबाव में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने स्वेज नहर पर कब्जा जमाने का प्रयास किया और इस लड़ाई में इजराइल भी बीच में कूद गया और इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायःद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया अन्त में अमेरिका सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध की समाप्ति हुई। सन 1957 में इजराइल ने सिनाई प्रायःदीप को अपने कब्जे से मुक्त कर दिया।

6 दिन का युद्ध 1967–

1960 के दशक में इजराइल के उसके पड़ोसी देशों से सम्बन्ध निरन्तर खराब होते जा रहे थे और इस आग में चिंगारी का काम मिस्र ने किया मिस्र ने मिश्व वे इजराइल को लाल सागर में प्रवेश बन्द करने से रोक दिया किया। कुछ ही दिनों में इजराइल ने मिस्र, जॉडर्न, और सीरिया पर हमले किए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईराक और लेबनॉन भी थे। इस युद्ध में भी इजराइल की निर्णायक जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही इजराइल ने कई देशों के हिस्सों पर अपना कब्जा स्थापित किया हालांकि शान्ति वार्ता के पश्चात् इजराइल ने कई देशों से अपने कब्जाए गए क्षेत्रों को मुक्त कर दिया और अपनी सेनाए भी उन क्षेत्रों से वापस बुला ली।

1973 का युद्ध–

मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। मिस्र और सीरिया को इस बार सोवियत संघ से समर्थन प्राप्त था वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन प्राप्त था। इस युद्ध में मिस्र और सीरिया को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा।

शांति के प्रयास–

शांति का पहला और बड़ा प्रयास 1977–1978 में हुआ उस दौरान अनवर अलसादत जो कि तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति थे। जिन्होंने इजराइल का दौरा किया और इसी के साथ मिस्र पहला अरब देश बना जिसने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। 1978 में कैम्प डेविड नाम की सन्धि इजराइल और मिस्र के बीच हुई। इसमें इजराइल ने सिनाई प्रायःदीप को पुनः मिस्र को सौंप दिया। इस शांति समझौते को झटका तब लगा, जब इजराइल ने यरुशलम को अपनी आधिकारिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव 1980 में परित किया।

1992–1999 में शांति की पहल–

सन 1993 में फिलिस्तीन लेवरेशन आगनाइजेसन (PLO) के साथ इजराइल ने शांति समझौता किया। इस शांति समझौते में इजराइल और PLO ने एक दूसरे को मान्यता प्रदान की और इसी समझौते के तहत PLO को गाजा पट्टी और वेस्ट बँक पर शासन करने के अधिकार को इजराइल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। 1994 में इजराइल ने जार्डन के साथ शान्ति समझौता किया, इस समझौते के तहत जार्डन ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। इन दोनों शान्ति समझौतों में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉविन की मुख्य भूमिका थी और 1995 में रॉबिन की हत्या के साथ ही शांति के प्रयासों को जोरदार झटका लगा।

1996 के शान्ति प्रस्ताव–

इजराइल ने अरब बहुसंख्यक वाले हिब्रॉन शहर से अपनी सेना पीछे खींच ली और साथ ही साथ फिलिस्तीन सरकार को फिलिस्तीन के शासन को लेकर ज्यादा अधिकार

दिए लेकिन यह सब समझौते लम्बे समय तक शांति स्थापित करने में असफल रहे।

1999–2001 तक शान्ति प्रस्ताव–

सन 1999 से 2001 तक शांति स्थापित करने के अनेक प्रयास हुए हलांकि ये प्रस्ताव भी शाति स्थापित करने में नाकाफी साबित हुए इनमें सन् 2000 की कैंम्प डेविड वार्ता प्रमुख है। इस वार्ता के दौरान इजराइल ने अपनी तरफ से यह प्रस्ताव रखा कि फिलिस्तीन को गाजा पट्टी का 100 प्रतिशत हिस्सा (पूरा) और बेस्ट बैंक का 90 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा और यरुशलम को दोनों देशों की साझा राजधानी बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव में अमेरिका ने मध्यस्थता की थी लेकिन अन्तिम समय में यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाया।

विवाद के कारण–

1. हरम अल–शरीफ–

हरम अल–शरीफ को ही टेम्पल माउन्ट भी कहते हैं यह क्षेत्र यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म की आस्था का केन्द्र है। तीनों धर्मों में हरम अल–शरीफ पर अधिकार को लेकर संघर्ष जारी है फिलहाल यह क्षेत्र इस्लाम धर्म के अधिकार क्षेत्र में आता है और बाहरी दीवार पर यहूदी और ईसाई धर्म का अधिकार है।

2. यरुशलम–

यरुशलम इजराइल के एक शहर का नाम है इसी शहर में हरम अल– शरीफ भी स्थित है। यह शहर दुनिया के प्राचीनम शहरों में से एक है और इजराइल फिलिस्तीन के विवाद का मुख्य बिन्दु यरुशलम शहर ही है। यरुशलम शहर में यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के अनेक पवित्र

स्थान मौजूद है। फिलिस्तीन यरुशलम को अपना क्षेत्र मानता है वहीं इजराइल यरुशलम को अपनी आधिकारिक राजधानी बनाने की तैयारी में है। सन 1980 में इजराइल ने कानून बनाकर यरुशलम को अपनी राजधानी घोषित किया था हालांकि विश्व भर के देशों ने इजराइल के इस प्रस्ताव का विरोध किया। इजराइल की यरुशलम को राजधानी बनाने की जिद इजराइल फिलिस्तीन विवाद को और भड़का रही है।

अमेरिका ने ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान यरुशलम में अपना दूतावास भी खोला था जिससे यह संदेश जाता है कि भविष्य में अमेरिका यरुशलम को इजराइल की राजधानी के रुप में अपनी मान्यता प्रदान कर सकता है।

3. फिलिस्तीन के क्षेत्र–

इजराइल फिलिस्तीन बनने के बाद जितने भी युद्ध हुए उनमें इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जे किए। तमाम युद्धों का यह परिणाम हुआ कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा और वहॉ पर अपने लोगों को उन क्षेत्रों पर बसाता रहा। आज के समय में फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में है।

4. इजराइल फिलिस्तीन का सीमा विवाद–

यूनाइटेड नेशन ने सयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमा का निधरिण किया था, सीमा निर्धारिण के बाद हुए युद्धों के कारण फिलहाल दोनों देशों की अधिकारिक सीमा निर्धारित नहीं हुई है।

इजराइल और फिलिस्तीन के सम्बन्ध में भारत की नीति–

सन 1947 से 1992 तक भारत का झुकाव पूरी तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में था भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र

के रूप में, मान्यता 1950 में दे दी थी हलांकि सम्बन्धों में गर्मजोशी नरसिम्हाराव सरकार के दौरान ही आई। जब भारत ने 1992 में तेल अबीब में अपना दूतावास खोला और पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए और भारत की नीति इस समय काल से काफी हद तक तटस्थ हो गयी हालांकि थोड़ा बहुत झुकाव फिर भी फिलिस्तीन की ओर ही रहा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भारत की नीति तटस्थ ही रही लेकिन थोड़ा झुकाव इजराइल की ओर रहा। मन मोहन सिंह सरकार के दौरान तटस्थ नीति के साथ झुकाव फिलिस्तीन की ओर रहा। नरेन्द्र मोदी सरकार के दौरान भारत की नीति काफी हद तक इजराइल की ओर झुकी रही। भारत इजराइल फिलिस्तीन बनने के समय से ही राष्ट्र सिद्धान्त का समर्थन करता रहा है और विस्तार वादी व आतंकीय घटनाओं के विरोध में खड़ा रहा है। हालिया हमास इजराइल सघर्ष में भारत ने आतंकवादी घटनाओं की आलोचना की है साथ ही साथ इस संघर्ष के दौरान निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की है, वहीं फिलिस्तीन की आर्थिक सहायता व अनेक राहत सामग्रियाँ भेजी हैं।

निष्कर्ष–

यह सिर्फ धर्म युद्ध है ये थोडा अलग प्रकार का युद्ध है क्योकि इजराइल का कुल क्षेत्रफल लगभग 22 हजार वर्ग किलोमीटर है और इजराइल को कुल आबादी है। 1 करोड़ है, सोचिए जो हमारा दिल्ली शहर है उससे भी काफी कम इजराइल में लगभग 73.8 प्रतिशत यहूदी, 18 प्रतिशत मुस्लिम और 1.9 प्रतिशत आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। इजराइल के ही नक्से में आप फिलिस्तीन को भी देख सकते हैं जिसमें दो बड़े इलाके आते हैं एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजापट्टी इन दोनों ही इलाकों में लगभग कुल आवादी 50 लाख है

जिसमें 99 प्रतिशत मुस्लिम और 1 प्रतिशत ईसाई है अर्थात कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन में कोई एक भी यहूदी नहीं है, अब हम अंदाजा इसी बात से लगा सकते है कि जिस इजराइल को कट्टर माना जाता है इसके देश में आज भी 18 प्रतिशत मुस्लिम रह रहे हैं? जिस फिलिस्तीन को लोग आज उदार कह रहे हैं वहाँ एक भी यहूदी नहीं रह सकता आप खुद समझ सकते हैं कि धार्मिक कट्टरवाद सबसे ज्यादा कहाँ है। इजराइल में कहावत है कि "इजराइल होना आसान काम नहीं है क्योंकि इजराइल दुनिया के 22 मुस्लिम (अरब) देशों से घिरे हैं और इन 22 मुस्लिम देशों में कुल 45 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं–

1. लेबनान
2. सीरिया
3. साइप्रस
4. इजिप्ट
5. जार्डन
6. ओमान
7. कुवैत
8. तुर्किए
9. ईराक
10. ईरान
11. कतर
12. वहरीन
13. कुवैत

14. U.A.E.

15. सउदी अरब

सारे जो मुस्लिम देश है वे विचार धारा के नाम पर और धर्म के नाम पर यहूदियों को पसन्द नहीं करते इजराइल से बदला लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इजराइल से यहूदी भाग जाए। वस्तुतः ये लड़ाई सिर्फ 74 लाख यहूदी और 45 करोड़ मुस्लिमों के बीच की है। इजराइल भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, उत्तर में इजराइल की सीमा लेवनान से मिलती है, उत्तर पूर्व में सीरीया से इजराइल की सीमा लगती है, उतरी और दक्षिणी पूर्व में इजराइल की सीमा जार्डन से लगती है, दक्षिणी पश्चिमी मे इजराइल की सीमा इजिप्ट (मिस्र) से लगती है इजराइल के पश्चिम में गाजापट्टी का भी इलाका है जहाँ से हमास के 1000 हजार आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की थी और किर इजराइल के हजारों नागरिकों का खून खराबा कर चुके हैं। अतः इजराइल अपने दुश्मनों से 6 तरफ से बुरी तरह घिरा हुआ है। इजराइल की सीमा टिपन देशों से लगती है उनमें कोई भी एक दोस्त देश इजराइल का नहीं है क्योंकि सारे देश मुस्लिम बाहुल्य देश है जिसमें लेवनान में 69 प्रतिशत, सीरिया में 58 प्रतिशत, जार्डन 92 प्रतिशत, इजिप्टा मिस्र में 90 प्रतिशत वेस्ट बैंक में 92 प्रतिशत और गाजा में 99 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। कुल मिलाकर इजराइल बहुत बुरी तरह फॅसा हुआ है और अब इजराइल अर्थात 74 लाख यहुदियों के अस्तित्व की लड़ाई है।

दोनों देशों के विवादों के आधार स्तंभ है धर्म, जमीन, विचारधारा, अस्तित्व और वर्चस्व की जंग। UN के बंटवारे के बाद भी यह विवाद अभी तक सुलझने के बजाय और अधिक

उलझा ही है। दोनों देश एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने को अभी तक तैयार नहीं है जिससे ये समस्या कहीं अधिक पेंचीदा हो जाती है। विवाद का समाधान न होने का एक कारण यह भी है कि दोनों देशों को कई मजबूत देशों का समर्थन प्राप्त है जिस कारण इजरायल और फिलिस्तीन ने युद्ध लड़ना लगातार जारी रखा है। दोनों देशों का समर्थन कर रहे देश इजरायल और फिलिस्तीन को हथियार पैसा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और तमाम विश्व मंचों पर समर्थन कर रहे हैं। इस संघर्ष ने न केवल मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और भू–राजनीति पर भी गहरा असर डाला है। विश्व राजनीति में यह मुद्दा महाशक्तियों और क्षेत्रीय शक्तियों के हितों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देश आमतौर पर इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि अरब देश और कई अन्य विकासशील राष्ट्र फिलिस्तीन के अधिकारों की वकालत करते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन ने कई युद्ध घोषित और अघोषित रूप से लड़े इन युद्धों की सबसे दुखद बात यह रही कि इनमें हजारों की संख्या में मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और युद्धों का कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया हालांकि इन युद्धों में इजरायल को विजय प्राप्त हुई जिससे चलते इजरायल का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता रहा। इन युद्धों में फिलिस्तीनी लोगों की बुरी हार हुई और उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध हमें साफ इशारा करते है कि युद्ध किसी समस्या का स्थाई समाधान कत्तई नहीं हो सकता कैप्टन वी0एच0 मिडिल हार ने कहा है If you want peace then prepare for war और अगर हमें बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाना है तो वो शांति कैप्टन चिः वार्ता के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है दोनों देश और उनके समर्थित देश इसे धर्मयुद्ध का नाम देते कहा वी०ए चूहे पर वास्तव में इनमें

कई तरह के युद्ध अंतर्निहित है। हालिया हमास और इजरायल युद्ध को लेकर कुछ लिहिल होते विशेषज्ञों का मानना है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि हमास ने ने कहा है रूस के उकसावे पर इजरायल पर हमला किया था ताकि अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद को रोके या कम करे और सभी देश इजरायल के पीछे जा कर खड़े हो जाए जिससे रूस को यूक्रेन विवाद में मदद मिले और रूस तेजी से यूक्रेन पर कब्जा करे, दूसरा कुछ लोगों का यह मानना है कि Unders-IMEG corridor को रोकने के लिए भी चीन समेत रूस की चाल के कारण भी हमास ने ऐसा कदम चला खैर जो भी कारण रहा हो अंतिम और सबसे अधिक नुकसान इजरायल और फिलिस्तीन के लोगों का ही हुआ और बड़े बड़े देशों ने मासूम लोगों की लाशों पर अपने हितों की रोटियाँ सेंकी।

इजराइल–फिलिस्तीन विवाद का समाधान आसान नहीं है क्योंकि यह धार्मिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक मुद्दों में गहराई से निहित है। दोनों पक्षों के बीच समझौता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। अंतराष्ट्रीय संबंध के लिहाज से इजरायल और फिलिस्तीन एक अत्यन्त इजराइल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इजरायल चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है जो कि इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं और फिलिस्तीन का पूर्ण रूप से समर्थन करते है इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद इजरायल आज भी पहले से मजबूत स्थिति में बना हुआ है। इजरायल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है जिसमें उसे अमेरिका का पूर्ण सहयोग प्राप्त है जिस कारण इजरायल तमाम इस्लामिक देश जिनमें भारी सऊदी अरब यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, इराक, कतर समेत अन्य देश शामिल है उन पर भारी पड़ रहा है। इस विवाद में धर्म

का शामिल होना इस विवाद को बहुत पेंचीदा बनाता है फिलहाल यहूदी, ईसाई गठबंधन इस विवाद में सबसे मजबूत पक्ष बनकर उभरा है अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इजरायल का पक्ष और अधिक मजबूत होने जा रहा है क्योंकि ट्रंप का इजरायल का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। अभी की स्थिति में देखा जाए तो अमेरिका अकेले दम पर इस विवाद को सुलझाने का दम रखता है क्योंकि अमेरिका है जो इजरायल को समर्थन देता है और इजरायल अमेरिका के सुझाए गए रास्ते पर चलता है वही इस्लामिक देश में भी अमेरिका अधिक प्रभावशाली देश है, वे देश भी अमेरिका की बात और सुझाए गए रास्ते को मानेंगे ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इस मुद्दे को पूर्ण रूप से सुलझा सकते हैं।

हाल ही में अमेरिका की मध्यस्तता के बाद इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है हालिया संघर्ष में 50 हजार से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री की हालिया मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा को अपने अधिकार में लेगा और वहाँ की आबादी को गाजा छोड़ना होगा ट्रंप का यह बयान और उनका यह फैसला इस विवाद को और अधिक उलझने का कुछ काम करेगा जिससे यह अभी का सीजफायर कुछ समय तक शायद न चल सके और एक बार फिर गाजापट्टी में इजरायल और अमेरिका बमबारी शुरू कर दें। जिस हिसाब से ट्रंप का इजरायल को समर्थन है उस हिसाब से इजरायल इस बार और अधिक आक्रामक होकर यह लड़ाई लड़ेगा और दोबारा शांति स्थापित करने में विश्व समुदाय को बहुत कठिनाई होगी। इस विवाद को शांति और सूझबूझ के साथ ही सुलझाया जा सकता है दोनों देशों को एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार कर के शांति की ओर कदम बढ़ाने होंगे।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ</u>–

1. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध **B.4.** फड़िया, 01 जनवरी, 2019 साहित्य भवन पब्लिकेशन।
2. **The Hindu.**
3. **The Economic Times.**
4. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राम सूरत पाण्डेय, 01 जनवरी, 2020
5. **Civil Services Time.**
6. ई–क्रोनिकल।
7. प्रतियोगिता साहित्य।
8. **Narain D. Satra, "Comprcuted relationship: India needs both Israel & Iran".**
9. अनूप कुमार गुप्ता, ''पाक–इजराइल सम्बन्धों का मतलब।''
10. **Times of India.**

India and the Middle East: A Bond Developed by Geography

Dr. Pallavi, Assistant professor, Department of Geography, Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda

India and the middle east the two big size areas on the Asian continent share a unique and unbreakable geographical bond. They share a deep geographical and historical bond shaped by proximity, trade, and cultural exchange. The Arabian Sea connects the Indian subcontinent to the Middle East, with the Persian Gulf and Red Sea serving as vital maritime links. The Indian Ocean has historically facilitated trade routes, notably the ancient Silk Road and spice trade, fostering economic and cultural ties between India and regions like the Arabian Peninsula, Mesopotamia, and Persia.

Geographically, the Middle East lies to India's west, with countries like Iran, Iraq, and Saudi Arabia being key neighbors across the sea. The proximity has enabled centuries of migration, with Indian traders, scholars, and laborers settling in places like Bahrain, Oman, and the UAE, while Arab and Persian influences shaped India's language, architecture, and cuisine. The Himalayas and Hindu Kush mountains, while barriers, also helps in interactions through passes, linking India to Central Asia and the Middle East. Today, this bond is evident in energy trade as India imports much of its oil from the Middle East, diaspora communities as millions of Indians work in Gulf countries, and strategic partnerships. Shared monsoon patterns and coastal ecosystems further tie the regions environmentally. This

geographical bond continues to make India and middle east relationship stronger with each passing day.

India and the Middle East, are divided by distance and languages, are united by something far more fundamental that is by geography. Their closeness on the map has been the foundation of a stronger relationship relations that is characterized by history, trade, cultural symbiosis, and geopolitical interdependence. In today's interconnected world, this bond is more vital than ever and due to their geography it becomes easy to develop strong relationship. India's western coastline lies directly across from the Middle Eastern region, particularly the Arabian Peninsula. The Arabian Sea, once used by ancient travelers and spice traders, continues to serve as a crucial maritime corridor. Proximity has made movement easier of people, goods, and ideas and has forged connections that might not have existed otherwise.

As discussed earlier the Monsoon winds enabled regular travel and trade between Indian ports such as Kochi, Surat, and Mumbai and the Gulf cities like Muscat, Dubai, and Basra. These early commercial exchanges formed the foundation of interdependence.

Historical and Cultural Ties due to geographical bond-

Long before modern states existed, ancient civilizations in Mesopotamia and the Indus Valley traded with one another. Archaeological findings suggest that goods from the Indian subcontinent were present in the markets of ancient Iraq and Iran.

Culturally, Islam became a prominent bridge in this relationship. Muslim traders and scholars from the Arab world reached India's shores as early as the 7th century,

influencing the development of Islamic architecture, language , and cuisine in India.

Similarly, Indian philosophies and goods influenced Middle Eastern societies. The game of chess, originally from India, was popular in Persia and then spread further west.

Economic connection due to Geography –

In the 21st century, economic ties between India and the Middle East are stronger than ever. The Gulf Cooperation Council (GCC) countries—particularly the UAE and Saudi Arabia—are among India's top trading partners. Crude oil and natural gas form the backbone of this trade, as India relies heavily on Middle Eastern energy to power its growing economy.

India exports food, textiles, machinery, and pharmaceuticals to the Gulf. The India-UAE Comprehensive

Economic Partnership Agreement (CEPA) signed in 2022 is a testament to the growing mutual dependence.

The geographical bond help in economical relationship between India and Middle East.

Human Bonds with the help of geography

One of the most visible outcomes of this geographic bond is the Indian diaspora in the Middle East. Over 9 million Indians live and work across the Gulf, particularly in the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, and Qatar. These workers contribute significantly to both economies through remittances to India and by sustaining the infrastructure and services sectors in the Gulf.

The presence of Indian schools, cultural centers, and cuisine has helped nurture a soft power dynamic, where Indians are not just economic contributors but also cultural ambassadors.

Strategic and Political Cooperation-

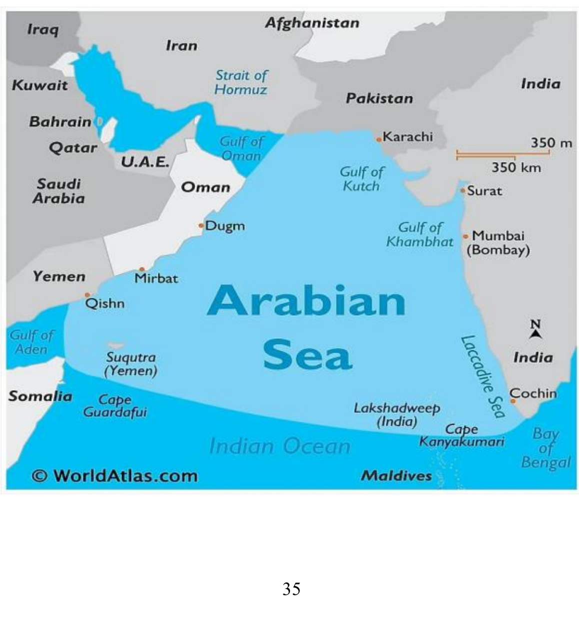

Given the geographic nearness and mutual interests, India and the Middle Eastern nations have cultivated strong political and strategic ties. This includes collaboration on counter-terrorism, maritime security in the Indian Ocean, and defense cooperation.

India's growing strategic footprint in West Asia includes military exercises, defense equipment deals, and intelligence-sharing mechanisms. The Middle East, in turn, looks to India as a stable, democratic partner with a large market and global influence.

Energy and Connectivity Corridors with the help of geography –

The geographic bond is now being translated into ambitious connectivity initiatives. The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), announced in 2023, envisions a modern-day "spice route" linking Indian ports with Gulf countries and onward to Europe through rail and sea. This is set to rival China's Belt and Road Initiative and further solidify the geographic and strategic importance of India-Middle East ties.

Geographical factor is one of the factors which help one nation to develop relationships with other nation. India and middle east relationship built on proximity and trade has evolved into a complex tapestry of economic, cultural, and strategic ties. As the global order shifts and regional powers rise, the connection between India and the Middle East will not only endure but deepen—guided by geography and strengthened by shared goals.

Role of Arabia sea in this geographical bond –

The Arabian Sea forms a natural maritime corridor between the western coast of India and the eastern shores of

the Middle East. This proximity has historically enabled extensive maritime interaction, which has significantly contributed to the development of Indo-Arab relations.

The Arabian Sea is bounded by India to the east, Pakistan to the north, the Arabian Peninsula to the west, and the open Indian Ocean to the south. Its geographical location makes it one of the most important maritime zones in the world. It acts as a gateway for the exchange of goods, people, and ideas between the Indian subcontinent and the Middle East, particularly through the western Indian states of Gujarat, Maharashtra, and Kerala.

Ancient Maritime Trade-

The Arabian Sea was an essential part of the ancient maritime Silk Road. Archaeological sites such as Lothal in the Indus Valley Civilization show evidence of maritime links with Mesopotamian civilizations. These ancient sea routes enabled the exchange of spices, textiles, gems, incense, and other luxury goods between Indian and Arab merchants.

Arab Traders and Monsoon Navigation-

Arab sailors mastered monsoon wind patterns, enabling reliable travel between the Arabian Peninsula and India. These traders established coastal settlements and helped integrate the economies of both regions through sustainable trade practices over centuries.

Arab traders played a crucial role in introducing Islam to coastal India, particularly in Kerala and Gujarat. Many settled in these regions, leading to the emergence of Muslim communities long before the Islamic conquests in northern India. These interactions led to the development of hybrid cultural traditions, including language, architecture,

and cuisine. Several Indian coastal cities show Arab architectural influences and include Arabic vocabulary in their local languages.

The Arabian Sea also enabled Indian Muslims to undertake pilgrimages (Hajj and Umrah) to Saudi Arabia, further strengthening spiritual and cultural bonds. India depends heavily on oil and gas imports from the Middle East, much of which is transported via the Arabian Sea. Major Indian ports such as Mumbai, Kochi, and Mormugao serve as critical entry points for these imports. Similarly, India exports pharmaceuticals, textiles, and food products to Gulf nations.

Ports such as Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) in India and Jebel Ali (Dubai) and Salalah (Oman) in the Middle East facilitate massive cargo traffic and container shipments, serving as logistics hubs for Indo-Arab trade.

The Arabian Sea has historically supported the movement of people. Today, more than 8 million Indians reside in GCC countries. These expatriates work in diverse sectors and send remittances that contribute significantly to the Indian economy.

Maritime routes were once the only means of transport between the regions, and even today, sea routes remain vital for shipping goods and maintaining supply chains.

The Arabian Sea is of major strategic interest to India, which maintains a robust naval presence to secure sea lanes and counter piracy. Joint naval exercises with Gulf nations enhance mutual trust and maritime security.

Chabahar and Gwadar Ports-

India's involvement in developing Chabahar Port (Iran) provides it strategic access to Central Asia and Afghanistan, bypassing Pakistan. Meanwhile, China's investment in Gwadar Port (Pakistan) highlights the region's increasing geopolitical competition.

Maritime Diplomacy-

India and Middle Eastern nations regularly collaborate on maritime safety, regional stability, and counter-terrorism through bilateral and multilateral dialogues. The Arabian Sea provides a practical stage for these engagements.

The Arabian Sea plays a pivotal role in the South Asian monsoon system, which directly affects agriculture and livelihoods in India. It is also home to rich marine biodiversity, supporting the livelihoods of coastal fishing communities in both regions.

There are increasing concerns about climate change, marine pollution, and overfishing, which necessitate cooperative environmental policies between India and Middle Eastern countries.

The Arabian Sea has been, and continues to be, a central axis around which Indo-Middle Eastern relations revolve. From facilitating ancient maritime trade and religious exchanges to supporting modern energy trade, diaspora movements, and naval cooperation, its role has evolved but remained vital.

In an era of globalization, energy dependency, and regional competition, the Arabian Sea's significance as a strategic, economic, and cultural bridge is only growing. As India and Middle Eastern countries seek deeper cooperation

in various fields, the Arabian Sea will continue to be an indispensable medium for this evolving relationship.

How can we use Geographical bond-

India and the Middle East share a strong geographical and to get more benefit from this relationship.

Strengthen Trade and Investment Ties-

Expand and implement FTAs like the India-UAE CEPA to reduce tariffs and encourage cross-border trade.

Move beyond oil and textiles to include tech, pharmaceuticals, green energy, defense, etc. We can diversify our trade relationship with the middle east

We need to encourage sovereign wealth funds (like from UAE or Saudi Arabia) to invest in Indian infrastructure and startups.

Long-term Energy Contracts: Ensure energy security for India with stable pricing agreements will be beneficial for all. Partner in solar and hydrogen energy projects, leveraging India's Solar Mission and Middle East's capital and help the planet in general to fight against global warming.

Improve Connectivity-

To improve the connectivity we have to invest in shipping, port infrastructure, and digital corridors. Chabahar Port (Iran) and the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) are key.

We can Expand direct flight routes and maritime shipping lines for faster trade and tourism.

Ease of Mobility: Streamline visa and work permit processes to encourage business and talent flow. We need to made this process fast so that mobility became fast.

Strategic and Security Cooperation-

Defense and Intelligence sharing with the countries of middle east will help to strengthen the bond with India , also Joint exercises, counter-terrorism, and cybersecurity initiatives will help to make geographical bond stronger.

Collaborate on issues in the Indian Ocean Region and West Asia for stability. That will benefit both regions and help to exploit the geographical bond between India and the middle east.

Reference –

1- **Wikipedia – Geography of India**

2- **Wikipedia – Geography of middle east**

3- **Wikipedia – Arabian sea**

4- **Britannica: Geography of middle east**

5- **https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=12120&lid=7393**

6- **https://www.orfonline.org/research/india-middle-east-europe-economic-corridor-towards-a-new-discourse-in-global-connectivity**

मध्य पूर्व के देशों की सामान्य जानकारी

अनुपमा सिंह,
शोध छात्रा,
रक्षा एवम स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग,
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज,
गोंडा

General Information

मध्य पूर्व में ऐसे देश शामिल हैं–जिसमें मिस्र, ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, और कभी–कभी उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से जैसे लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को भी इसमें शामिल हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या अरब है और इस्लाम का पालन करती है, हालांकि इस क्षेत्र में कुर्द, यहूदी और ईसाई जैसे विविध जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक भी इन देशों में रहते हैं। यह ''एक भू–राजनीतिक क्षेत्र है जिसमें अरब प्रायद्वीप, लेबनान, तुर्की, मिस्र, ईरान और इराक शामिल हैं।''मध्य पूर्व, भूमध्य सागर के दक्षिणी और पूर्वी तटों के आसपास की भूमि, जिसमें कम से कम अरब प्रायद्वीप और, कुछ परिभाषाओं के अनुसार, ईरान, उत्तरी अफ्रीका और कभी–कभी उससे आगे का क्षेत्र शामिल है। इस सामान्य क्षेत्र के मध्य भाग को पहले निकट पूर्व कहा जाता था, यह नाम इसे कुछ पहले आधुनिक पश्चिमी भूगोलवेत्ताओं और इतिहासकारों द्वारा दिया गया था, जो ओरिएंट को तीन क्षेत्रों में विभाजित करते थे। निकट पूर्व

यूरोप के सबसे नजदीकी क्षेत्र को लागू करता है, जो भूमध्य सागर से फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है य मध्य पूर्व, फारस की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व, वे क्षेत्र जो प्रशांत महासागर का सामना करते हैं।

शब्द के उपयोग में परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले शुरू हुआ और उस युद्ध के दौरान इसकी पुष्टि हुई, जब मध्य पूर्व शब्द को मिस्र में ब्रिटिश सैन्य कमांड को दे दिया गया। 20वीं सदी के मध्य तक मध्य पूर्व की एक आम परिभाषा में तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, इसराइल, पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, जॉर्डन, मिस्र, सूडान, लीबिया और अरब के विभिन्न राज्य और क्षेत्र शामिल थे (सऊदी अरब, कुवैत, यमन, ओमान, बहरीन, कतर और ट्रूशियल स्टेट्स या ट्रूशियल ओमान ख्अब संयुक्त अरब अमीरात,)। बाद की घटनाओं ने, ढीले उपयोग में, परिभाषा में शामिल भूमि की संख्या को बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई है। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को के तीन उत्तरी अफ्रीकी देश अरब राज्यों के साथ भावना और विदेश नीति में निकटता से जुड़े हुए हैं। कभी–कभी, ग्रीस को मध्य पूर्व के दायरे में शामिल किया जाता है क्योंकि मध्य पूर्वी (तब निकट पूर्वी) प्रश्न अपने आधुनिक रूप में पहली बार तब स्पष्ट हुआ जब 1821 में यूनानियों ने ओटोमन साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के लिए विद्रोह किया।

1. मिस्र–[Egypt]

मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में फैला हुआ देश है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में स्थित है। जिसका हृदयस्थल, नील नदी घाटी और डेल्टा, प्राचीन मध्य पूर्व की प्रमुख सभ्यताओं का घर था और पूर्व में मेसोपोटामिया की तरह, दुनिया के सबसे शुरुआती शहरी और साक्षर समाजों में से एक का स्थल था। फारोनिक मिस्र लगभग

3,000 वर्षों तक देशी राजवंशों की एक श्रृंखला के माध्यम से फला –फूला, जिसमें विदेशी शासन की संक्षिप्त अवधि भी शामिल थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद, शहरी मिस्र हेलेनिस्टिक दुनिया का एक अभिन्न अंग बन गया। ग्रीक टॉलेमिक राजवंश के तहत, अलेक्जेंड्रिया शहर में एक उन्नत साक्षर समाज फला–फूला, लेकिन जो अब मिस्र है उसे 30 ईसा पूर्व में रोमनों ने जीत लिया था। यह रोमन गणराज्य और साम्राज्य का हिस्सा रहा और फिर रोम के उत्तराधिकारी राज्य, बीजान्टिन साम्राज्य का हिस्सा रहा, प्राचीन मिस्र को उत्तरपूर्वी अफ्रीका के रेगिस्तान में एक मरुद्यान माना जा सकता है, जो नदियों के वार्षिक जलप्लावन पर निर्भर था। नील नदी को अपने समर्थन के लिए कृषि आबादी। देश की प्रमुख धन नील घाटी के उपजाऊ बाढ़ के मैदान से आता था, जहाँ नदी चूना पत्थर की पहाड़ियों के बीच बहती है, और नील डेल्टा, जिसमें यह वर्तमान काहिरा के उत्तर में कई शाखाओं में फैल जाती है। बाढ़ के मैदान और पहाड़ियों के बीच कम रेगिस्तान की एक परिवर्तनशील पट्टी है जो एक निश्चित मात्रा में खेल का समर्थन करती है। नील नदी मिस्र की एकमात्र परिवहन धमनी थी।

चित्र.1

मिस्र की सीमा ये देशों से लगती हैः

पश्चिम में लीबिया, पूर्व में फिलिस्तीन और इजराइल, दक्षिण में सूडान, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी इत्यदि।

2. ईरान–[Iran]

अगर हम ईरान (Iran) देश की बात करें तो ईरान एक इस्लामी गणराज्य और पश्चिमी एशिया का एक देश है (Islamic Country)। यह पश्चिम में इराक और तुर्की से, उत्तर–पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया से, उत्तर में कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से और दक्षिण में ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है।

नोटः– पाकिस्तान और ईरान की सीमा का नाम ''गोल्ड स्मिथ'' है।

''प्राकृतिक गैसों के रिजर्व (भंडार) की दृष्टि से ईरान विश्व का सबसे बड़ा देश है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक(1960) का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

चित्र.2

3. इराक–[IRAQ]

इराक प्राचीन काल में नवाचार का केंद्र था, जिसने प्रारंभिक लिखित भाषाओं, साहित्यिक कृतियों और खगोल विज्ञान, गणित, कानून और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की। स्वदेशी शासन का यह युग 539 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। जब नव–बेबीलोनियन साम्राज्य को साइरस द ग्रेट के तहत अचमेनिद साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया, जिसने खुद को "बेबीलोन का राजा" घोषित किया। बेबीलोन शहर, बेबीलोन की शक्ति का प्राचीन केंद्र, अचमेनिद साम्राज्य की प्रमुख राजधानियों में से एक बन गया। प्राचीन इराक, जिसे मेसोपोटामिया के रूप में जाना जाता है, दुनिया के पहले यहूदी प्रवासी समुदाय का घर है, जो बेबीलोनियन निर्वासन के दौरान उभरा था।

इराक की सीमाएं इन देशों से लगती हैं:

उत्तर में तुर्की, दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत, पूर्व में ईरान, पश्चिम में सीरिया, दक्षिण–पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण–पश्चिम में जॉर्डन इत्यादि।

- इराक, मध्य–पूर्व एशिया में स्थित एक जनतांत्रिक देश है.
- इसकी राजधानी बगदाद है.
- इसकी मुख्य बोलचाल की भाषा अरबी और कुर्दी है.
- इराक की दो प्रमुख नदियां दजला और फरात हैं.
- इराक दुनिया के सबसे ज्यादा तेल पर निर्भर देशों में से एक है.
- इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ था.

• इराक में असीरिया के पतन के बाद विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व रहा है.

• इराक में 2003 से दिसंबर 2011 तक अमेरिका के नेतृत्व में नैटो की सेना की उपस्थिति रही.

• इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्र 1992 में एक स्वायत्त इकाई के रूप में उभरा था.

4. इजराइल–[ISRAEL]

यह मध्य पूर्व के दक्षिणी लेवेंट में स्थित है, और उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूर्व में वेस्ट बैंक और जॉर्डन, दक्षिण–पश्चिम में गाजा पट्टी और मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल के दक्षिणी छोर पर लाल सागर पर एक छोटी तटरेखा भी है, और मृत सागर का एक हिस्सा इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसकी घोषित राजधानी यरुशलम में है, जबकि तेल अवीव देश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र और आर्थिक केंद्र है। इजराइल एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसे यहूदी इजराइल की भूमि के रूप में जानते हैं, जो कनान क्षेत्र और पवित्र भूमि का पर्याय है।

एक महाद्वीपीय चौराहे पर स्थित , इस क्षेत्र ने रोमनों से लेकर ओटोमन्स तक के साम्राज्यों के शासन में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अनुभव किया।

फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश की समाप्ति के बाद, इजराइल ने 14 मई 1948 को स्वतंत्रता की घोषणा की।

भौगोलिक वातावरण–

समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच स्थित होने के कारण, यहाँ चार अलग–अलग फाइटोग्राफिक क्षेत्र हैं। इस कारण से, वनस्पति और जीव–जंतु अत्यंत विविध हैं। इजराइल में पौधों की 2,867 ज्ञात प्रजातियाँ हैं। इनमें से कम से कम 253 प्रजातियाँ पेश की गई और गैर–देशी हैं। 380 इजराइली प्रकृति भंडार हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका 1948 में इजरायल को एक राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था, और 2017 में यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। इजरायल संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान साझेदार है, और इजरायल का संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। अमेरिकी और इजरायली लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता से एकजुट हैं।

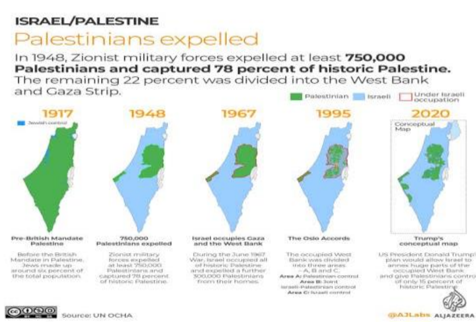

5. सीरिया [SYRIA]

सीरिया, दक्षिण–पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसके क्षेत्र में गोलान हाइट्स का क्षेत्र शामिल है जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। वर्तमान क्षेत्र प्राचीन सीरिया से मेल नहीं खाता है, जो पूर्वी भूमध्यसागरीय तट और उत्तरी अरब के रेगिस्तान के बीच स्थित उपजाऊ भूमि की पट्टी थी। इसकी राजधानी है दमिश्क (दमिश्क), बरदा नदी पर, कसीउन पर्वत (कासियुन) के तल पर एक मरूद्यान में स्थित है।

चित्र.5

जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम एशिया का एक अरब देश है। यह अकाबा खाड़ी के दक्षिण में और सीरियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित है. जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा है। जॉर्डन में शुष्क रेगिस्तान, दरार घाटी, ऊंचे इलाके, और मैदान हैं। जॉर्डन

की अर्थव्यवस्था व्यापार और सेवा–संबंधी गतिविधियों पर निर्भर है। जॉर्डन में विनिर्माण, कृषि, खनन, और निर्माण गतिविधियां भी होती हैं। जॉर्डन में प्राचीन वास्तुकला, पवित्र स्थल, और रेगिस्तान में रोमांच का मजा लिया जा सकता है । जॉर्डन में गहरे समुद्र में गोताखोरी भी की जा सकती है। जॉर्डन में स्वादिष्ट खाना भी मिलता है।

लेबनान पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैयह अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और लंबे इतिहास के लिए जाना जाता है।

सऊदी अरब, मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अरब देश है. यह एक इस्लामिक राजतंत्र है. सऊदी अरब के बारे में जरूरी जानकारी पर यदि ध्यान केंद्रित करें तो, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब में इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना हैं। सऊदी अरब में रेतीली जमीन है और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु है। सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में से एक है।

सऊदी अरब में इस्लाम की राजनैतिक राजधानी है।

तुर्की, यूरेशिया में स्थित एक देश है. यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तुर्की के बारे में जरूरी जानकारी लें तो, तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। तुर्की में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं।तुर्की, यूरोप और एशिया के बीच का 'पुल' है। तुर्की के एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। तुर्की तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। तुर्की, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

तुर्की में माउंट अरारत की दो चोटियां हैं, जिनमें से ग्रेट अरारत 16,945 फुट (5,165 मीटर) ऊंचा है। तुर्की में कृषि, आर्थिक आय का आधा हिस्सा देती है।तुर्की में उद्योगीकरण की ओर बढ़ोतरी हुई है। तुर्की में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में हैं।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बारे में जरूरी जानकारी इस प्रकार है। यूएई, मध्य पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है और सबसे बड़ा शहर दुबई है।

यूएई की स्थापना 02 दिसंबर, 1971 को हुई थी। यूएई की सीमा सऊदी अरब, ओमान, और कतर से लगती है। यूएई में अरबी भाषा बोली जाती है और इस्लाम देश का राष्ट्रीय धर्म है। यूएई में शुष्क रेगिस्तानी जलवायु है। यूएई में सालाना औसतन 140–200 मिमी बारिश होती है। यूएई में कभी–कभी हिंसक धूल के तूफान आते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में शामल हवाएँ कहा जाता है। यूएई की अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व में सबसे विकसित है।तेल भंडार के मामले में यूएई दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। यूएई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है।

यमन गणराज्य अरब प्रायद्वीप के दक्षिण–पश्चिमी से दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अदन की खाड़ी और अरब सागर तथा उत्तर–पूर्व में ओमान से लगती है। यमन के 200 द्वीपों में सबसे बड़ा सोकोत्रा है, जो मुख्य भूमि यमन से लगभग 354 किमी दक्षिण में स्थित है। ऐसे में और कई छोटे–छोटे देश शामिल हैं जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को इत्यादि शामिल हैं।

'मध्य-पूर्व के देशों का भूगोल'

Geography of Middle East Countries

प्रणव (शोध छात्र)

भूगोल विभाग,

दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर

सर्वप्रथम हमें मध्य–पूर्व के देशों व दक्षिण–पश्चिम एशिया और जो उत्तर–पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक बड़ा और विविधताओं से परिपूर्ण भौगोलिक संरचना है उनके विषय में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखो ये उपर्युक्त भौगोलिक संरचना जो है वह उत्तर में काला सागर से लेकर (इस सागर से निम्न देश अपनी सीमा साझा करते हैं, **पश्चिम में बुल्गारिया, रोमनिया, उत्तरपूर्व में रूस और यूक्रेन और दक्षिण में तुर्की के मध्य स्थित है, इसके** पूर्व जॉर्जिया तथा कॉकेशस की पवर्तमालाएं हैं, जो कैस्पियन सागर से अलग करती है।) दक्षिण में अरब सागर तक 3218.688 किलोमीटर (2000 मील) और पश्चिम में भू–मध्य सागर से लेकर (इस सागर से निम्न देश अपनी सीमा साझा करते हैं, **अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोबिना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्त्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेवनेग्रो, मोरस्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की है**) ईरान के पहाँड़ों तक लगभग 1609. 344 किलोमीटर (लगभग 1000 मील) तक फैला हुआ है। ''जब 20वीं सदी का दौर आता है तब ''मध्य–पूर्व'' शब्द का अनावरण हो इस्तेमाल में आया, लेकिन इस शब्द को आज भी

आधिकारिक रूप से परिभाषित नही किया गया है। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र के एक हिस्से के लिए कभी–कभी उपयोग में लाया जाने वाला शब्द ''फर्टाइल क्रिसेंट'' है– ये जो फर्टाइल क्रिसेंट शब्द है, इसकी रचना जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड ने 1914 में उपजाऊ कृषि क्षेत्रों के चाप को संदर्भित किया था। इसी को अपना प्रारम्भिक सम्भ्यताओं का आधार बनाया, जो आज के समय में इराक, सीरिया, लेबनान और इजराइल हैं। प्राचीन अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान आमतौर पर इस क्षेत्र के लिए ''नियर ईस्ट'' शब्द का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक स्वारूप का वर्णन पहाड़ और रेगिस्तान मध्य पूर्व को छह क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से अलग–अलग हैं और जिन्होंने क्षेत्र के अधिकांश इतिहास में सांस्कृतिक परंपराओं के विकास और रख– रखाव को प्रभावित किया है।

इनमें से पहले क्षेत्र में, नील नदी सूडान के खार्तूम (जहाँ इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ मिलती हैं) से सहारा रेगिस्तान के माध्यम से उत्तर की ओर बहती है, मिस्र से होकर भू–मध्य सागर तक जाती है। वार्षिक बाढ़ में जमा पानी, भोजन और उपजाऊ मिट्टी के स्रोत के साथ–साथ परिवहन मार्ग के रूप में यह प्राचीन न्युबियन और मिस्र की सभ्यता के लिए पारिस्थिति आधार था। इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में, विस्तृत जलोढ़ मैदान छह ''झरनों'' से टूटा हुआ है– नील में जो नील नदी है इसके आस–पास के रेगिस्तानों के समृद्ध खनिज संसाधन जैसे कि विशेष रूप से सोना अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण रही है। बात आती है कि ''लेवेंट क्षेत्र'' इस क्षेत्र के अंतर्गत इज़राइल, लेबनान और पश्चिमी सीरिया के आधुनिक देशों के साथ–साथ जॉर्डन और तुर्की के कुछ हिस्से को मिलाकर इस क्षेत्र का धरातल की सम्पूर्ण संरचना लेवेंट

कहलाती है। (**फ्रांसीसी शब्द "उगते हुए" के बाद यहाँ उगते सूरज का जिक्र है।**)

जबकि अधिकांश लोग ये जो मध्य–पूर्व का क्षेत्र है इस क्षेत्र को एक विशाल गर्म रेगिस्तान के रूप में ही देखते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो इस क्षेत्र में पहाड़, उपजाऊ नदी घाटियाँ और यहाँ के तटीय मैदान शामिल हैं। हम यहाँ की भौतिक विशेषताओं के विषय को लेकर यदि हम अध्ययन करें तो इस क्षेत्र की जलवायु, जैव विविधता और मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती है। अगर हम मध्य–पूर्व के प्राकृतिक बनावट की बात करें तो इस क्षेत्र में कई सारी पर्वत श्रंखलाएं हैं, जिनमें ईरान के जाग्रोस पर्वत, तुर्की में ऑरस पर्वत और उत्तरी ईरान में अल्बोरज पर्वत शामिल हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक अवरोधों के रूप में कार्य करते हैं, जो क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न, जल वितरण और जैव विविधता को प्रभावित किए वगैर नही रहते हैं। अच्छा एक बात और है कि वे अपने आप में रणनीतिक महत्व भी रखते हैं। एक बात और ये प्राकृतिक सुरक्षा अवरोध खनिज संसाधन और पशुओं को चारागाह भूमि प्रदान करते हैं।

बेशक, आज भी यह विशाल क्षेत्र रेगिस्तानों रेतों से ढ़के हुए हैं। अरब रेगिस्तान, जिसमें रूब अलखली (खाली क्वार्टर) शामिल हैं, यह एक "अत्यधिक शुष्क" क्षेत्र है, जहाँ हर साल 2 इंच से भी कम वारिश होती है, सीरियाई रेगिस्तान जॉर्डन और सीरिया के अधिकांश भाग को कवर करता है और इसमें चट्टानी या बजरी वाला रेगिस्तान है, जिसमें कभी–कभी वादी या नदी के किनारे होते हैं। ये जो रेगिस्तान है इसमें तेल और गैस भंडारों से समृद्ध हैं, जो उन्हें मध्य पूर्व के देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बनाते हैं। इराक में टिगरिस और यूफ्रेट्स नदियाँ तथा जॉर्डन नदी मध्य पूर्व में प्रमुख नदी

प्रणालियाँ हैं। ये नदी घाटियाँ उपजाऊ कृषि भूमि का समर्थन करती हैं, जिसने मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सम्भ्यताओं के विकास को सक्षम बनाया और बस्तियों के पैटर्न को प्रभावित किया। इन नदी घाटियों में जल संसाधनों पर नियंत्रण पड़ोसी देशों के बीच तनाव और संघर्ष का स्रोत रहा है, जिससे भू–राजनीतिक मुद्दे पैदा हुए हैं।

लाल सागर शिपिंग और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। साथ ही इसमें कोरल रीफ भी हैं। यह मानव निर्मित स्वेज नहर द्वारा भू–मध्य सागर से जुड़ा हुआ है, जो 120 मील लम्बा जलमार्ग है जिसे 1869 में खोला गया था। सऊदी अरब और ईरान के बीच स्थित फारस की खाड़ी तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, जो इसे दुनिया में ऊर्जा संसाधनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनाती है। यह ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में खाली होने से पहले होर्मूज जलडमरुमध्य तक संकरी हो जाती है। भू–मध्य सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर की सीमा पर स्थित इस क्षेत्र के तटीय मैदान समुद्री व्यापार मछली पकड़ने और शहरी विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। बेरुत तेल अवीव और दुबई जैसे शहर तटीय मैदानों पर स्थित है, जिससे वे आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में काम कर सकते हैं। ये तटीय क्षेत्र पर्यावरणीय खतरों जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि प्रदूषण और तटीय कटाव के प्रति संवेदनशील हैं। जिससे स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकीतंत्र पर प्रभाव पड़ा है। जैसे कि इस रूपरेखा से पता चलता है कि भूगोल दुनिया के किसी भी देश की संस्कृतियों का निर्माण और रख–रखाव दोनों में ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बड़े जनसंख्या केंद्रों वाली शुरुआती सम्भयताएं पानी और कृषि भूमि के प्रचुर स्रोतों के पास विकसित हुई न कि धातुओं, अर्ध–कीमती पत्थरों, इमारती पत्थरों या लकड़ी जैसे अन्य मूल्यवान कच्चे माल के

क्षेत्रों में ये जो भूगोल है, न ये क्षेत्रीय संस्कृतियों की विशिष्ट विशेषताओं के लिए भी आधार प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पूर्वी भू–मध्य सागरीय क्षेत्र (जहाँ अंगूर और जैतून आसानी से उगाये जा सकते हैं।) के व्यंजनों में जैतून के तेल और शराब का महत्व या दैनिक जीवन, अनुष्ठान अभ्यास और दक्षिणी अरब की संस्कृतियों में आर्थिक आदान–प्रदान में धूप का व्यापक उपयोग होता है।

अगर हम अपने मनीषियों से इस विषय पर चर्चा करें कि ये जो भूगोल होता है यह किस हद तक संस्कृति और ऐतिहासिक परिवर्तन की दिशा को आकार देता है, कुछ लोग भूगोल को नियति के रूप में देखते हैं। जबकि बहुत से लोग भूगोल द्वारा इतिहास के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने वाले बदलते अवसरों और बाधाओं के अधिक जटिल रूप में देखते हैं।

मध्य–पूर्व क्या है?

मध्य पूर्व की सीमाओं को परिभाषित करने के मानदण्ड भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय और धार्मिक है, जो बताता है कि इसकी सीमाओं और परिभाषाओं के बारे में विभाजित क्यों है? फिर भी यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि इस क्षेत्र में शामिल देश, मिस्र, ईरान, तुर्की, इराक, सऊदी, अरब, यमन, सीरिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, फिलिस्तीन, कुवैत, इजराइल, कतर और बहरीन हैं।

मध्य पूर्व शब्द का प्रयोग अमेरिका और यूरोप में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में किया जाने लगा पहले सुदूर पूर्व शब्द का प्रयोग यूरोप से सर्वाधिक दूर स्थित एशियाई क्षेत्रों (जापान, चीन, कोरिया) और निकट पूर्व का प्रयोग यूरोप के सर्वाधिक निकट स्थित एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए किया जाता था। आज इनमें से कई देशों को

मध्य पूर्व का हिस्सा माना जाता है। जो दर्शाता है कि परिसीमन के जो मानदण्ड हैं वह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हैं।

<u>मध्य पूर्व की विशेषताएँ</u>–

मध्य पूर्व की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1. यह पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण–पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है। इसके मध्य इसकी अवस्थिति है।
2. इसका सीमा निर्धारण के लिए कोई स्थल मानदण्ड नहीं हैं।
3. इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 2.7 वर्ग मील (7 मिलियन किमी) है।
4. इसमे शामिल देशों की जनसंख्या 430 मिलियन से अधिक है।
5. प्रमुख जलवायु शुष्क (गर्म एवं शुष्क) है।
6. वार्षिक वर्षा का स्तर 11.8 इंच (300 मिमी) से अधिक नहीं है।
7. यहां की जो मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन, कृषि, खनिज, पर्यटन हैं।

<u>मध्य पूर्व का भौतिक भूगोल और जलवायु</u>–

ये जो मध्य पूर्व के देश हैं इन देशों के अधिकांश क्षेत्र में गर्म शुष्क जलवायु का प्रभाव है, इसकी विशेषता उच्च तापमान है, जो औसतन 64^0F (18^0 C) से अधिक है और कम वर्षा होती है। जो प्रतिवर्ष 11.8 इंच (300 मिलीमीटर) से अधिक नहीं होती है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की उच्चावचें हैं जिनमें अगर ईरान में देखा जाए तो जाग्रोस पर्वत श्रृंखला जैसे पर्वतीय क्षेत्र, तुर्की की कहें तो अनातोलियन पठार और अरब पठार

जैसे विस्तृत पठार मिस्र में नील घाटी और इराक में टिगरिस और फरात नदियों की घाटियाँ जैसे मैदान और घाटियाँ तथा ये जो इजराइल है और जॉर्डन देश की सीमा पर मृत सागर बेसिन जैसे अवसाद शामिल हैं। ये जो मध्य पूर्व का भाग है इसके अधिकांश क्षेत्र में गर्म रेगिस्तान है। यहां का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान को ''रूब अल खली'' रेगिस्तान कहते हैं। जो सऊदी अरब, यमन, ओमान, और संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अपने विशाल क्षेत्र के बावजूद यह पूरी तरह से निर्जन क्षेत्र है। गर्मियों में इसका तापमान 131^0F (55^0C) से अधिक हो सकता है। वार्षिक वर्षा शायद ही कभी 2 इंच (50 मिलीमीटर) तक पहुंचती है।

यहाँ की भूमिगत भूमि खनिजों और तेलों से समृद्ध है। तेल उत्पादन मध्य पूर्व के अधिकांश देशों में मुख्य गतिविधि है, जिनमें से कुछ, सऊदी अरब, ईरान, ईराक, कुबैत और संयुक्त अरब अमीरात सहित पेट्रोलियम, निर्यातक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) के सदस्य देश हैं। इस क्षेत्र में अन्य खनिज प्राकृति गैस, लोहा, फास्फेट, तांबा, जस्ता और सोना है। अगर हम जीव–जन्तुओं के संदर्भ में कहें तो ऊँट मध्य–पूर्व के विशिष्ट जानवर हैं, क्योंकि पानी को संग्रहीत करने और उच्च तापमान का प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता उन्हें क्षेत्र की चरम स्थितियों के अनुकूल बनाती है। इन ऊँटों को पालतु बनाकर उन्हें परिवहन के साथ में उपयोग किया जाता है। थोड़े अधिक आद्र भूमि क्षेत्रों में कृषि और चराई संभव है, जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियाँ हैं।

संस्कृति और धर्म–

इस मध्य पूर्व को मानव सभ्यता की दुनिया के समस्त सम्भ्यता उद्गम स्थलों में से एक माना जाता है और इस

प्रकार प्राचीन संस्कृतियों के असंख्य जीवित और पुरातात्विक निशान मौजूद हैं, जो कि मानव के इतिहास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं इसके उदाहरण के लिए कहूँ तो मेसोपोटामिया क्षेत्र प्राचीन संस्कृतियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण था जिसने लेखन जैसे अविष्कारों के साथ सभ्यता की नींव रखी, इसी तरह ईरान में मौजूद फारसी सम्भ्यता का एक प्राचीन संस्कृति का साक्ष्य आज भी मजबूती से मौजूद है। जिसमें प्राचीन दुनिया के वर्चस्व के लिए हेलेनिस्टिक ग्रीस के साथ प्रतिस्पर्धा की।

अगर मैं इनके धर्मों पर प्रकाश डालूँ तो यह मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है यह विश्व के तीन प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों का भी घर है।

1. यहूही धर्म।
2. ईसाई धर्म।
3. इस्लाम धर्म आदि।

अगर हम पहले के फिलिस्तीन और आज के इजराइल की बात करें तो आज के इसी इजराइल के यरुशलम शहर में बहुत ही कम दूरी पर इनमें से प्रत्येक धर्म के प्रतिष्ठित स्थल हैं :– उमर की मस्जिद जो इस्लाम के लिए अपना एक पवित्र स्थान है, यहीं पर ईसा मसीह का कब्र जो कि कैथोलिक धर्म के लिए मौलिक है और बेलिंग बॉल, जो यहूदी धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। अगर हम प्रमुख रूप से किसी धर्म का अधिक रूप में बोल–बाला देखें तो वह इस्लाम धर्म है, शिवाय इजराइल राज्य के, जहाँ अधिकांश आबादी यहूदी धर्म के अनुयायी हैं। अरबी लगभग सभी देशों में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, हालांकि फारसी, तुर्की और हिब्रू भी यहाँ वाद बोली जाती है।

<u>इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था</u>–

यहाँ के अगर हम अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो हम पायेगें कि तेल निष्कर्षण ही रोजगार का प्रमुख स्रोतों में से एक है। मध्य–पूर्व मुख्य रूप में खनिज और तेल उत्पादक वाला क्षेत्र है, इसकी भूमि में दुनिया के हाइड्रोकार्बन भण्डारों का लगभग 60% हिस्सा है, विशेष रूप से तेल है, इसी की वजह से कतर, कुबैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे अत्यन्त धनी देशों का उदय हुआ है। इस क्षेत्र में खनन भी महत्वपूर्ण है, कुछ देशों में खनिजों का दोहन और निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा है। फॉस्फेट, लोहा तांबा और सोना सबसे प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। जहाँ पर अत्यधिक आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र हैं वहाँ कृषि ही मात्र एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं कहूं तो मिस्र में ऐसा ही है जहाँ नील नदी की घाटियों में गहन कृषि की जाती है। जो देश की खाद्यान्न व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था के लिए अपनी जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं।

<u>पर्यटन</u>:–

यहाँ की भौगोलिक बनावट रेगिस्तानी होने की वजह से ठंडे प्रदेशों के विदेशी लोगों को आकर्षित करती हैं, जो कि अपने शरीर को गर्मी प्रदान करने के उद्देश्य से रेगिस्तान में खुद को घूमना पसंद करते हैं। इसलिए यह क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य से कुछ मध्य पूर्वी देशों के लिए एक और प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। अगर हम देखें तो सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में जॉर्डन का क्षेत्र शहर, मिस्र के पिरामिड और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दुबई शहर शामिल है।

मध्य पूर्व में राजनीतिः–

यहाँ पर कई देशों में राजतंत्रों का शासन है, जैसे सऊदी अरब में जबकि अन्य संवैधानिक राजतंत्र है, जैसे जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में। इसके अलावा इजराइल और कुबैत जैसे अन्य देशों में लोकतंत्र सरकार का रूप है। अगर हम सही मायने में कहें तो किसी भी राजनीति का जन्म वहाँ के भूगोल के भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक संसाधनों पर अत्याधिक निर्भर करती है, और वहाँ की राजनीति कैसी होगी तय करती है। उपर्युक्त बहस में हमने प्राकृति बनावट को सही से अवलोकन किया जो हमें यह बताती है कि इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जटिल है, जो कई संघर्षों, युद्धों और विदेशी हस्ताक्षेपों का मंच रही है। इसका एक उदाहरण पर अपनी नजर डालें तो इसका तथाकथित उदाहरण इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1- **मध्य–पूर्व का भूगोल–निबंध–ज्योफ एम्बरलिग।**

2- **ENCYCLOPEDA.**

3- **The Hindu**

4- **Master of the Game (Henry Kissinger of the Art of Middle East Diglomacy) MARIIN INDYK.**

5- **Protesting Jordan. (Geographies of Power and Dissent) Jillian Schwedler.**

6- **The Remaking of Republication Turkey-Nicholas L. Danforth.**

7- **Times Of India.**

China and the Middle East

Kirti Kumar Pandey, Assistant professor, Department of Political science, Sant Tulsidas Degree College, Kadipur (Sultanpur)

China is the growing economy and the potential superpower who is fastly spreading its influence across the globe. China playing its card like a pro player in order to establish itself as global super power. In order to achieve its target one of the top Chinese priorities is to secure its energy needs and to achieve this China is growing its influence in the middle eastern region. One of the main reason behind Chinese Belt and road initiative is to secure energy routes. China's historical interactions with Middle Eastern countries date back over a millennium, encompassing trade, diplomacy, and cultural exchanges.

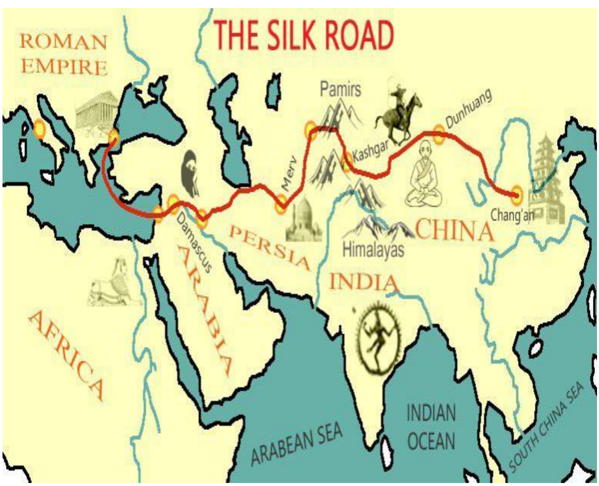

Ancient Trade Routes and Early Contacts- During the Tang Dynasty (618–907 AD), Chinese and Arab traders

established robust commercial ties via the Silk Road and maritime routes. Arab merchants played a critical role in introducing Chinese goods, such as silk and porcelain, to the Middle East and Europe, while bringing Middle Eastern products like spices and textiles to China. Notably, in 1008 AD, Egyptian Admiral Domiyat travelled to China, reopening diplomatic relations between Egypt and China that had lapsed since the Tang Dynasty's decline.

Islamic Influence and Cultural Exchanges- The advent of Islam in the 7th century further strengthened Chinese – Arab relations. Muslim communities emerged in China, particularly in regions like Xi'an, increasing cultural and religious exchanges. Chinese historical records indicate that interactions between the two civilizations date back to pre-Islamic times, with trade routes established during the Han Dynasty (206 BC–220 AD).

20th Century Diplomatic Relations- In the 1930s, the Republic of China under the Kuomintang

established diplomatic relations with Egypt and Saudi Arabia. Chinese Muslims were sent to study at Al-Azhar University in Egypt, and Chinese Muslim pilgrims performed the Hajj in Mecca. During the Second Sino – Japanese War, Chinese Muslims were dispatched to Middle Eastern countries to garner support against Japanese aggression. For instance, in 1939, Isa Yusuf Alptekin and Ma Fuliang were sent to Egypt, Turkey, and Syria to seek support for China.

Post-1949 Relations with the People's Republic of China – After the establishment of the People's Republic of China in 1949, relations with Middle Eastern countries evolved:

1956: Egypt, under President Gamal Abdel Nasser, recognized the People's Republic of China, marking a significant shift in diplomatic relations.

1993: The Arab League opened its first office in China, strengthening institutional ties.

2004: The China–Arab States Cooperation Forum (CASCF) was established to enhance cooperation in various fields, including politics, trade, and culture.

These historical interactions have laid a solid foundation for contemporary relations between China and Middle Eastern countries, characterized by ongoing economic partnerships, cultural exchanges, and diplomatic engagements.

China and US diplomatic competition in the Middle east-

The geopolitical landscape of the Middle East has evolved into a complex arena where both the United States and China exert significant influence, leading to a form of

strategic competition reminiscent of a modern-day Cold War.

Historically, the U.S. has maintained a dominant presence in the Middle East, as US thinks ahead of time that's evident as US has still the superpower of the world

US plan: Military Engagements Post-9/11, the U.S. initiated the "war on terror," leading to prolonged military campaigns in Afghanistan and Iraq. These interventions aimed at nation-building and countering terrorism have shaped regional dynamics. US deployed weapons and soldiers across the middle east countries.

Diplomatic Initiatives: The U.S. has played a central role in mediating peace processes, notably between Israel and Palestine, and has been instrumental in forming coalitions to address regional conflicts.

Economic Sanctions: To curb nuclear proliferation and counter state-sponsored terrorism, the U.S. has imposed sanctions on nations like Iran, aiming to limit their regional influence.

China's plan –

In recent years, China has strategically increased its footprint in the Middle East through:

Economic Investments: China's Belt and Road Initiative (BRI) has led to substantial infrastructure investments across the region, enhancing trade connectivity and economic ties.

Diplomatic Mediation: China has positioned itself as a neutral mediator. A notable example is the 2024 Beijing Declaration, where China facilitated a unity agreement between Palestinian factions, showcasing its growing

diplomatic clout. China involved in deal between Saudi Arabia and the Iran that deal literally shocked the whole world.

Energy Partnerships: As a major consumer of energy, China has secured long-term oil and gas agreements with Middle Eastern countries, ensuring its energy security while bolstering regional economies.

Contemporary Dynamics:

The interplay between U.S. and Chinese strategies in the Middle East has led to:

Strategic Rivalry: Both nations vie for influence, with the U.S. emphasizing military alliances and China leveraging economic partnerships. This competition affects regional alignments and policy decisions.

Regional Perceptions: Middle Eastern countries navigate this rivalry by balancing relations with both powers, seeking to maximize benefits while avoiding over-reliance on either.

Global Implications: The U.S.-China competition in the Middle East reflects broader global power shifts, influencing international trade, security frameworks, and diplomatic relations.

While the U.S. continues its traditional role in Middle Eastern affairs, China's emerging strategies have introduced a new dimension to the region's geopolitical landscape, leading to a nuanced and multifaceted rivalry.

China – India Competition in middle east-

One of the eye catching competition of 21st century is China and India. India and China are increasingly competing for influence in the Middle East, each employing

distinct strategies that reflect their broader geopolitical ambitions and economic interests.

Economic Connectivity and Infrastructure – China has made significant inroads through its Belt and Road Initiative (BRI), investing heavily in regional infrastructure such as ports, railways, and energy projects. These investments not only secure access to energy resources but also deepen China's economic and political ties with key Middle Eastern countries. In response, India has launched initiatives like the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), which aims to provide an alternative connectivity route that leverages historical ties and the large Indian diaspora in the Gulf. This corridor is designed to counterbalance China's expansive BRI by offering Middle Eastern states another avenue for trade and investment.

Energy Security and Trade- Both nations rely heavily on the Middle East for energy imports, making the region a critical arena for securing oil and gas supplies. China's robust economic engagement has helped it lock in long-term energy agreements, while India is actively working to diversify its supply routes and strengthen ties with Gulf states. This competition is not only about accessing energy resources but also about influencing the region's broader trade networks and supply chains.

Diplomatic and Strategic Engagement – China's approach in the Middle East is characterized by pragmatic economic investments and a focus on shaping a multipolar regional order that challenges U.S. dominance. India, on the other hand, has traditionally pursued a non-aligned, culturally rooted diplomacy. However, faced with China's assertive posture, New Delhi is increasingly aligning with like-minded partners—including deepening its strategic and

defense ties with the United States—to bolster its regional influence. For India, the goal is to provide Middle Eastern countries with a credible alternative to Chinese investment, emphasizing transparency and long-term economic benefits.

Challenges and Opportunities – While China's investments often overshadow India's due to their scale and speed, India's strengths lie in its historical connections and soft power. Many Middle Eastern nations are keen to diversify their partnerships and are cautious about over-reliance on any single external power. This gives India an opportunity to position itself as a trusted partner. Yet, India faces challenges in matching the massive financial and infrastructural commitments that China can muster, meaning that its influence in the region is growing but remains more modest compared to Beijing's.

The competition between India and China in the Middle East is a multifaceted contest involving infrastructure development, energy security, and diplomatic outreach. Each country's approach reflects its broader strategic imperatives, with China emphasizing large-scale investments and India banking on historical ties and alternative connectivity projects to carve out its own sphere of influence.

Future Chinese Middle east strategy –

China's future strategies in the Middle East will likely focus on economic expansion, energy security, and diplomatic influence, while avoiding direct military entanglements.

Future China's approach: Economic Expansion & Infrastructure Development - Belt and Road Initiative (BRI): China will continue investing in infrastructure projects like

ports, railways, and energy pipelines to strengthen trade routes across the region.

Digital Silk Road: Expanding Chinese tech companies' presence in 5G, AI, and smart city projects.

Energy Security & Diversification:

Oil & Gas Imports: The Middle East remains China's top energy supplier, particularly Saudi Arabia, the UAE, and Iran. China will aim to secure long-term energy deals.

Green Energy Investments: Expanding solar and nuclear energy projects in the region to align with global energy transition trends.

Diplomatic & Political Influence-

Balancing Relations: China will maintain ties with Iran, Saudi Arabia, Israel, and the Gulf states while avoiding taking sides in regional conflicts.

Mediation Role: Following its 2023 mediation of Saudi-Iran rapprochement, China may seek more diplomatic roles in regional peace processes.

Non-Interference Policy: Unlike the U.S., China avoids military interventions and promotes economic partnerships.

Military & Security Cooperation Arms Sales & Defense Ties - Expanding arms exports and military technology cooperation with regional players like Saudi Arabia and Egypt.

Naval Presence- Increasing patrols in the Red Sea and the Arabian Gulf to protect trade routes.

Trade & Yuan Internationalization-

Petro-Yuan & De-Dollarization: China is pushing for oil trade settlements in yuan (CNY) instead of the U.S. dollar to reduce dependence on Western financial systems.

Expanding Free Trade Agreements: Strengthening trade deals with the Gulf Cooperation Council (GCC) and individual states.

Geopolitical Competition: The U.S., India, and the EU may counter China's influence in the region.

Regional Instability: Conflicts in Gaza, Yemen, or tensions with Iran could disrupt Chinese investments.

Over-Reliance on Energy Imports: A shift in global energy markets could impact China's long-term plans. China's future Middle East strategy will focus on economic leverage, energy security, and cautious diplomacy, aiming to shape the region's future while avoiding the mistakes of Western powers.

Conclusion

China's relationship with the Middle East has grown significantly in recent years, driven by economic interests, energy security, and strategic partnerships. The Belt and Road Initiative (BRI) has deepened Beijing's economic footprint in the region, while its balanced diplomatic approach has allowed it to maintain good relations with key players, including Saudi Arabia, Iran, and the UAE. Unlike the U.S., China has largely avoided military entanglements, instead focusing on trade, infrastructure, and mediation efforts, such as its role in the Iran-Saudi Arabia rapprochement.

India, meanwhile, is also increasing its engagement with the Middle East, leveraging historical ties, energy needs, and its large diaspora. Through initiatives like the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), New Delhi is positioning itself as an alternative economic partner to China. Additionally, India's strong relations with both Israel and the Gulf nations reflect its pragmatic and multipolar foreign policy.

The United States, traditionally the dominant external power in the Middle East, is recalibrating its role. While security and military alliances remain strong, Washington is facing growing challenges from China's economic influence and regional actors seeking greater strategic autonomy. The U.S. still plays a crucial role in maintaining stability, but its influence is no longer unchallenged. Going forward, the Middle East will continue to be a geopolitical arena where China, India, and the U.S. compete and collaborate, shaping the region's economic and security landscape. The balance of power will depend on how these actors navigate their interests while addressing regional conflicts, energy transitions, and infrastructure development.

The crux of China's relationship with Middle Eastern countries centers on a pragmatic, economically driven partnership that is underpinned by three main pillars:

Energy Security and Trade:

China is one of the world's largest crude oil importers, and the Middle East remains a critical source of oil and gas. This energy dependence drives extensive trade relationships, with Middle Eastern states supplying a significant portion of China's energy needs, while China, in turn, serves as a major market for regional oil exports.

Economic Investment and Infrastructure:

Through initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI) and the China–Arab States Cooperation Forum (CASCF), Beijing has massively invested in regional infrastructure, technology, and industrial projects. These investments not only boost economic development in the region but also deepen long-term economic ties, offering mutual benefits beyond the traditional oil-for-goods model.

Non-Interventionist Diplomacy and Strategic Balancing:

China's foreign policy in the region is characterized by its commitment to non-interference and respect for sovereignty. By maintaining a low-key, neutral stance on internal conflicts, Beijing positions itself as a reliable partner—especially attractive to states seeking alternatives to traditional Western (particularly U.S.) involvement. This approach allows China to expand its influence and act as a counterbalance in a region where geopolitical rivalries are intense.

These elements combine to form a relationship that is less about ideological alignment and more about pragmatic economic interests and strategic stability. Beijing's model emphasizes mutually beneficial economic engagement while avoiding entanglement in the region's often volatile political disputes, thereby securing its energy needs and expanding its global influence.

Reference –

1- https://www.csis.org/analysis/china-and-middle-east

2- https://www.brookings.edu/articles/forecasting-chinas-strategy-in-the-middle-east-over-the-next-four-years/

3- https://www.foreignaffairs.com/united-states/multialigned-middle-east-china-influence?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_middle_east_tfd&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8q--BhDiARIsAP9tKI1rmfMvPMzl_PxM8-CZS5-JhjHuN5_Gpcg9o23wulYtCLwg02zgvHQaAslzEALw_wcB

4- https://www.researchgate.net/publication/370221347_The_US-China_Rivalry_in_the_Middle_East_A_Critical_Analysis

5- https://www.kcl.ac.uk/events/the-india-china-rivalry-and-the-israel-palestine-conflict

6- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23477970241285200

7- **https://gjia.georgetown.edu/2025/01/18/the-colonial-strategy-and-india-china-conflict-past-present-and-future/**

' ईरान और मध्य पूर्व '

* Iran & The Middle East *

स्वाती सिंह

(शोध छात्रा)

रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव किसान

पी0जी0कॉलेज बभनान, गोण्डा

मान्यता है ईरान को लेकर जिसमें पहले पुरापाषाण युग कालीन लोग रहते थे। क्योंकि लगभग 5000 ईसा पूर्व से खेती आरम्भ हो गई थी। मेसोपोटामिया की सम्भयता के पहले यहाँ से मानव बस्तियों के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईरानी लोग लगभग 2000 ईसा पूर्व के आस–पास उत्तर तथा पूर्व की दिशा से आये। इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ एक मिश्रित संस्कृति की आधारशिला रखी जिससे ईरान को उसकी पहचान मिली। ये जो आज का ईरान है, यह ईरान इसी संस्कृति पर विकसित हुआ है। ये माया पर जो लोग थे ये ईरानी भाषा बोलते थे और धीरे–धीरे इन्होंने यहाँ खेती करना शुरू कर दिया। अगर हम आर्यों के विषय को लेकर यदि बात करें तो आर्यों की कई शाखाएँ ईरान (कई देशों तथा क्षेत्रों) में आई। जैसे इनमें से कुछ भिदि, कुछ पार्थियन, कुछ फारसी, कुछ सोगदी तो कुछ अन्य नामों से जाने गए थे। मिदि तथा फारसियों का जिक्र असीरियाई स्रोतों में अगर देखें 836 ईसा पूर्व के आस–पास मिलता है। लगभग यही समय ज़रथुस्त

(ज़रदोरत या ज़ोरोएस्टर के नाम से भी प्रसिद्ध) का काल माना जाता है। हालांकि कई लोगों तथा ईंरानी लोक कथाओं के अनुसार ज़रदोस्त बस एक मिथक था। एक बार की बात जब असीरियाई के शाह ने लगभग 720 ईसा पूर्व के आस–पास इजराइल पर आधिपत्य जमा लिया था। इसी दौर में कई यहूँदियों को वहाँ से हटकर मीदि प्रदेशों में लाकर बसाया गया। इसी कारण, जो यहूदी में रहे उन पर जरदोस्त के धर्म का बहुत असर पड़ा और इसके बाद यहूदी धर्म में काफी परिवर्तन आया।

मध्य पूर्व में ईरान की पैठ:–

अगर हम मध्य–पूर्व में ईरान की पैठ की बात करें तो 1979 के दौर में ईरानी–इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान उसी कट्टरपंथी विचारधारा को लागू करने के लिए आतंकवादी प्रॉक्सी की स्थापना करता है, वित्त पोषण और हथियार देकर दुनिया भर में अपनी विचारधारा का प्रसार करने का काम कर रहा है। ईरान और उसके प्रॉक्सी की विचारधारा का आधार इजराइल राज्य पर अतिक्रमण और विनाश है। मध्य–पूर्व में ईरान के कई सारे आतंकवादी संगठन है। जिनमें शामिल है : लेबनॉन में हिजबुल्लाह, गाजापट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद सीरिया और ईराक में शिया मिलिशिया तथा यमन में हौथी आदि।

ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कुद्रस फोर्स, जो ईरान के बाहरी इलाकों से ऑपरेशन और विदेशों में ईरान के प्रॉक्सी को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार हैं। जनवरी 2020 तक कुद्रस फोर्स का नेतृत्व मेजर जनरल ''कासिम सुलेमानी कर रहे थे, लेकिन जब वे अमेरिकी सैन्य अभियान (संक्रिया) में मारे गये, तो सुलेमानी की जगह **''डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी''** ने सम्भाल ली।

<u>लेबनॉन में हिजबुल्लाह</u>:–

ये जो हिजबुल्ला है यह एक शिया आतंकवादी संगठन है जिससे भार (जन्म) 1982 के दौरन लेबनॉन में जब लेबनॉनी गृह युद्ध के दौरान इस्लामी गणतंत्र ईरान द्वारा स्थापित एक मिलिशिया के रूप में उभरा। अगर देखें तो ये जो हिजबुल्लाह

है। यह एक ईरानी प्रतिनिधि है, जो कि लेबनॉन और दुनिया भर में अपनी चरमपंथी विचारधारा को फैलाने और उसे आगे बढ़ाने में मद्द करता है। ईरान हिजबुल्लाह को हर साल 700 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि प्रदान करता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि उन्हें बुलीज IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) कुद्र फोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित करता है जो पूरे मध्य–पूर्व में ईरानी समर्थित प्रॉक्सी का समर्थन और संवर्धन करता है। 1992 से हिजबुल्लाह का नेतृत्व **''हसन नसरल्लाह''** कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो ईरान हाल ही के समय में हिजबुल्लाह को ''सटीक निर्देशित मिसाइल तकनीकी'' से लैस करने का प्रयास कर रहा है। ताकि हिबुल्लाह इजराइली नागरिकों और रणनीतिक लक्ष्यों पर लक्षित हमलें शुरु कर सकें।

इस्लामिक जगत में जिहद और गाजा में हमासः–

हमास एक फिलिस्तीनी **''सुन्नी''** आतंकवादी संगठन है अगर इसकी स्थापना को लेकर बात करें तो यह 1987 में गाजा में हुआ था। यह मिस्र की पार्टी **''मुस्लिम ब्रदर हुड''** की एक शाखा है। इसी की शाखा के रूप में की गई थी। जो 2007 से हमास ने गाजा को नियंत्रित किया। भले ही हमास एक सुन्नी संगठन है, लेकिन गाजा में हमास का स्थान और इजराइल से इसकी निकटता इसे ईरान के लिए एक आदर्श सहयोगी और प्रॉक्सी बनाती है।

ईरान इस आतंकवादी संगठन को सलाना लगभग 80 मिलियन डॉलर देता है। अगर हम गाजा की जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करें तो पाते हैं कि गाजा पट्टी पर नागरिक आबादी पर हमास की जिम्मेदारी के बावजूद ईरान द्वारा प्रदान किया गया अधिकांश धन फिलिस्तीनी नागरिकों की मद्द करने के बजाय, इजराइल के खिलाफ आतंकी हमलों और अभियानों

को वित्त पोषित करने में जाता है। मौट्रिक सहायता के अलावा भी ईरान हमास को हथियार और गोला–बारूद, रॉकेट, एंटी टैंक, एयरक्राफ्ट मिसाइल और मोर्टार की आपूर्ति करता है।

इस्लाम जिहाद:–

इस्लामिक जिहाद (II) गाजा में स्थित एक आतंकवादी संगठन है जिसका ईरान के साथ सर्वाधिक पुराना और सबसे करीबी संबंध है। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह इस्लामिक जिहाद इस्लामी क्रांति से सर्वाधिक प्रेरित हुई थी। 1980 का दौर जब ईरान के साथ इस्लामिक जिहाद का संबंध काफी मजबूत था। अब समूह का नेतृत्व मिस्र से लेबनॉन चला गया है। जहाँ हिजबुल्लाह पहले से ही स्थित था। वहाँ इस्लामिक जिहाद ने IRGC और हिजबुल्लाह के साथ साझेदारी की है जिसने इसे प्रशिक्षण और हथियार प्रदान किए। आज, ईरान II (इस्लामिक जिहाद) को हथियार और लगभग 70 मिलियन डॉलर (S) सालाना की फडिंग देता रहता है। ये जो इस्लामिक जिहाद है, ये इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों और अभियानों के माध्यम से इजराइली नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है।

सीरिया में ईरान का रोल:–

अगर हम सीरिया में ईरान के किरदार की बात करें चाहे वह हिजबुल्लाह हो, हमास या फिर इस्लामिक जिहाद के विपरीत, सीरिया पर ईरान की कमान किसी आतंकवादी प्रॉक्सी के उपयोग से बंधी नहीं है, बल्कि ईरान ने सीरिया में खुद को सीधे तौर पर स्थापित कर लिया है, जहाँ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉर्ड कॉर्प्स कुद्रस फोर्स और ईरानी शासन

सीरिया की राजनीतिक और सैन्य कार्यवाईयों पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।

ईरान और सीरिया के मध्य संबंध ईरानी क्रांति के बाद के शुरुआती वर्षों से ही है। ईरान–इराक युद्ध (1980–88) के दौरान ईरान का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने वाला एक मात्र अरब देश, असद शासन ने ईरानी शासन के साथ अपना घनिष्ठ वैचारिक संबंध बनाए हुए हैं। जब वर्ष 2000 में बशर–अल–असद को अपने पिता से सीरिया से राष्ट्रपति का पद विरासत में मिला जो उस समय ईरान और सीरिया के मध्य संबंधों में और घनिष्ठता हुई। 2011 से ईरान ने सीरिया में अस्थिरता का पूर्ण लाभ उठाया और सीरिया पर अपना पैर फैला लिया। अब बचा था कि जब सीरिया में संघर्ष की शुरुआत होती है तो इसी संघर्ष के दौरान, असद शासन क्षेत्र पर अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए ईरानी शासन पर अधिक से अधिक निर्भर होता है।

आधुनिक ईरान और इजराइल के मध्य संबंध:–

ये जो ईरान और इजराइल है इनके मध्य संबंधों को चार प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

1. 1947–1953 दुविधापूर्णकाल।
2. 1953–1979 पहलवी राजवंश/मैत्रीपूर्ण काल।
3. 1979–1990 ईरानी क्रांति/बिगड़ता हुआ काल।
4. 1992–To Till New खाड़ी युद्ध/खुली दुश्मनी/बड़ा संघर्ष।

1947 में ईरान उन 13 देशों में शामिल था, जिन्होंने फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खिलाफ मतदान किया था। दो साल बाद ईरान ने

भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। ईरान, तुर्की के बाद इजराइल को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बाहुल्य देश था। जब 1953 में तख्ता पलट के बाद जिसने पश्चिमी समर्थक नेता मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान के शाह के रूप में फिर से स्थापित किया। दोनों देशों के मध्य संबंधों में काफी सुधार हुआ। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद, ईरान ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध तोड़ दिए और इसकी लोकतांत्रिक सरकार एक राज्य के रूप में इजराइल की वैधता को मान्यता नहीं देती है। ठंडी शांति से खुली दुश्मनी की ओर मोड़ 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। सोबियत संघ के पतन और खाड़ी युद्ध में इराक की हार के तुरन्त बाद 1990 के दशक की शुरुआत में संघर्ष बढ़ गया क्योंकि पिन्रान राबिन की सरकार ने ईरान पर अधिक आक्रामक रूख अपनाया।

द्विपक्षीय तनाव को बढ़ाने में योगदान देने वाले अन्य कारकों में ईरान द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास, ईरान द्वारा हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हमास और हपैथी आंदोलन जैसे इस्लामी समूहों को वित्त पोषण, 1992 में ब्यूनस आमर्स में इजरायली दूतावास पर हमलें और 1994 में AMIA का बमबारी जैसे आतंकवादी हमलों में ईरान की भागीदारी शामिल है। तकरीबन 1985 से ईरान और इजराइल एक चल रहे छठा संघर्ष में लगे हुए हैं। अगर सच में कहा जाए तो इसने मध्य–पूर्व की भू–राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसमें ईरानी और इजराइली संगठनों के मध्य प्रत्यक्ष सैन्य टकराव शामिल है। जैसे कि 2006 में जब लेबनॉन युद्ध में शामिल था। संघर्ष का स्वरूप विभिन्न तरीकों से हुआ है। जिसमें सीरिया–यमन में संघर्षों में विरोधी गुटों को समर्थन

देना भी शामिल है। ईरान में सीरियाई सरकार को समर्थन प्रदान किया है। जबकि इजराइल ने विद्रोहियों से लड़ने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन प्रदान किया है। संघर्ष में एक–दूसरे के बुनियादी ढ़ाँचे पर साइबर हमले और तोड़–फोड़ भी शामिल हैं। जिसमें परमाणु सुविधाओं और तेल टैंकरों पर हमलें शामिल हैं। 2024 में इजराइल–हमास युद्ध से उपजे क्षेत्रीय तनावों के बीच दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रत्यक्ष संघर्ष का दौर बढ़ गया, जिसमें दोनों एक– दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। साथ ही इजराइल ईरान और सीरिया में लक्ष्यों की हत्या कर रहा है।

ईरान के पक्ष में कारकः–

ईरान का लक्ष्य जो है एक महान क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खुद को सम्मानित करना चाहता है। ये सच है कि जब तक यह एक मात्र वैश्विक महाशक्ति का महान दुश्मन बना रहेगा, यह क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कभी भी सम्मानित नहीं हो सकता। यह संभव नहीं होगा। तथ्य यह है कि उक्त महाशक्ति इसे मध्य–पूर्व में अपनी नीति के लिए एक दीर्घकालिक समस्या के रूप में देखती है। हालांकि इराक, खाड़ी देशों, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से घिरे होने के बावजूद ये जो ईरान है, अपनी पूरी ताकत से खेलता है।

एक तरफ इराक और शिया का सवाल है? इराक में अमेरिका की अनिश्चित नीति से उत्पन्न होने वाले अपरिहार्य विरोधाभाषों में से एक शिया खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है, वास्तव में यह ठीक वही इराकी शिया समूह है जिनके ईरान के साथ सबसे करीबी ऐतिहासिक देश में सरकार में रखा है। यहां की इस्लामिक दावा पार्टी जिससे इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल– मलिकी संबंधित है और सुप्रीम इस्लामिक इराकी

काउंसिल (SIIC) जिसका नेतृतव अब्दुल अजीज करते हैं फिर भी यह इराकी शिया खिलाड़ी है, जो तेहरान से सबसे स्वतंत्र है। और जिस पर इसका कम प्रभाव है। मुक्तदा– अल–सदर जो इराक में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।

मध्य–पूर्व में ईरान का प्रभावः–

ईरान का मध्य–पूर्व में जो प्रभाव है वह उनकी अन्य नीतियाँ चिंता का विषय नहीं बनती जितना कि परमाणु कार्यक्रम, लेकिन फिर भी ईरानी विदेश नीति के बारे में चिंता केवल इसके परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व में हिंसक समूहों के साथ उसकी छठा ताकतों और गठबंधनों को लेकर भी है, जिनमें से कई ब्रिटेन द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किए गए है। जब 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से जब शाह को उखाड़ फेंका गया और अयातुल्लाह खुमैनी देश में वापस आ गए, ईरानी शासन ने पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की है। ऐसा करने के लिए ईरान ने 1980 के दशक में लेबनॉन में हिजबुल्लाह से शुरू करके सम्बद्ध मिलिशिया समूहों और अन्य गैर राज्य अभिनेताओं के नेटवर्क के साथ पारंम्परिक सैन्य बलों का मुकाबला किया है। इस्लामिक रिबोल्यूशनरी गार्ड कॉपर्स (IRGC) कुद्रस बल इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहा है।

लेबनॉन (1980 के दशक से) ईराक (2003) और यमन (2014) में अस्थिरता और कमजोर राज्यों ने ईरान को लेबनॉनी हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया और यमन के हुती के साथ गठबंधन करने का मौका दिया। ईरान सीरिया और उसके राष्ट्रपति असद का पुराना सहयोगी है।

ईरान की विदेश नीति का पूर्वानुमान:—

2015 के परमाणु समझौते को फिर से स्थापित करने के लिए वार्ता 2022 में रुकी हुई है, जबकि वे कथित तौर पर अपने अंतिम चरण में थें। यूक्रेन में रूस के लिए ईरान के समर्थन की पृष्ठभूमि 2022 के महसा अमिनी (मार्गदर्शन गरती, जिसे रायत, रूप से नैतिकता पुलिस के रूप में जाना जाता है।) (इसने इस्लामी ड्रेस नहीं पहनी थीं। इसलिए पुलिस हिरासत में मौत हो गई) विरोध प्रदर्शनों पर इसकी प्रतिक्रिया की आलोचना और अक्टूबर 2023 से क्षेत्रीय वृद्धि, नई वार्ता के लिए चुनौतियाँ पेश करती हैं।

ईरान के साथ 2015 में समझौते के कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे ईरान पर—

संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध कुछ मिसाइलें और ड्रोनों के निर्यात और आयात पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध अब समाप्त हो गये हैं, लेकिन अभी भी यूके, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने इन प्रतिबंधों को जारी रखा है।

ईरान का 2024 में ब्रिक्स :—

अर्थ—व्यवस्थाओं के समूह (चीन सहित और यूएई और मिस्र के साथ) में शामिल होना, इसकी **''पूर्व की ओर देखों नीति''** के हिस्से के रूप में अपने वैश्विक अलगाव का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध उस सीमा तक ईरान व्यापार कर सकता है। ईरान के नये राष्ट्रपति प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1. **The Hindu.**
2. **Wikipidiy**

3. Drishti 198

4. Team Cas Arabe e Institute du estudies Arabs y del Mondo Musalman 9IEAM) Maclrol and Cordoba: - Geam Martin Maunoz Dirctoo General.

5. Indian Express.

6. Dan in the Middle East Irasnatcoal Encounters and Social Histoy L.B. TAURIS.

IMEC-India Middle East-Europe Economic Corridor

गुलाब चन्द्र

सहायक आचार्य

राजनीति शास्त्र विभाग

जवाहर लाल नेहरु स्मारक पी0जी0 कालेज,

महराजगंज, (उ0प्र0)।

भारत–मध्य पूर्व–यरोप आर्थिक गलियारा (IMEE EC) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक निर्बाध परिवहन नेटवर्क बनाना है। यह गलियारा जो है विशेष रूप से भारत के रणनीतिक हितों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सन्दर्भ में अत्यधिक भू–राजनीतिक और आर्थिक महत्व रखता है। ये जो परियोजना है, यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी का हिस्सा है। यह एक प्रकार का महत्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रीय गलियारा है, जिसमें भारत– मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की घोषणा के एक वर्ष के बाद परियोजना में प्रगति के साथ–साथ कुछ बाधाएँ भी देखी गई हैं। अगर हम इसकी स्थापना को लेकर बात करें तो हम पायेंगे कि जब भारत की राजधानी नई दिल्ली में G-20 (Group-20) का शिखर सम्मेलन 2023 में होता है तो उसी दौर के अर्थात G-20 के सम्मेलन के वातावरण में भारत, यूरोपीय संघ (27 देश), फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी, अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अमेरिका के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित

एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से हुआ था। अगर हम इस गलियारे की गुजरने की अवस्थिति को आलोक में ले तो पायेंगे कि यह गलियारा **भारत देश के मुम्बई से लेकर, संयुक्त अरब अमीरात के <u>जबल अली</u> (Jabal Ali) तक तथा जबल अली से लेकर इसी संयुक्त अरब अमीरात के अल–ग़ुवाइफ़त तक तथा सऊदी अरब के हराद से लेकर इसी सऊदी अरब के रियाद ओके इसी सऊदी अरब के अल–हदीथा तक तथा इजराइल देश के हाइफा तक तथा यही गलियारा ग्रीस के पिरेयस तक जाता है।** अर्थात अगर मैं कहूं कि ये गलियारा जो है तीन महाद्वीपों में अपना विस्तार करता है। पहला एशिया के भारत से लेकर यूरोप के ग्रीस (एथेंस) तक यह गलियारा फैला हुआ है।

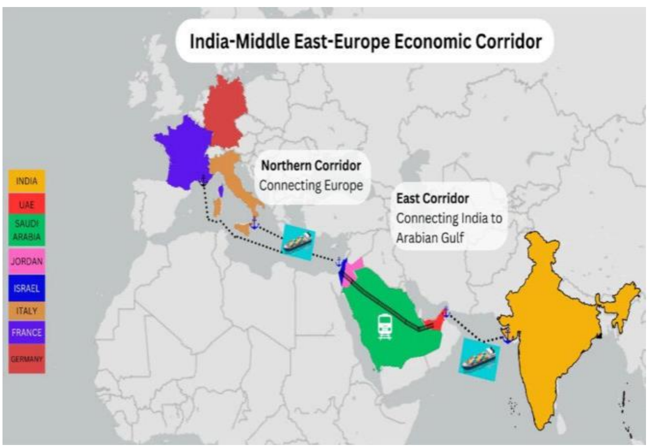

यह जो परियोजना है इस परियोजना को रेल और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से यूरोप और एशिया के मध्य परिवहन आदि संचार लिंक को मजबूत करने के लिए किया गया था और इसे यानि ये जो चीन का एक बेल्ट एण्ड रोड एनिशियेटिब पहल है उसी चीनी परियोजना के खिलाफ/जबाव में देखा जा रहा है। समझौता ज्ञापन दस्तावेज

ने केवल एक गलियारे के संभावित भूगोल को दर्शाया है और यह खोज नहर से गुजरने वाले वर्तमान व्यापार मार्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। IMEC गलियारा एक प्रस्तावित बुनियादी ढ़ाँचा नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले क्षेत्रों के साथ मध्य आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह परियोजना भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक फैला हुआ है जिसमें महत्वपूर्ण पारगमन और संपर्क मार्ग शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाना सीमा–पार निवेश को बढ़ावा देना और माल और ऊर्जा के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है।

1–भारत–मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य–

ये जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का उद्देश्य है। यह सुगम व्यापार मार्ग बनाने के लिए भारत मध्य–पूर्व और यूरोप के बीच वस्तुओं का अधिक से अधिक आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत के मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है–

- **आर्थिक एकीकरण**–भागीदार क्षेत्रों के मध्य घनिष्ठ आर्थिक संबंध और सहयोग को सक्षम बनाना।
- **अवसंरचना विकास**–ये जो अवसरंचना विकास है ये व्यापार की विस्तारित भाषा को आधार प्रदान करने और उसे बनाए रखने के लिए आधुनिक परिवहन संरचना का विकास करना है।

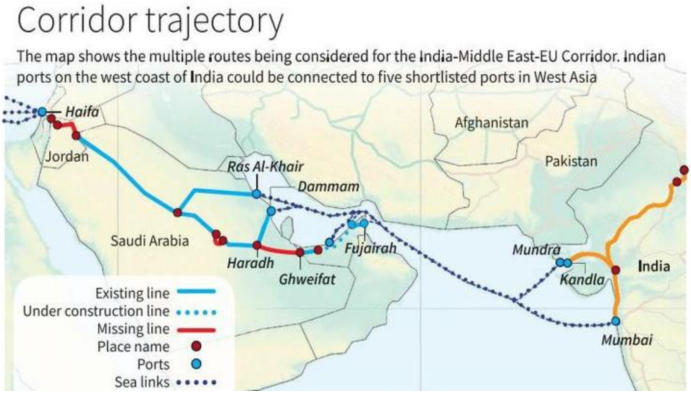

- **<u>रणनीतिक गतिशीलता</u>**–

यदि हम रणनीतिक गतिशीलता की बात करें तो ऊर्जा संसाधनों विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बेहतर रणनीतिक गतिशीतला की सुविधा प्रदान करना।

<u>रोजगार सृजन</u>–

विस्तारित व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजना के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना।

<u>भू–राजनीतिक स्थिरता</u>– ये जो भू–राजनीतिक स्थिरता है यह क्षेत्रों के मध्य भू–राजनीतिक साझेदारी और आर्थिक निर्भरता को बढ़ाना।

<u>भारत–मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के प्रमुख घटक</u>–

भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे के दो अलग–अलग गलियारों में विविध परिवहन अवसरंचना शामिल होगी जिसमें शामिल है–वे दो गलियारा निम्न है–

1. पूर्वी गलियारा।

2. उत्तरी गलियारा।

1–<u>पूर्वी गलियारा</u>–

यह भारत और अरब की खाड़ी के मध्य का गलियारा है जो कि मुम्बई से जुबल–अली, जुबल–अली से अल–गुवाइफत, अल–गुवाइफत से हराद तक हराद से रियाद तथा रियाद से अल–हदीथा तक, पूर्वी गलियारे की संरचना को सफल बनाता है। जिसके अंतर्गत रेल मार्ग, जहाज से रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल हैं।

2–<u>उत्तरी गलियारा</u>–

यह गलियारा खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है, जो कि इजराइल के हाइफा से होकर पूर्वी यूरोप के एक देश ग्रीस (एथेन्स) के पिरेयस को जोड़ती है जिसके अंतर्गत **रेल, जहाज से रेल संपर्क और सड़क नेटवर्क सहित समान परिवहन अवसरंचना है।**

भारत–मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के अंतर्गत शामिल बंदरगाहों की बात की जाये तो यह गलियारा, भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बुधा महत्वपूर्ण बंदरगाहों को जोड़ेगा। ये बंदरगाह गलियारा के भीतर प्राथमिक जोड़ के रूप में अपना कार्य करते हैं और क्षेत्रीय बाजारों तक ट्रांसंशिपमेंट गेटवे पहुँच प्रदान करते हैं इस प्रक्रिया में शामिल प्रमुख बंदरगाह हैं। जैसे भारत के बंदरगाहों की बात करें तो यहाँ हम पायेंगे कि मुद्रा बंदरगाह (गुजरात), कांडला बंदरगाह भी गुजरात का ही है, जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह नवी मुम्बई में अवस्थिति किया गया है। अगर हम मध्य पूर्व के बंदरगाहों की बात करें तो पायेंगे कि फुजैराह पोर्ट, यह इसकी अवस्थिति संयुक्त अरब अमीरात में है और जेबेल अली पोर्ट भी। अबूधाबी

बंदरगाह भी संयुक्त अरब अमीरात में ही हैं। दम्मन बंदरगाह यह बंदरगाह सऊदी अरब में है और इस अल खैतू बंदरगाह भी सऊदी अरब में ही है। इजराइल का जो सबसे दक्षिणी बिन्दु है वहाँ एक बंदरगाह है जिसका नाम हाइफा बंदरगाह हैं जो यूरोप में ग्रीस के पिरेयस बंदरगाह को जोड़ता है। मेसिना बंदरगाह यह दक्षिणी इटली और मार्सिल पोर्ट जो कि फ्रांस से अपनी IMEC की सीमा को स्पर्श करता है।

इन बंदरगाह के अलावा, इस गलियारे में एक रेल मार्ग भी होगा जो संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह को इजराइल के हाइफो बंदरगाह से जोड़ेगा तथा सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेष रूप से क्रमशः गुवाइफत और इराद से होकर गुजरेगा।

भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का महत्व–

भारत–मध्य पूर्व यूरोप का भू–राजनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत काफी है।

भू–राजनीतिक निहितार्थ–

- चीन के बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा चीन के बेल्ट एण्ड रोड एनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करता है। जिसके विकासशील देशों पर प्रभाव डालने तथा उन्हें ऋण जाल में फंसाने के साधन के रूप में देखा जा सकता है।

- **अरब प्रायद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करना**– ये जो भारत है इसके साथ अरब प्रायद्वीप के मध्य स्थायी सम्पर्क के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ अपने राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत

करने के लिए भारत के प्रयासों ने और मजबूती प्रदान की है।

मध्य पूर्व में भारत अमेरिका सहयोग–

भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इस धारणा को खारिज करता है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन मध्य पूर्व में नहीं। यह भारत अमेरिका इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संयुक्त आर्थिक पहल किए जाने की संभावना को दर्शाता है।

अफ्रीका के साथ सहभागिता–

यदि भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा सफल रहा तो अफ्रीका में भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के मध्य आगे के सहयोग के लिए मिसाल कायम कर सकता है। जबकि भारत पहले से ही अफ्रीका महाद्वीप के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बना रहा है। इसलिए संभावानाएं सहभागिता की बढ़ जाती है।

यूरोप का एकीकरणः–

यह क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में यूरोप को महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक बनाता है, जिससे भारत और अरब प्रायद्वीप के मध्य यूरोप के साथ एकीकरण बढ़ता है।

आर्थिक निहितार्थः–

1. **ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन तक पहुंच**ः–

भारत–मध्य पूर्व–यूरोप और आर्थिक गलियारा अन्य देशों से सुरक्षित ऊर्जा और संसाधन आपूर्ति की गारंटी देता है जिससे IMEC के सदस्य देशों में ऊर्जा संसाधन की आपूर्ति करेगा, जिससे कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को एक नई ताकत मिलेगी।

2. **विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाना**:–

इस गलियारे का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्दिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक विकास को साकार करने के लिए किया जा सकता है।

रोजगार सृजन–

इस रोजगार सृजन की बात की जाए तो बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी जिसके लिए कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होगी जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार बढ़ावा मिलेगा।

प्रेरित औद्योगिक विकास–

माल के बाधा मुक्त परिवहन के लिए अर्न्तक्षेत्रीय संपर्क और कुशल परिवहन नेटवर्क औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो इन गलियारों से जुड़े हैं।

बेहतर व्यापार की संभावनाएँ–

यह जो भारत–मध्यपूर्व–यूरोप है का आर्थिक गलियारा है– इसके पारगमन समय को काफी हद तक कम कर सकता है जिससे स्वेज नहर के माध्यम से समुद्री मार्ग की तुलना में यूरोप के साथ व्यापार लगभग 40 प्रतिशत तेज हो जायेगा। जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।

भाग लेने वाले देशों द्वारा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को सकारात्मक रूप से देखा जाता है जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने कनेक्टिविटी बढ़ाने और यूरोपीय संघ (27) और चीन के मध्य व्यापार और आर्थिक संबंधों को संभावित रूप से संतुलित करने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए अगर

देखा जाए तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा को चीन के लिए चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने और अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये तो IMEC है यह अपने व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण और एशिया व यूरोप में अपने भू–राजनीतिक प्रभाव को अधिकतम करने की इच्छा के अनुरूप है।

वर्तमान सितम्बर 2024 में इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में एक अपने संभाषण संबोधन के दौरान इस आर्थिक **''गलियारे को मध्य पूर्व के लिए''** **''आशीर्वाद''** कहा था। और ईरान और उसके सहयोगियों को **''अभिशाप''** के रूप में संदर्भित किया।

भारत के लिए महत्व–

- यह परियोजना भारत और खाड़ी संबंधों को सुदृढ़ बनायेगा।
- गौरतलब व्यापार की वृद्धि।
- संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार टोकरी का विविधीकरण।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है व्यापार में वृद्धि होगी।
- **तीव्र संपर्क**–भारत से यूरोपीय मुख्य भूमि तक माल स्वेज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में 40 प्रतिशत तेजी से पहुंचने तथा लागत में 30 प्रतिशत कमी आने की उम्मीद है।

- **<u>भू–राजनीतिक आकांक्षाएं</u>**– भारत के दो सबसे बड़े व्यापार ब्लॉको, यूरोपीय संघ (EU) और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) को जोड़कर IMEC भारत की तेजी से विकास करने और वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में यह कदम है।

<u>निष्कर्ष</u>–

भारत–मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक व्यापार गलियारा है जिसका उद्देश्य वर्तमान भू–राजनीतिक स्थितियों में व्यापार और संपर्क में सुधार करना है। अच्छा इन गलियारों के विकास में भारत की सर्वाधिक व महत्वपूर्ण भूमिका है जो भारत इसका निर्वहन भी करता है। यह व्यापार संवर्धन के साथ–साथ तनाव को कम करने में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। अच्छा इस गलियारे का अगर हम केन्द्रित होकर अध्ययन करें तो हम इसकी कमियों व चुनौतियों का भी पता लगा पायेंगे जो हर किसी परियोजना की प्रकृति में ही कमियाँ व चुनौतियों अर्न्तनिहित होती है। इस IMEC में भी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में परिवहन के विभिन्न साधनों के प्रबंधन में भाग लेने वाले देशों के मध्य व्यापक समन्वय शामिल है। अपनी क्षमता के बावजूद भारत–मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के सामने प्रमुख चुनौतियों है जैसे–वर्तमान मार्गों में संभावित व्यवधान यदि किसी प्रकार से उनके आर्थिक हितों में परिवर्तन किया जाता है तो वर्तमान में विद्यमान मार्ग तथा संबंधित देशों के हित इसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे–रेल संपर्क तथा उनका निर्माण : रेलवे संपर्क विशेषकर मध्य पूर्व में इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं पर्यावरणीय प्रभाव यह सुनिश्चित करना कि बुनियादी ढ़ाँचे का विकास हरित और टिकाऊ बना रहे।

<u>संदर्भ ग्रंथ सूची</u>–

1. **The Hindu.**
2. **Vision IAS.**
3. **Test Book.**
4. **Drishti IAS**
5. **Wikipedia.**
6. **Indian Express**
7. **PW.Only IAS.**

'अरब स्प्रिंग'

Arab Spring

डॉ0 अमित कुमार शुक्ला

असिस्टेंट प्रोफेसर

रक्षा एवं स्तातेजिक अध्ययन विभाग

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोंडा (उ0प्र0)।

किसी भी देश में क्रान्ति की बात की जाए तो वह उस देश के असंतुष्ट जनता की भावना के मस्तिष्क में उपजी बदलाव से है। वह परिवर्तन की भावना महज किसी भी वस्तु, विचार अथवा व्यापक रूप से देश–दुनिया में बदलाव की भूमिका में खड़ी दिखाई देती है, वह हिंसक भी हो सकती है अथवा आहिंसक भी। ऐसे ही कुछ अरब स्प्रिंग में भी दिखाई देती है। बात आती है कि ये जो अरब स्प्रिंग है इसका वास्ताविक अर्थ क्या है? इसे हम अरब बसंत कहते है। इस अरब बसंत का आशय विरोधों का बंसत या फिर विद्रोहों का बसंत। अरब दुनिया में, अरब स्प्रिंग शब्द का प्रयोग, सरकार विरोधी प्रदर्शन, विद्रोहों और सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इस अरब स्प्रिंग को अरबी में ''अल–रबी अल–अरबी'' कहते हैं । अरब स्प्रिंग की शुरुआत सर्व प्रथम अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में हुई। जो 2010 के दशक के प्रारम्भ में अरब जगत के अधिकांश हिस्सों में फैल गयी। अगर हम अरब स्प्रिंग शब्द के अति सूक्ष्म अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें तो इनमें से अधिकांश विद्रोह 2011 के बसंत ऋतु (Spring Season) में हुए थे, इसलिए इस क्रांति का

नामकरण बसंत अर्थात अरब बसंत या अरब के कृत ने सर्वाधिक प्रसिद्ध जौस्मिन क्रांति के लिए उत्प्रेरक का काम किया। इसके कारण ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में लोग सड़कों पर विरोध प्रर्दशन करना शुरू कर दिया और यह पूरे देश में फैल गया। अब यहाँ के प्रधान शासक 20 साल तक ट्यूनिस पर शासन करने के बाद राष्ट्रपति 'जीन अल अबिदीन बेन अली'' को सऊदी अरब भागने पर मजबूर कर दिया। ट्यूनीशिया की इन घटनाओं के बाद दूसरे देशों की जनता ने इसी देश से प्रेरणा लेकर आंन्दोलन करना शुरू कर दिया। बात अक्टूबर 2011 की है जब ट्यूनीशिया में हुए पहले संसदीय लोकतांत्रिक चुनाओं से प्रेरित होकर अन्य, पड़ोसी देशों की जनता ने भी अपने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिये । होते करते ये क्रान्ति पूरे अरब जगत के लगभग पाँच मुख्य देशों मे अग्नि की ज्वाला की तरह फैल गई। वे देश निम्न है–

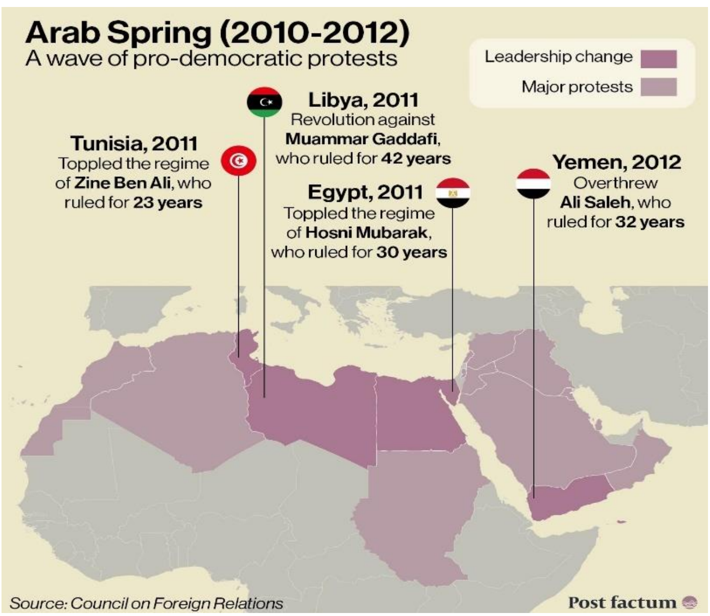

1. लीबिया (ब्रिंपोली)
2. मिस्त्र (काहिरा)
3. यमन (साना)
4. सीरिया (दमस्क)
5. बहरीन (मनामा)

इन पाँचों देशों के शासकों को सत्ता से पदच्युत करने के लिए लीबिया की जनता ने शासक 'मुअम्मर गद्दाफी' (2011), मिस्र की जनता ने 'होस्नी मुबारक' (2011), यमन की जनता ने 'अली अब्दुल्लाह सालेह' (2012) इसी क्रम में सीरिया व बहरीन की जनता ने अपने निरंकुश शासकों को सत्ता से पदच्युत करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। इन विद्रोह में दंगे गृहयुद्ध या उग्रवाद सहित सामाजिक हिंसा शामिल थी। अरब जगत में प्रदर्शनकारियों का प्रमुख नारा था–''अश–शाब मुरीद इस्कात अन–नियाम'' यह अरबी शब्द है जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ–''लोग शासन को गिराना चाहते हैं।''

अरब स्प्रिंग का उभरना–

17 दिसम्बर, 2010 का एक ऐसा वक्त जब ट्यूनीशियाई स्ट्रीट के एक बेंडर ''तारेक अल–तैयब मोहम्मद बौअजीजी'' ने खुद को आग लगा ली यह एक ऐसा कृत्य जो ट्यूनीशियाई क्रान्ति और निरंकुश शासन के खिलाफ व्यापक अरब स्प्रिंग के लिए बुझे हुए चुने में पानी मिलाने का कार्य किया। इस 26 वर्ष के व्यक्ति ने ट्यूनीशियाई क्रांति को अलग दिशा प्रदान की।

ट्यूनीशियाई क्रांन्ति के कारण –

ट्यूनीशिया में असंतुष्ट जनता का प्रमुख कारण–

- अधिनायकवाद का बढ़ जाना।
- पूर्णतया राजशाही का शासन होना।
- मुद्रा स्फीति का बढ़ना।
- चोर तंत्र को बढ़ावा।
- राजनीतिक भ्रष्टाचार का व्यापक रूप ले लेना।
- गरीबी का चरम सीमा तक पहुंचना।
- संप्रदायवाद।
- मोहम्मद बौअजीजी का आत्म दाह करना।
- बोरोजगारी का बढ़ना।
- जन सांख्यिकीय कारक।
- 2000 का ऊर्जा संकट आदि।

ट्यूनीशियाई क्रांति के लक्ष्य –

- प्रजातंत्र का खात्मा और लोकतंत्र को लाना।
- यहाँ की जनता जनार्दन आर्थिक स्वतंत्रता की मॉग।
- यहाँ की जनता रोजगार चाहती थी।
- जनता को स्वतंत्र चुनाव का लक्ष्य।
- देश के शासन व्यवस्था में सुधार।
- शासन सत्ता में परिवर्तन का लक्ष्य आदि।

आन्दोलन के तरीके–

- सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरीके।
- सह युद्ध का सहारा लेना।
- नागरिक प्रतिरोध का शामिल होना।
- प्रदर्शन कारियों का प्रदर्शन होना।
- नागरिकों का विद्रोह शामिल होना।
- इन्टरनेट की सक्रियता का सहारा।
- मीडिया का सही रूप से सहारा लेना।
- विरोधियों द्वारा विरोधी शिविर का बनाना।
- क्रांति, देंगे का सहारा।
- हड़ताल कार्यवाही।
- मौन विरोध।
- आत्म बलिदान आदि के तरीके को अपनाना।

ये कारण लक्ष्य और तरीके अन्य कई देशों में अपना विस्तार व्यापक रूप में किया–

अन्य देश में क्रान्ति की लहर–

अरब स्प्रिंग आंदोलन का असर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भी महसूस किया गया क्योंकि इस क्षेत्र के कई देश में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए।

अल्जीरिया, जॉर्डन, मोरक्को और ओमान ने अपने देशों में विरोध प्रदर्शन में शासकी न हो इसके दूर फैलाव को रोकने के लिए वहाँ के जो अलोकप्रिय आला अफ्सर हुआ करते थे।

उनकी बर्खास्तगी से लेकर संवैधानिक बदलावों तक कई तरह की रियायतें देना उनमें डर की लहर शुरू हो गई क्योंकि कहीं हमारे भी देश में उपर्युक्त देशों की भाँति क्रांति की लहर दौड़ जाए। इन्हीं से सीख लेकर सऊदी जैसे देशों में अपने कर लाभार्थी वहाँ की बना दिया।

बात 6 अगस्त, 2022 की है जब ट्यूनीशिया में एक नये संविधान व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के बाद ट्यूनीशिया में लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद देश में पुनः राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया। राष्ट्रपति कैस सैयद का एक–कावती शासन संस्थागत हो जायेगा। इस सरकार ने 2021 में निर्वाचित की गई संसद को निलंबित कर दिया था और इसने अपने आपको सर्वाधिक, शक्तियाँ प्रदान कर लीं। अब वहाँ पर यानि ट्यूनीशिया में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की चितां बढ़ गई कि अभी जो 2011 में अरब स्प्रिंग (जैस्मिन) क्रान्ति हुए थी और देश को नया संविधान मिला था ट्यूनीशिया को जो भी लोकतांत्रिक उपलब्धियाँ हासिल हुई थी उन्हें मिटा देगा और देश को फिर से सत्तावादी अभिशापी पतन की ओर धकेल देगा।

ट्यूनीशिया

ट्यूनीशिया के संविधान ने एक निश्चित संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली 2014 में आयी जिसमें राष्ट्रपति और संसद दोनों का मतदाताओं द्वारा संधि चुनाव किया जाता था। सिर्फ राष्ट्रपति को विदेशी मामलों में और सैन्य के केवल देख–रेख करनी थी जबकि शासन के दिन हाति– पिन के मसले व मामलों के प्रभारी सांसदों के बहुमत के समर्थन से निर्वाचित प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस ट्यूनीशिया में 2011 से 2021 के मध्य नौ सरकारों का आवागमन हुआ। इस देश की पहले

से ही अर्थव्यवस्था नाजुक हुआ करती थी। दुरदैव से इसी बीच COVID-19 संकट के आ जाने से इसकी अर्थव्यवस्था की हालत और बदतर हो गई।

इस देश के संविधान में जब परिवर्तन हुआ तो अशांति को रोकने के लिए, श्री सईद ने एन्नदा समर्थित प्रधानमंत्री 'हिन्चेम मेचिन्य' को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया। अब क्या था? कि देश संवैधानिक संकट में पड़ गया । अब हुआ क्या? कि 2019 के संविधान के तहत ऐसे संकटों का निपटारा के संवैधानिक न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायालय का गठन किया ही नहीं गया था। अब क्या था? कि राष्ट्रपति को देश पर शासन करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उन्होंने देश में आपात काल की घोषणा कर दी। तो प्रदर्शन कारियों का भड़कना स्वाभाविक हो गया।

यमन में प्रदर्शन–

यमन में जहाँ पहला विरोध प्रदर्शन जनवरी माह के 2011 के अन्त में हुआ, जहाँ के राष्ट्रपति ''अली अब्दुल्ला सालेह'' का जो समर्थन का आधार था । वह तब क्षतिग्रस्त हो गया जब देश के कई शक्तिशाली आदिवासी और सैन्य नेताओं ने लोक तंत्र समर्थक प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन कारियों के रोग मिलकर उनसे पद (सत्ता) छोड़ने की मांग की। लेकिन फिर भी ये प्रदर्शनकारी सालेह को सत्ता से हटाने विफल रहे और यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन कारियों की ऐसी हालत आ पहुँची, जिसमे वफादार और विपक्षी लड़ाके आपस में भिड़ गये और गृहयुद्ध जन्म ले लेता है, जो वर्तमान में भी शुरु रहता है।

बहरीन में प्रदर्शन–

फरवरी 2011 के मध्य में, बहरीन में, बहरीन के मानवाधिकार कार्यकत्ताओं और बहरीन के हाशिए पर पड़े शिया बहु संख्यकों के नेतृत्व में। बहरीन के सुरक्षा बलों द्वारा विरोध प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबा दिया गया। जिसमे खाड़ी सहयोग परिषद सुरक्षा बल (सऊदी अरब के लगभग 1000 सैनिकों और संयुक्त अरब अमीरात के 500 पुलिस अधिकारियों से बना) की सहायता भी शामिल थी।

लीबिया में प्रदर्शन–

लीबिया में शामन के खिलाफ प्रदर्शन फरवरी 2011 के मध्य में मुअम्मर अल–गद्दाफी के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा दिया जब मार्च में विद्रोह को बढ़ावा दिया । जब मार्च के महीने में ही विद्रोही सेनाएँ हार के कगार पर पहुंच गईं थी। तो NATO की सेनाओं ने उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि, NATO के हस्तक्षेप ने अन्ततः सैन्य संतुलन को विद्रोही बलों के पक्ष में बदल दिया, गद्दाफी राजधानी त्रिपोली में कई महीने तक सत्ता पर काबिज रहने में सफल रहा। विद्रोही बलों के द्वारा त्रिपोली में सत्ता से बाहर करते करते हुए मोहम्मद गद्दाफी को अक्टूबर 2011 में सिर्ते में मारा गया। जब बिद्रोही बलों ने शहर पर कब्जा लिया। विद्रोही ताकतों द्वारा स्थापित और अन्तस्तर पर मान्यता प्राप्त ''ट्रांजिशनल नेशनल काउंसिल ने सत्ता संभाली लेकिन देश जगाने से उसके संघर्ष ने युद्ध की शुरुआत कर दी लेकिन 2014 में गृहयुद्ध शुरू हो गया।

अरब स्प्रिंग और सीरियाई प्रदर्शन–

2010 में 'अरब विद्रोह', जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया ने पहला विरोध प्रदर्शन देखा, जो बाद में कई देशों में फैल गया और इसके परिणामस्वरुप शासन व्यवस्थाएं बदल गई।

सीरिया भी इससे अछूता नहीं रहा। राष्ट्रपति बशर अल–असद के शासन और उसके बाद शुरू हुए गृह युद्ध के खिलाफ पहले विरोध प्रदर्शन के लगभग 14 साल बाद बसर–अल–असद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और बसर–अल–असद की हालत यह हुई कि वह सीरिया से भाग गया और इसके परिणाम स्वरुप जो सीरिया की राजधानी दमिश्क थी। वह सशस्त्र संघर्ष से घिर गई और जब विरोध प्रदर्शन शुरु हुआ तो असद ने बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्यवाही की। अब क्या था, विरोध प्रदर्शन गृहयुद्ध (civil war) में बदल गया। अब अमेरिका, रुस, ईरान और तुर्की ने विभिन्न समय पर अलग–अलग संस्थाओं के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई।

डोनाल्ड ट्रंप जी ने सत्तासीन हुए उन्होंने एक्स पर लिखा था कि ''सीरिया एक गड़बड़झाला है लेकिन हमारा मित्र नहीं है, अमेरिका को इससे कोई लेना–देना नहीं चाहिए। यह हमारी लड़ाई नहीं है। इसे चलने दे इससे शामिल न हों।''

निष्कर्ष–

अब हम एक नजर अरब स्प्रिंग के निष्कर्ष पर अपना दृष्टि डालें तो, में अलग –अलग देशों में अलग– अलग परिणाम दित्बाई देते हैं। कुछ देशों में शासन व्यवस्था में बदलाव दिखाई दिया, तो कुछ में गृहयुद्ध छिड़ गये। जैसे हम कुछ प्रमुख देशों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें तो हम पायेंगे कि ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया जैसे देशों में शासन व्यवस्था

में बदलाव आया और यहा की नवनिर्वाचित सरकारे अपने संविधान में संशोधन कर अच्छी व्यवस्था को जन्म दिया। वहीं सीरिया में बशर–अल–असद के खिलाफ नागरिक विद्रोहों ने गृहयुद्ध को जन्म दिया। अल्जीरिया, इराक, कुवैत, मोरक्को और सुडान में भी विरोध प्रदर्शन हुए। यूँ कहें तो ''अरब स्प्रिंग'' क्रांन्ति बहुत हद तक इसके परिणाम सफल भी असफल भी। स्प्रिंग के विश्लेषण में जिन प्राथामिक प्रभावों को आलोक में लाया गया है। उनमें से एक पिछौट के पहले समाज की औपचारिक और अनौपचारिक, संस्थाओं की सापेक्षित शक्ति या कमजोरी को प्रदर्शित करती है। उस समय की बात जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी तो ट्यूनीशिया में एक स्थापित बुनियादी दाचा था और लीबिया जैसे अन्यराज्यों की तुलना में छोटे–मोटे भ्रष्टाचार का स्तर कम था। यानि इसका अर्थ यह हुआ कि मौजूदा शासन को उत्बाड फेकने के बाद, ट्यूनीशियाई संस्थानों में सुधार के लिए अन्प जाना भीडिया जगहों की तुलना में कम काम किया था। ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे सोशल तक अधिक पहुंच वाले देश लोगों के बड़े समूहों को संगठित करने में अधिक प्रभावी साबित हुए। हालाँकि सोवाल मीडिया ने भूमिका ओं की घटनाओं को आकार देने में बडी का निर्वहन किया, लेकिन सामाजिक सक्रिमता शून्य में नहीं हुई और पिछली सरकार शर्शनों के दौरान विरोध प्रदर्शनों मौन समर्थन भी विभिन्न आन्दोलन की सफलता अरम स्प्रिंग बदल दिया गया। राष्ट्रीय सौन्य बलों का देशों में अरब से जुड़ा हुआ है। फायदा समाज में यह हुआ कि विरोध प्रदर्शनों में सेना के समर्थन को शिभन्न समाजों में जातीय एकरूपता की डिग्री से भी जोड़ा गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. **The Hindu.**
2. **The Arab Spring : The hope and reality of the uprisings. Mark L. Haas, 2016.**
3. **The Arab Spring : The end of Postcolonialism Hamid Dabashi. 2012.**
4. **दृष्टिं IAS.**
5. **Britanicca.**
6. **Wikipedia.**
7. **Indian Express.**

इजराइल-फिलिस्तीन का संघर्ष एवं पश्चिमी एशिया पर उसका प्रभाव-

पंकज कुमार

(नेट, जी0आर0एफ0)

शोध छात्र–

भूगोल विभाग

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री, गोंडा, (उ0प्र0)।

ये जो फिलिस्तीन है, यह भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा–सा ऐतिहासिक राज्य था। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसकी राजधानी यरूशलेम को पवित्र नगरी माना जाता है। यहाँ विश्व के दो प्रमुख धर्म – यहूदी और ईसाई – की उत्पत्ति हुई।

यही कारण है कि आज भी यह क्षेत्र तीनों पवित्र धर्मों के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्त्व रखता है। यहूदी मान्यता के अनुसार फिलिस्तीन उनका मूल जन्मस्थान है। मध्ययुगीन काल में जब यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार हुए, तो वे पलायन कर विभिन्न देशों में बस गए। परंतु जब यूरोप से उनका निर्वासन बढ़ने लगा, तब यहूदियों में एक स्वतंत्र राज्य की भावना प्रबल हुई।

धीरे–धीरे यहूदियों ने एक संगठित आंदोलन चलाया जिसे जायनवाद ;पवदपेउद्ध कहा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना था। 1897 ई. में थिओडोर हर्जल ने स्विट्जरलैंड के बेसल नगर में प्रथम जायनिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया और घोषणा की –

"यहूदी केवल तभी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं जब उनका अपना स्वतंत्र राज्य हो।"

इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष केवल सीमाओं का विवाद नहीं है; यह पहचान, विस्थापन, सुरक्षा, आत्मनिर्णय, और न्याय की मानवीय आकांक्षाओं का संघर्ष है। एक ओर सुरक्षा, शरण और संप्रभुता की यहूदी आकांक्षाएँ हैं, तो दूसरी ओर भूमि, राज्य और गरिमा के फिलिस्तीनी अधिकार हैं। यही कारण है कि यह संघर्ष दशकों से राजनीतिक बहस का विषय होने के साथ–साथ मानवीय पीड़ा का भी स्रोत बना हुआ है–गृहों का उजड़ना, शरणार्थी कैंप, रोजगार और शिक्षा का टूटना, तथा पीढ़ी–दर–पीढ़ी अविश्वास का सिलसिला।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद मण्डेट व्यवस्था और परवर्ती दशकों में यहूदी व फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलनों के उभार के साथ विवाद तीखा हुआ। 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना ;न्छळ। 181द्ध और 1948 में इजराइल के गठन के साथ प्रथम अरब–इज़राइल युद्ध छिड़ा। आगे 1956, 1967 और 1973 के युद्धों ने भू–राजनीतिक मानचित्र और कठोर बना

दिया—खासतौर पर 1967 के छह—दिवसीय युद्ध के बाद पश्चिम तट, गाजा, पूर्वी यरूशलम और गोलन हाइट्स पर इजराइली नियंत्रण, जो आगे चलकर संघर्ष का केंद्रीय प्रश्न बन गया।

1973 के यौम किप्पुर युद्ध ने केवल सैन्य मैदान ही नहीं बदला; इससे तेल राजनीति भी बदली। ओपेक प्रतिबंध ने वैश्विक तेल कीमतों को उछाला, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था मंदी और मुद्रास्फीति के चक्र में फँसी—यह दिखाता है कि यह संघर्ष पश्चिम एशिया से बाहर भी प्रभाव डालता है।

मूल विवाद के तत्व

1. सीमाएँ और क्षेत्र : 1967 में कब्जाए गए क्षेत्रों की स्थिति (पश्चिम तट, गाजा, पूर्वी यरूशलम, गोलन) और "भूमि के बदले शांति" का सिद्धान्त ;न्छैब 242ध्338द्ध लंबे समय से वार्ताओं का आधार है।

2. यरूशलम का दजा : यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पवित्र शहर—पूर्वी यरूशलम की संप्रभुता, पवित्र स्थलों की निगरानी और राजधानी का प्रश्न सबसे संवेदनशील मुद्दों में से है।

3. शरणार्थी और 'राइट ऑफ रिटर्न' : 1948 और 1967 के विस्थापन के बाद फ़िलिस्तीनी शरणार्थी आज भी न्छॅ। की सूची में करोड़ों की संख्या में पंजीकृत हैं; इनका भविष्य,

नागरिक अधिकार और पुनर्वास शांति–प्रक्रिया का कठिन पहलू बना हुआ है।

4. बस्तियाँ ै;मजजसमउमदजेद्ध और सुरक्षा : पश्चिम तट में बस्तियों का विस्तार तथा आतंकवादी हमलों/रॉकेट हमलों के जवाब में सुरक्षा–मूलक उपाय, दोनों ने परस्पर अविश्वास को बढ़ाया, जिससे 'दो–राष्ट्र समाधान' की व्यवहार्यता पर बार–बार प्रश्न उठता है।

शांति प्रयास :

1991 का मैड्रिड सम्मेलन और 1993–95 के ओस्लो समझौते एक निर्णायक मोड़ थे। च्स्व् और इजराइल की आपसी मान्यता, वेस्ट बैंक–गाज़ा में सीमित फ़िलिस्तीनी स्वशासन और अंतिम स्थिति के मुद्दों (सीमाएँ, यरूशलम, शरणार्थी, बस्तियाँ, सुरक्षा) पर आगे की वार्ता का रोडमैप तय हुआ। किंतु बाद की राजनीतिक हत्याएँ, आत्मघाती हमले/रॉकेट, बस्तियों का विस्तार तथा परस्पर अविश्वास ने प्रक्रिया को बार–बार पटरी से उतारा। 2000 के दशक में दूसरी इंतिफादा और गाज़ा–इज़राइल हिंसा–चक्रों (2008, 2014, 2021, 2023–वर्तमान) ने मानवीय संकट और गहरा किया।

2023 के बाद का परिदृश्य

अक्टूबर 2023 के हमलों और उसके बाद की युद्ध–स्थिति ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर हताहत, विस्थापन और बुनियादी ढाँचे की तबाही को जन्म दिया। न्छ एजेंसियों के अनुसार लाखों लोग विस्थापित हुए, स्कूल–अस्पताल प्रभावित हुए और मानवीय सहायता का प्रवाह बाधित रहा–जिससे नागरिकों के लिए पानी, खाद्य, स्वास्थ्य और आश्रय जैसे आधारभूत अधिकारों तक पहुँचना कठिन हुआ। साथ ही, इज़राइल में भी नागरिक हताहत और बंधक बनाए जाने जैसी त्रासदियाँ हुईं–जो संकेत देती हैं कि हिंसा का मानवीय दायरा सीमाएँ नहीं देखता।

पश्चिम एशिया पर प्रभाव :

1) सुरक्षा और सामरिक संतुलन

इज़राइल–फ़िलिस्तीन संघर्ष, लेबनान–सीमा तनाव, सीरिया में अस्थिरता, और ईरान–इज़राइल प्रतिद्वंद्विता मिलकर एक 'क्षेत्रीय सुरक्षा दुविधा' बनाते हैं। सीमावर्ती झड़पें, रॉकेट हमले, और सीमांकन को लेकर अनिश्चितता, जॉर्डन और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों की आंतरिक–बाह्य सुरक्षा नीतियों को भी प्रभावित करती है। 1967 और 1973 के युद्धों के बाद बनी संधियाँ (इज़राइल–मिस्र 1979; इजराइल–जॉर्डन 1994) यद्यपि स्थायित्व लाती हैं, पर फ़िलिस्तीनी प्रश्न अनसुलझा रहने से कुल मिलाकर शांति–व्यवस्था अस्थिर बनी रहती है।

2) ऊर्जा–अर्थव्यवस्था और समुद्री मार्ग

1973 के युद्ध के बाद तेल प्रतिबंध ने दिखाया कि पश्चिम एशिया में तनाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को कैसे झकझोर सकता है। आज भी संघर्ष के उभार पर कच्चे तेल की कीमतें, शिपिंग बीमा लागत, और आपूर्ति–श्रृंखलाएँ प्रभावित होती हैं। लाल सागर–पूर्वी भूमध्य–और सुयेज रूट की सुरक्षा पर असर, बीमा प्रीमियम का बढ़ना, तथा बंदरगाहों/टर्मिनलों की कार्यक्षमता में गिरावट व्यापार को महँगा बनाती है–जिसका असर भारत जैसे आयातक देशों तक जाता है।

3) कूटनीति और खेमाबंदी

ओस्लो के बाद कुछ समय के लिए उम्मीद जगी; बाद में अब्राहम समझौते जैसे सामान्यीकरण प्रयासों ने (इज़राइल के साथ कुछ अरब देशों के संबंध खुलने) क्षेत्रीय खेमाबंदी के नए रूप बनाए। लेकिन फ़िलिस्तीनी प्रश्न का टिके रहना इन प्रक्रियाओं की वैधता और टिकाऊपन पर प्रश्नचिह्न लगाता है–क्योंकि सड़क–स्तर की धारणा और पवित्र स्थलों का मुद्दा व्यापक जनमत को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर, यह संघर्ष पड़ोसी राजधानियों की घरेलू राजनीति, खाड़ी–देशों की रणनीति और अमेरिका/यूरोप/रूस जैसे बाहरी खिलाड़ियों की पश्चिम एशिया नीति का एक केंद्रीय निर्धारक बना रहता है। (सामान्य, पर व्यापक निष्कर्ष; पृष्ठभूमि के लिए संघर्ष–सारांतरण देखें)

4) मानवाधिकार, शरणार्थी और मानवीय सहायता

लगभग 60–70 लाख के बीच पंजीकृत फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों का बोझ जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पश्चिम तट और गाज़ा में सामाजिक–आर्थिक दबाव बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सहायता में UNRWA की भूमिका निर्णायक है; लेकिन फंडिंग/राजनीतिक दबाव में उतार–चढ़ाव राहत–प्रणाली को अस्थिर बनाते हैं–जिससे सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और महिलाएँ होती हैं। 2023 के बाद गाज़ा में विस्थापन और हताहतों की ताज़ा लहर ने क्षेत्रीय मानवीय संकट को और गहरा किया है।

5) धार्मिक–सांस्कृतिक संवेदनशीलता

यरूशलम/अल–अक्सा सहित पवित्र स्थलों का प्रश्न केवल स्थानीय राजनीति नहीं है; यह अरब–मुस्लिम विश्व, यहूदी प्रवासी समुदायों और ईसाई संस्थाओं तक फैला भावनात्मक मुद्दा है। पवित्र स्थलों पर तनाव से सड़क–स्तरीय प्रदर्शन, सोशल मीडिया लामबंदी, और कभी–कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी उभरता है–जो घरेलू राजनीति पर दबाव बनाकर क्षेत्रीय कूटनीति को कठिन कर देता है।

समाधान

(क) दो–राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) दशकों से अंतरराष्ट्रीय सहमति के रूप में प्रस्तुत होता रहा है–सीमाओं पर वार्ता, परस्पर सुरक्षा आश्वासन, यरूशलम पर विशेष व्यवस्थाएँ, तथा शरणार्थियों के लिए व्यावहारिक, सम्मानजनक समाधान। UNSC 242/338 जैसे ढाँचों ने इसी 'भूमि के बदले शांति' की दिशा सुझाई थी। पर यह तभी संभव है जब हिंसा रुके, बस्तियों के प्रश्न पर ठोस समझौता बने, और दोनों समाजों में भरोसा फिर से पैदा किया जाए।

(ख) क्रमिक/अंतरिम व्यवस्थाएँ – जहाँ सीमित क्षेत्रों में प्रशासनिक एकीकरण, आर्थिक गलियारे, और सुरक्षा–समन्वय बढ़ाकर जमीन पर "शांति के लाभ" दिखाए जाएँ। ओस्लो की सीख यही है कि रोडमैप के हर पायदान पर पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार–केंद्रित निगरानी आवश्यक है।

(ग) मानवीय प्राथमिकताएँ – युद्धविराम, बंधकों/कैदियों की अदला–बदली, सहायता का निर्बाध प्रवाह, स्कूल–अस्पतालों की सुरक्षा, और पुनर्निर्माण के लिए बहुपक्षीय ट्रस्ट–ये कदम किसी भी दीर्घकालिक समाधान के "पूर्व–शर्त" हैं।

(घ) विकास और रोज़गार – युवा आबादी को सम्मानजनक अवसर देना, क्रॉस–बॉर्डर SME/ स्टार्टअप सहयोग, जल–ऊर्जा–परिवहन जैसे साझा अवसंरचना

प्रोजेक्ट—ये सब संघर्ष—भूमि को ″प्रतिस्पर्धी शांतिपूर्ण विकल्प″ प्रदान कर सकते हैं। (सामान्य नीति—सिफ़ारिश)

निष्कर्ष

इज़राइल—फ़िलिस्तीन संघर्ष की कहानी खून—खराबे या बयानबाजी से अधिक, उन लाखों आम लोगों की कहानी है जो केवल सुरक्षा, सम्मान, और भविष्य चाहते हैं। पश्चिम एशिया के लिए यह संघर्ष ″स्थायी अस्थिरता″ का स्रोत बना रहा—ऊर्जा—बाज़ार से लेकर सामरिक समीकरण और कूटनीति तक। 1967, 1973 जैसे पड़ाव और 1993—95 के ओस्लो जैसे प्रयास दिखाते हैं कि युद्ध और आशा, दोनों इस इतिहास का हिस्सा हैं। आज आवश्यकता है कि क्षेत्रीय और वैश्विक खिलाड़ी ″मानव सुरक्षा″ (Human Security) को केंद्र में रखकर कूटनीति को पुनर्जीवित करें—ताकि सीमाएँ ही नहीं, बल्कि बच्चों की कक्षा, मरीज का अस्पताल, और हर परिवार की रसोई सुरक्षित हो सके। यही किसी भी न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति का मानक होना चाहिए।

त्ममितमदबमे:

1. **Encyclopaedia Britannica: "Israel–Palestine Conflict Explained (History, Maps & Dates)"**
2. **Encyclopaedia Britannica: "Six-Day War (1967)"**
3. **Encyclopaedia Britannica: "Yom Kippur War (1973)"**
4. **U.S. Federal Reserve History: "Oil Shock of 1973–74."**

मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका

United State of America & Middle East

डॉ0 सुनील कुमार तिवारी

असिस्टेंट प्रोफेसर

रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग

जवाहर लाल नेहरु स्मारक पी0जी0 कालेज

महराजगंज, (उ0प्र0)।

आज के दौर में जब कभी भी मध्य–पूर्व का जिक्र किया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की चर्चा अवश्य होती हैं, क्यूँ? इसी प्रश्नवाचक शब्द पर ही हम अपने चर्चा का विषय बनायेंगे।

मध्य–पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की जड़ें 19वीं सदी के शुरुआती **"त्रिपोलिटन युद्ध"** में अर्न्तनिहित है, जो 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्थापना के तुरन्त बाद हुआ था लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यह और अधिक विस्तृत हो गया। शीत युद्ध के दौरान जब मध्य–पूर्व क्षेत्र में जब सोवियत संघ ने मध्य पूर्व में जब प्रभाव हासिल कर रहा था तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस (सोवियत संघ) के प्रभाव को रोकने के अमेरिकी विदेशी शासनों की विभिन्न रूपों में व्यापक समर्थन दिया। इस लक्ष्य के संबंध में अमेरिका की ये जो सर्वोच्च्च प्राथमिकताओं में से एक अरब–इजराइल संघर्ष के चरम के दौरान अपने सोवियत समर्पित पड़ोसी अरब देशों के खिलाफ

इजराइल राज्य को समर्थन देना था। अन्य लक्ष्यों के अलावा फारस की खाड़ी से तेल का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ये जो अमेरिका है इस अमेरिका ने 1960 और 1970 के दशक में सऊदी अरब के साथ–साथ फारस की खाड़ी के अन्य अरब राज्यों के लिए मुख्य सुरक्षा संरक्षक के रूप में यूनाइटेड किंगडम की जगह ले ली। 2023 तक अमेरिका मध्य पूर्व के हर देश के साथ अपना राजनयिक संबंध बनाया है। शिवाय ईरान के, जिसके साथ 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद संबंध टूट गये थे। और सीरिया जिसके साथ 2012 में सीरियाई गृह युद्ध के फैलने के बाद संबंध निलंबित कर दिये गये हैं।

हाल ही के वर्षों में ग्रेटर मध्य–पूर्व में अमेरिकी प्रभाव कम हो गया है। सबसे ज्यादा अरब स्प्रिंग के बाद से लेकिन

फिर भी इतना ही पर्याप्त है। पूर्व में अमेरिकी सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं में इजराइल– फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करना और क्षेत्रीय राज्यों विशेष रूप से ईरान के मध्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को सीमित करना शामिल है। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले मध्य पूर्व के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध सीमित थे, हालांकि 19वीं सदी की शुरुआत में भी वाणिज्यिक संबंध मौजूद थे। अमेरिका ने 1801 से 1805 तक त्रिपोलिटन युद्ध के दौरान कर (Tax) भुगतान को लेकर **'आटोमन त्रिपोलिटानिया'** के साथ सैन्य संघर्ष किया, जिसे राष्ट्रपति थामस जेफरसन ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने 1833 में मस्कट और ओमान के सुल्तान के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया (सुल्तान ने अमेरिका को ब्रिटेन के भारी क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक संभावित संतुलन के रूप में देखा) ऐतिहासिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीत युद्ध के दौर से लेकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध तक मध्य–पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अगर हाल के वर्षों में देखें तो मध्य– पूर्व और खाड़ी देशों में उल्लेखनीय कमी आई है। अगर हम पिछले दशक की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की **''प्रभावी उपस्थिति''** कहे जाने वाले प्रभाव में स्पष्ट गिरावट देखी गई है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र में तकनीकि रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद वाशिंगटन ने मध्य पूर्व के जटिल राजनीतिक पारिस्थितिकीतंत्र से अलग रहने का फैसला किया है।

<u>**बदलती परिस्थितियाँ**</u>:–

ये जो खाड़ी क्षेत्र है इस खाड़ी क्षेत्र के भी संयुक्त राज्य अमेरिका के घटते प्रभाव को विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसकी स्थिति में बदलाव का एक उल्लेखनीय कारण भी है, जो क्षेत्रीय गतिशीलता में पर्याप्त परिवर्तन रहा है। जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा छोड़ा गया सुरक्षा शून्यता को भरने के लिए नये अभिनेता उभर कर सामने आ रहे हैं। सीरिया में तुर्की की सैन्य भागीदारी, इराक, सीरिया और लेबनॉन में ईरान के प्रभाव का विस्तार और असद शासन के लिए रूस के अटूट समर्थन ने शक्ति संतुलन को बदल दिया है– इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौथी विद्रोही और सीरिया में कुर्द बलों जैसे गैर राज्य अभिनेताओं ने भू–राजनीतिक परिदृश्य में और जटिलताएं जोड़ दी हैं। गंभीर रूप से, इन परिवर्तनों को विशेष रूप से क्षेत्र में घटते अमेरिकी प्रभाव से नही जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें रणनीतिक विकल्पों और इन क्षेत्रीय अभिनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।

आर्थिक परिवर्तन–

आर्थिक परिवर्तन ने भी अमेरिका की उपस्थिति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या **"फ्रैकिंग"** की उछाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर और मध्य पूर्व के बाहर अन्य देशों से तेल उत्पादन में वृद्धि ने तेल और गैस के लिए इस क्षेत्र में अमेरिकी निर्भरता को कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव और तरलीकृत प्राकृतिक गैस में वैश्विक विस्तार ने मध्य पूर्वी जीवश्म ईंधन के रणनीतिक महत्व को कम कर दिया है। इस क्षेत्र में अमेरिका की घटती भूमिका पर अरब–जगत की प्रतिक्रिया बहुआयामी रही है। कई क्षेत्रीय देशों ने अमेरिकी हस्तक्षेप वाद में कथित गिरावट पर राहत व्यक्त की है। अगर हम वाशिंगटन की बात करें, तो हम पायेंगे कि अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी वाशिंगटन की विदेश नीति के लक्ष्यों को साझा करते हैं। स्थिरता और सुरक्षा को रखने के बारे में कहीं अधिक आशंकित है। मध्य–पूर्वी देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका को जाते हुए देखने को अधिक अनिच्छुक है। वे अक्सर किसी न किसी तरह से ईरान से जुड़े हुए है, क्योंकि वे ईरान और उसके विदेशी गैर–राज्य भागीदारों को अमेरिकी वापसी के प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में देखते हैं। हालांकि कुछ जीसीसी देशों ने विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की है– विदेश नीति का विकास घरेलू घटनाओं, अन्य देशों की नीतिया या व्यवहार, विशिष्ट भू–राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की योजनाओं से प्रभावित होता है। कूट नीति विदेश नीति का प्राथमिक उपकरण है। युद्ध गठबंधन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सभी इसकी अभिव्यक्तियाँ या इसकी विफलता के परिणाम हो सकते हैं।

हाल ही के वर्षों में अरब स्प्रिंग विद्रोह के बाद हिंसा और अस्थिरता में वृद्धि और कट्टरपंथी पश्चिमी विरोधी विचारधाराओं वाले इस्लामवादी– चरमपंथी आतंकवादी समूहों के प्रसार के रूप में मध्य पूर्व में उथल–पुथल मची हुई। इसलिए अमेरिका ने लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाये रखी है और कुल मिलाकर मध्य–पूर्व को वैश्विक स्तर पर कुल अमेरिकी सेन्स सहायता का 50% से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी यह क्षेत्र अब पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर प्रतीत होता है, जिसमें कई तरह के संघर्ष और संकट है।

इस समय से पहले यूरोपीय शक्तियों ने मध्य–पूर्व से संबंध बनाए, मुख्य रूप में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ के माध्यम से 1950 के दशक के दौरान, शीतयुद्ध ने मध्य–पूर्व के बारे में और अधिक चिंता का विषय बना दिया। जब 1965 का दौर आता है तब इस क्षेत्र के प्रति अमेरिकी नीति बदल गई, जो 1970 की दशक में, ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान और अफगानिस्तान में राजनीतिक संकटों से बचने के लिए लोगों के पलायन के दौरान अधिक उदार आव्रजन (Migration) कानूनों में परिलक्षित हुई। मध्य पूर्व में तेल के कारण इन राजनीतिक संकटों और ऊर्जा संबंधों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को प्रभावित किया। 1980 के दशक में राष्ट्रपति कार्टर ने मध्य पूर्व के लिए कार्टर सिद्धान्त के रूप में जाना जाने वाला सिद्धान्त घोषित किया जिसने क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रयासों को निर्दिष्ट और एकीकृत किया अगर सही मायने में यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें, तो पायेंगे कि मध्य पूर्व में अमेरिकी कार्यवाईयों के लिए आयोजन सिद्धान्त के रूप में कार्य करता रहा है। इस योजना में ऊर्जा रक्षा खर्च और क्षेत्र के देशों के लिए समर्थन जैसे मुद्दों पर

ठोस कदम शामिल थे। सिद्धान्त का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा **''फारस की खाड़ी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए किसी भी बाहरी ताकत को रोकने का अमेरिकी उद्देश्य''** था। क्योंकि उस समय मध्य पूर्व के तेल में संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण हित थे। मध्य पूर्व एशिया अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ऐसा केन्द्र बन गया है, जहाँ अमेरिका और रूस जैसी बड़ी वैश्विक ताकतें अपने आर्थिक हितों के लिए इस क्षेत्र को अस्थिर करने की रणनीति पर काम करती है।

अमेरिका और ईरान के मध्य तनावः–

अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य संबंधों का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि जब से अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर आया है तब से दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंध की स्थिति देखी जाती है। और इनमें किसी प्रकार के सुधार की संभावना दिखाई भी नहीं देती। हिंसा से अभिशापित मध्य–पूर्व को एक बार फिर अशांति की ओर धकेला जा रहा है। अबकी बार अमेरिका के निशाने पर ईरान है। अमेरिका ने ईरान पर चोरी–छिपे परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाकर केवल उससे अपनी संधि को ही खत्म नहीं कर दिया है, बल्कि हाल ही में भारत और चीन जैसे चुनिन्दा देशों पर भी ईरान से तेल खरीदने की छूट वापस लेकर ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की अपनी निर्णायक चाल चली है।

तेल के संदर्भ में अमेरिका की विदेश नीतिः–

अगर हम तेल के संदर्भ में USA की नीति पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हम पायेंगे कि तकरीबन सौ सालों से पश्चिमी एशिया के भूगोल, राजनीतिक सुरक्षा और स्थिरता जैसे सभी आयाम **''तेल और पेट्रोलियम''** (Black Gold) पर

ही केंद्रित रहे हैं। अगर हम पिछले इतिहास पर अपनी नजर केंद्रित करें तो पायेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध (1914—1918) से लेकर 2003 के द्वितीय खाड़ी युद्ध तक मध्य पूर्व में हुई तमाम हलचले और समकालीन समय में जो अरब स्प्रिंग की भयावह जैसी क्रांतियाँ होती हैं, सीरियाई गृह युद्ध ईरान पर प्रतिबंध आदि—आदि।

क्षेत्रीय युद्ध के संभावित बढ़ने में ईरान की क्या भूमिका है?

ईरान मध्य पूर्व के उन दो देशों में से एक है, जिनके साथ अमेरिका का कोई अधिकारिक संबंध नहीं है। यह देश मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय तनावों में शामिल है कई समूहों का समर्थन करता है। जिसमें गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौथी विद्रोही गुट शामिल है। ईरान अपने द्वारा समर्थित समूहों के नेटवर्क को **"प्रतिरोध की धुरी"** कहता है। हाल ही के समय में एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट दी कि हमास को छोड़कर इस गठबंधन में शामिल समूह मध्य पूर्व में हमले बढ़ा रहे हैं। ताकि इजराइल हमास युद्ध को जारी रखना इजरायली और अमेरिका के लिए बहुत मंहगा प्रयास बन जाए। अगर देखा जाए तो ईरान, चीन और रूस के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। जिससे अमेरिकी नेताओं में चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच, लेबनॉन स्थित हिजबुल्लाह लेबनॉन की दक्षिणी सीमा पर इजराइल के साथ लड़ रह है। हाल ही में, एक इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत हो गई, जिससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और भी बढ़ जाने की आशंका है। इजराइल ने समूह के साथ **"एक और युद्ध"** की चेतावनी दी है, जो अमेरिका के लिए विशेष चिंता का विषय है, जिसने 1982 में इजराइल के आक्रमण के बाद 1984 में सैनिकों की

वापसी के बाद से लेबनॉन के साथ **''घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध''** बनाए रखने के लिए काम किया है।

<u>पेट्रो डॉलर</u>:–

ये जो पेट्रो डॉलर है ये अमेरिकी–डॉलर को ही पेट्रो डॉलर का जाता है। जो तेल–निर्यातक देशों को तेल के बदले भुगतान किया जाता है। जब 1944 का समय होता है तब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है जिसमें अमेरिकी डॉलर को विश्व की सबसे सुरक्षित मुद्रा माना गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में सर्वाधिक सोना अमेरिका के ही पास माना जाता था। ये जो अमेरिकी डॉलर है इस अमेरिकी डॉलर को सोने में आँका जाता है। 1971 में अमेरिकी मुद्रास्फीति जन्य मंदी (Stagflation) की वजह से यूनाइटेड किंगडम ने अपने पास मौजूद अधिकांश अमेरिकी डॉलरों के बदले सोना खरीद लिया।

<u>आर्थिक के साथ सामरिक दबाव</u>:–

अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक के साथ सामरिक दबाव बढ़ाने के लिए ईरान के विरोधी देश सऊदी अरब के साथ आठ अरब डॉलर के हथियार सौदे को मंजूरी दे रही है। इन हथियारों में अत्याधुनिक बम शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने युद्ध में पोत भी तैनात कर दिये हैं। इराक से अमेरिकी नागरिकों को वापस लौटने को कह दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से मध्य–पूर्व में पहले से ही जो अस्थिरता बनी हुई है, उसमें और वृद्धि हुई। ईरान के प्रति अमेरिकी नीति में आक्रमता का एक प्रमुख कारण अमेरिका का इजराइल के प्रति झुकाव भी रहा है।

क्लिंटन मध्य पूर्व और यूरोप के नेताओं से मुलाकात कर तनाव कम करने और क्षेत्रीय युद्ध को रोकने की कोशिश

कर रहे हैं क्लिंटन की यात्रा में तुर्की, ग्रीस, जार्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, बेस्ट बैंक और मिस्र शामिल है। अगर हम अमेरिकी विदेश विभाग की बात करें तो इसके अनुसार मध्य–पूर्व (जिसे उत्तरी अफ्रीका के साथ निकट पूर्व कहा जाता है। इसमें 18 देश और एक गैर–राष्ट्र फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिका के दो को छोड़कर हर मध्य पूर्वी देश के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध हैं। ईरान और सीरिया 1979 में ईरानी छात्रों द्वारा अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने और 50 से अधिक अमेरिकियों को बंधक बनाने के बाद अमेरिका ने 1980 में ईरान के साथ अधिकारिक राजनयिक संबंध तोड़ दिये, लेकिन फिर भी इस अमेरिका ने मानवीय सहायता आज भी जारी रखी है। अगर इजराइल के हम संबंधों की बात करें तो पांच मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ अधिकारिक संबंध हैं, **बहरीन**, **मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात** आदि से है। इनमें से तीन अधिकारिक संबंध 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित किए गए।

अब्राहम समझौताः–

2020 में एक ऐसा दौर जब, इजराइल, संयुक्त अरब–अमीरात, बहरीन और मोरक्को ने अब्राहम समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिससे आधिकारिक तौर पर तीनों देशों और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए इन देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण की दिशा में प्रगति माना जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. **The Hindu.**
2. **Drishti IAS**

3. **Indian Express.**
4. **The Middle East and the United States: A Historical and Political Reassessment. William B. Quandt.**
5. **The Middle east and the United States: Davidw. Lesch Mark L. Hass.**

I2U2: A Game Changer of the Middle East and The Global Politics

Abhishek Mishra

M.A. Political science

Middle east politics is experiencing the competition between US, China and India, also Russian involvement and in this competition India and US making partnership to counter China in this strategically important region. The U.S.-India partnership in the Middle East has been growing and has strategic importance, reflecting their shared interests in energy security, economic connectivity, and regional stability. There are various fields in which partnership is working to counter Chinese influence and protect Indian and US interest in the middle east region.

India also increases its Defence and security cooperation in this region. India and the U.S. work together on counterterrorism, maritime security, and intelligence-sharing in the Middle East. India maintains strong defense ties with Gulf nations, and the U.S. supports its expanding security role. Joint military exercises, such as the Malabar Exercise, enhance regional security cooperation. Also India is conducting military exercise with the individual countries of middle east to increase its Defence cooperation in this region.

Energy and trade that is the true potential of this region. The Middle East is crucial for India's energy needs, with over 60% of its crude oil imports coming from the region. Energy is most important reason that make Middle

eastern region one of the most strategic regions of the world. The U.S. supports India's energy diversification efforts, including LNG supplies and renewable energy projects. India and the U.S. back stability in key regions like the Strait of Hormuz to ensure uninterrupted energy flows.

Economy and connectivity is one of the important aspect of US and India partnership in the region, India and the U.S. are promoting alternative trade corridors, reducing dependence on Chinese-dominated routes. The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), announced at the G20 Summit in 2023, aims to boost connectivity between South Asia, the Middle East, and Europe.

This corridor competes with China's Belt and Road Initiative (BRI), reinforcing India's and the U.S.'s role in global supply chains.

US and India both nations support a stable Middle East that is less influenced by adversarial powers. India maintains balanced relations with countries like Israel, Iran, and Saudi Arabia, while the U.S. provides strategic backing. India's strong diaspora presence in the Gulf (9 million+ people) strengthens its diplomatic influence.

The Israel-Palestine conflict poses a diplomatic challenge, as India balances its historical ties with both Israel and Palestine. U.S.-Iran tensions affect India's interests, especially its access to Iran's Chabahar Port.

Overall, U.S.-India cooperation in the Middle East is set to grow, driven by economic interests, security concerns, and regional geopolitics. Their partnership aims to create a multipolar, stable, and economically integrated Middle East.

The I2U2 group –

This group is going to change the politics of middle east as well as the world politics. If this group goes well and it has a potential to be a game changer in the Global Geopolitics. This group comprising India, Israel, the UAE, and the U.S. It is an emerging strategic alliance aimed at fostering economic cooperation and regional stability in the Middle East. Launched in 2021, this grouping is often referred to as the “West Asian Quad” and is seen as a potential game changer in geopolitics. It is one of the strategically important group on the world stage.

Economic and Trade Connectivity- The I2U2 group seeks to boost regional trade by leveraging India’s manufacturing capabilities, Israel’s innovation, the UAE’s investment power, and the U.S.’s global influence. Major focus areas that this Quad is focusing include food security, clean energy, healthcare, and critical infrastructure. The initiative promotes cross-border investments, helping Gulf nations diversify their economies beyond oil.

Counterbalance to China’s Influence- The current top priority of the Government of India and the US is to limit the Chinese influence in global politics and especially in the strategically important region. In the middle east region I2U2 offers an alternative to China’s Belt and Road Initiative (BRI) in the Middle East, reducing dependency on Chinese infrastructure projects. The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), announced at the G20 Summit 2023, complements I2U2 by creating a new trade route linking South Asia, the Middle East, and Europe. This reduces reliance on the Suez Canal and enhances supply chain resilience.

Regional Stability and Security- In this region stability and security is one of the important concern for India as stability offers condition to realise any region its potential. I2U2 fosters greater regional cooperation, particularly in a historically volatile Middle East. By focusing on economic collaboration rather than military alliances, it reduces friction among member nations and promotes diplomatic stability. The initiative aligns with the Abraham Accords, which normalized relations between Israel and Gulf states, further promoting regional peace.

I2U2 and Geopolitical –

I2U2 allows the U.S. to maintain strategic influence in the Middle East by supporting economic initiatives rather than military intervention. It enhances U.S.-India cooperation, reinforcing their Indo-Pacific strategy.

India's involvement in I2U2 elevates its status as a key global player and bridges gaps between different geopolitical blocs.

It strengthens India's trade ties with the Gulf while maintaining its relationships with Iran and Russia. India's technology and manufacturing sectors benefit from increased collaboration with Israel and the UAE. Israel benefits by expanding its trade and security cooperation beyond the U.S. to India and the Gulf. The UAE positions itself as a global investment hub, attracting tech and infrastructure projects.

Food and Energy Security- A $2 billion food corridor project between India and the UAE ensures stable food supplies in the Middle East. Renewable energy projects—like the UAE-India-Israel solar energy collaboration—support sustainability and reduce dependence on fossil fuels. Conflicts like the Israel-Palestine

issue or tensions with Iran could disrupt cooperation. The four countries have different strategic priorities, which could slow decision-making. Large-scale projects like IMEC require sustained commitment and investment. I2U2 is a transformational initiative that enhances economic integration, geopolitical stability, and strategic partnerships in the Middle East. By shifting the focus from security to development, it offers a new model for global cooperation. If successful, I2U2 could redefine the Middle East's economic landscape and play a crucial role in shaping 21^{st}-century geopolitics.

Current war in middle east and I2U2-

The current conflict in the Middle East that is impacting the I2U2 group (India, Israel, UAE, and the United States) primarily revolves around the ongoing Israel-Hamas war, which escalated significantly following Hamas' attack on Israel on October 7, 2023. This conflict has cast a shadow over the I2U2 initiative, a partnership formed in 2021 to foster economic cooperation and joint investments in areas such as water, energy, transportation, space, health, and food security. The Israel-Hamas conflict has strained the dynamics within the I2U2 group, particularly affecting the relationship between Israel and the UAE. The UAE, a key member of I2U2, has publicly condemned Israel's military actions in Gaza, labelling the Hamas attacks and the subsequent Israeli response as a "serious and grave escalation." This stance reflects the UAE's sensitivity to regional sentiment and its need to align with broader Arab world perspectives, despite its normalization of ties with Israel under the Abraham Accords in 2020. The UAE's reluctance to engage actively with Israel amid the ongoing war has led to a dormancy in I2U2 activities, with no significant meetings or advancements reported since the last

Sherpas meeting in September 2023, held on the sidelines of the United Nations General Assembly.

India, adopting a "wait and watch" approach, has refrained from pushing the I2U2 agenda forward, prioritizing its delicate balancing act in the Middle East. India maintains strong ties with both Israel and Arab nations, including the UAE, and has historically supported the Palestinian cause while deepening strategic and economic relations with Israel. The conflict's escalation has complicated India's position, as it seeks to avoid alienating any regional partners. Sources indicate that India is unlikely to drive I2U2 initiatives unless the US and Israel take proactive steps, which seems unlikely given the UAE's current distancing from Israel due to the conflict.

The United States, while reaffirming I2U2 as a priority in early 2024, faces challenges in maintaining momentum for the group amid the Middle East turmoil. The Biden administration has emphasized the group's potential, but the lack of progress since the conflict intensified suggests that geopolitical tensions are overriding economic cooperation goals. The war has also raised doubts about related initiatives like the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), further illustrating the broader regional instability affecting I2U2.

The Israel-Hamas war, ongoing as of March 9, 2025, is the primary conflict spoiling the I2U2 group's progress. It has disrupted the UAE-Israel relationship, stalled collaborative projects, and forced India and the US to navigate a complex regional landscape, effectively putting the I2U2's ambitions on hold until stability returns or new diplomatic efforts emerge.

Future scenario of I2U2-

The comprising India, Israel, the United Arab Emirates (UAE), and the United States—hinge on several factors, including the resolution of the ongoing Israel-Hamas conflict, evolving geopolitical alignments, and the group's ability to deliver tangible economic and strategic outcomes. As of March 9, 2025, the group's momentum has been stalled by regional instability, but its long-term potential remains viable under certain conditions.

The ongoing war between Israel and Hamas, which escalated in October 2023, is the most immediate barrier to I2U2's revival. The UAE's public criticism of Israel's actions in Gaza and its subsequent distancing from joint initiatives with Israel have frozen I2U2 activities.

Short-Term Outlook- A ceasefire or de-escalation in Gaza is essential. Without it, the UAE is unlikely to re-engage fully with Israel within the I2U2 framework, given domestic and regional pressures to align with the Palestinian cause.

Long-Term Outlook- A sustainable resolution or at least a return to pre-October 2023 stability could restore UAE-Israel cooperation, allowing I2U2 to resume its focus on economic projects. The Abraham Accords, which normalized UAE-Israel ties, provide a foundation that could be rebuilt upon once tensions subside.

UAE's Balancing Act- The UAE seeks to maintain its image as a progressive regional leader while managing Arab solidarity. Progress in I2U2 will depend on the UAE's willingness to prioritize economic gains with Israel and India over political optics.

India's Neutral Stance- India's cautious approach, balancing ties with Israel, the UAE, and other Arab states, suggests it will only push I2U2 if the group's benefits outweigh diplomatic risks. A stable Middle East would embolden India to leverage I2U2 for energy security and trade diversification.

US Leadership- The United States, as the group's anchor, must actively drive I2U2 to counter China's growing influence in the region (e.g., via the Belt and Road Initiative). However, US domestic priorities and its focus on supporting Israel militarily may limit its bandwidth for I2U2 in the near term.

India offers a vast market, technological expertise (e.g., space and IT), and agricultural know-how.

Israel brings cutting-edge innovation in agritech, water management, and defense.

UAE provides financial muscle, logistical hubs, and renewable energy ambitions (e.g., solar projects).

US contributes capital, technology, and a strategic framework to align the group's goals.

Key Projects- Past initiatives, like the $2 billion UAE investment in Indian food parks using Israeli tech, showcase I2U2's potential. Future prospects could include joint renewable energy ventures, climate resilience projects, or space collaboration—areas less sensitive to political friction.

The group's success depends on sustained commitment from all four nations. The current hiatus suggests that political will is fragile amid conflict.

In the UAE and India, public sentiment toward Israel could constrain bold moves unless framed as purely economic partnerships.

Rival frameworks like the IMEC or China-led initiatives could dilute I2U2's relevance if it fails to deliver results soon.

Optimistic Scenario: If the Israel-Hamas conflict de-escalates by late 2025, I2U2 could reconvene by 2026, focusing on high-impact projects (e.g., green hydrogen or desalination). US mediation and India's diplomatic nudge could accelerate this.

Prolonged conflict or a broader regional escalation (e.g., involving Iran) could render I2U2 dormant indefinitely, with the UAE and India pivoting to bilateral ties or other alliances.

A slow thaw in tensions might see I2U2 limp along with limited, low-profile projects, preserving the framework but not realizing its full potential until the 2030s.

The future of I2U2 hinges on the Middle East's trajectory. While the Israel-Hamas war has sidelined the group as of March 2025, its strategic and economic rationale remains intact. A return to stability, coupled with proactive US leadership and UAE-Israel reconciliation, could position I2U2 as a key player in post-conflict regional development. However, without a clear resolution to current tensions, its prospects will remain uncertain, likely delaying significant progress beyond 2026. The group's ability to adapt to these challenges and deliver measurable outcomes will ultimately determine whether it thrives or fades.

<u>**Reference**</u> **–**

1- https://www.state.gov/i2u2

2- https://www.usip.org/publications/2022/07/what-you-need-know-about-i2u2

3- https://www.orfonline.org/research/the-i2u2-where-geography-and-economics-meet

4- https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=7760&lid=5166

5- https://www.onmanorama.com/news/india/2023/09/26/what-is-i2u2-grouping.html.

रूस-मध्य - पूर्व संबंधः भू-राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण

Dr. Anupama Srivastava

[Assistant professor]

Department of Defence and strategic studies]

Shri Lal Bahadur Shastri Degree College]

Gonda-

व्यापक मध्य पूर्व (उत्तरी अफ्रीका, लेवेंट और फारस की खाड़ी) में रूसी प्रभाव और उपस्थिति पिछले कई दशकों में काफी उतार–चढ़ाव भरी रही है। 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ ने मिस्र, इराक, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से, अरब जगत के एक नेता मिस्र ने पक्ष बदल लिया और अमेरिका का करीबी सहयोगी बन गया। 2020 के दशक में, इराक 1970 के दशक की तुलना में बहुत अलग देश है। ईरान के साथ युद्ध (1980–88), कुवैत पर कब्जा (1990–91), सद्दाम हुसैन शासन को गिराना (2003), और अंत में इस्लामिक स्टेट (ISI S) के साथ लड़ाई ने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता दोनों को खत्म कर दिया। मई 1990 में दक्षिण यमन का अस्तित्व समाप्त हो गया, जब इसे आधिकारिक तौर पर अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ मिला दिया गया।

सोवियत संघ 1990 (25 दिसंबर 1991) के अंत में भंग हो गया था और उभरते रूस को आर्थिक और राजनीतिक रूप

से खुद को स्थापित करने के लिए पुनर्गठित और स्थिर होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। रूस के व्यवहार की भविष्यवाणी करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह और भी मुश्किल हो गया है। जॉर्जिया के साथ 2008 का युद्ध, यूक्रेन–क्रीमिया (सिम्फरोपोल) में 2014 का हस्तक्षेप और 2015 का सीरियाई अभियान नीति निर्माताओं और विश्लेषकों को चौंका गया। 30 सितंबर 2015 को, रूस ने सीरियाई गृहयुद्ध में सीरियाई विपक्ष और इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ अपनी लड़ाई में सैन्य समर्थन के लिए बशर अल –असद की सरकार के अनुरोध के बाद सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। रूस के मध्य पूर्व के सभी देशों के साथ संबंध हैं । ऐतिहासिक रूप से यह वहाँ कई युद्धों में शामिल रहा है, विशेष रूप से तुर्की और ओटोमन साम्राज्य के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और हाल ही में सीरिया के समर्थन में भी आज, जब रूसी राजनीतिक प्रतिष्ठान मध्य पूर्वी देशों के साथ व्यवहार करता है, तो ऐसा लगता है कि वह बहुत कुछ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह साम्राज्यवादी समय में करता था–अक्सर उन्हें व्यापक कूटनीतिक और यहाँ तक कि सैन्य समर्थन भी देता है।

सैन्य दृष्टि से, ईरान पश्चिमी एशिया का एकमात्र देश है। जिसे (2007 में) सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, रूस–आधारित अन्तर्राष्ट्रीय संधि संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो नाटो के समानांतर है। राष्ट्रपति बनते ही व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ घनिष्ठ मित्रता अपनाई और ईरान और सीरिया के साथ रूसी सैन्य सहयोग को गहरा किया । 2015 में, पुतिन ने सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया, सीरियाई विपक्ष के खिलाफ हवाई बमबारी अभियान के साथ असद शासन और उसके ईरानी सहयोगियों का समर्थन किया। जबकि ईरानी सेना का

अधिकांश हिस्सा ईरानी निर्मित हथियारों और घरेलू हार्डवेयर का उपयोग करता है, ईरान अभी भी रूस से कुछ हथियार प्रणालियों की खरीद करता है। बदले में, ईरान ने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान अपने ड्रोन प्रौद्योगिकी और अन्य सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ रूस की सहायता की है।

रूस और ईरान दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन हैं, और प्रतिबंधों की प्रत्येक विस्तारित अवधि उनके बीच संबंधों को बेहतर बनाती है। हालांकि, रूस और ईरान दोनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के बाद यह कुछ हद तक बदल गया है। मास्को और तेहरान के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देशों के संबंधित संबंधों को सुधारना अधिक कठिन साबित हुआ। मार्च 2014 से, रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने और यूक्रेन को जानबूझकर अस्थिर करने के जवाब में, यूरोपीय संघ, अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देशों ने धीरे–धीरे रूस के खिलाफ प्रतिबंधात्मक प्रतिबंधों को अपनाया है। जवाबी कार्रवाई में, रूस ने कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगाते हुए, पश्चिमी देशों पर अपने प्रतिबंध लगाए। नवंबर 2018 में, जेसीपीओए द्वारा ईरान के खिलाफ हटाए गए प्रतिबंधों को ट्रम्प प्रशासन द्वारा पूरी तरह से बहाल कर दिया गया था, जो उस वर्ष की शुरुआत में सौदे से बाहर हो गया था।

24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। जिसके कारण यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और अन्य देशों द्वारा उस पर पर्याप्त आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए। रूसी सरकार के पास अब एक निर्दिष्ट, अमित्र देशों की सूची है, जो उन देशों को इंगित करती है। जिनके साथ अब संबंध तनावपूर्ण हैं (या अस्तित्वहीन हैं)। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद

से पश्चिमी दुनिया के साथ बिगड़ते संबंधों के बावजूद, रूस अभी भी कुछ देशों के साथ समर्थन और मजबूत संबंध बनाए हुए है, जैसे चीन, बेलारूस, वियतनाम (व्लादिमीर पुतिन के साथ हाल ही में बैठक के दौरान), ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, म्यांमार, इरिट्रिया, माली, जिम्बाब्वे, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन, बुरुंडी, इराक, लीबिया, आर्मेनिया और नाइजर। रूस को यमन से भी मजबूत समर्थन प्राप्त है।

रूस ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ट्रांसनिस्ट्रियन युद्ध और कोसोवो संघर्ष और दक्षिण ओसेशिया के प्रस्तावित रूसी विलय के बाद शांति को बढ़ावा देने की कोशिश में विशेष रूप से सक्रिय रूप से शामिल रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने 25 फरवरी 2008 को दावा किया कि नाटो और यूरोपीय संघ 2008 के कोसोवो स्वतंत्रता घोषणा के बाद सर्बों को कोसोवो छोड़ने से रोकने के लिए बल का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं।

रूस मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया का सह–प्रायोजक है और फारस की खाड़ी, कंबोडिया, बर्मा, अंगोला, पूर्व यूगोस्लाविया और हैती में संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय पहल का समर्थन करता है। रूस संपर्क समूह का संस्थापक सदस्य है और (जून 1997 में डेनवर शिखर सम्मेलन के बाद से) G7 का सदस्य था। नवंबर 1998 में, रूस एशिया–प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच (Asia-Pacific Economic Cooperation) में शामिल हो गया। रूस ने बोस्निया में नाटो के नेतृत्व वाले स्थिरीकरण बल में सैनिकों का योगदान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और OSCE सिद्धांतों के प्रति अपने सम्मान की पुष्टि की है। रूस ने पड़ोसी देशों में क्षेत्रीय संघर्ष के मामलों में UN

और OSCE की भागीदारी को स्वीकार किया है, जिसमें जॉर्जिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान और पूर्व आर्ट्सख गणराज्य में पर्यवेक्षकों को भेजना शामिल है।

रूस और लातविया के बीच प्सकोव ओब्लास्ट के पाइटालोवो (अबरेन) क्षेत्र को लेकर विवाद 27 मार्च 1997 की सीमा संधि में सुलझा लिया गया था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ सीमा पर विवाद अंततः 21 जुलाई 2008 को सुलझा लिया गया। उस दिन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बीजिंग में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत रूस ने चीन को लगभग 174 किमी 2 क्षेत्र सौंप दिय है। हस्तांतरित क्षेत्र में ताराबारोव द्वीप और बोल्शॉय उसुरीस्की द्वीप का लगभग आधा हिस्सा शामिल था । हस्तांतरित क्षेत्र बड़े पैमाने पर निर्जन था। उनके सीमा विवाद का निपटारा 40 वर्षों से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद हुआ। अंतिम समझौता अच्छे–पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि का परिणाम था। जो 2 जून 2005 को संपन्न हुआ और चीनी विदेश मंत्री ली झाओक्सिंग और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। इसके बाद व्लादिवोस्तोक में वार्ता हुई । अब रूस और चीन के बीच उनकी 4300 किलोमीटर की सीमा पर कोई सीमा विवाद नहीं है।

कैस्पियन सागर की सीमाएँ अभी तक सभी तटीय राज्यों के बीच निर्धारित नहीं की गई हैं। रूस और उसके सीमावर्ती राज्यों–अजरबैजान और कजाकिस्तान के मध्य के मुद्दों को 2003 में सुलझा लिया गया था। रूस की तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ कोई साझा भूमि या कैस्पियन–सागर सीमा नहीं है, जो कैस्पियन सागर के समझौतों से सहमत नहीं हैं। रूस ने अंटार्कटिका में कोई क्षेत्रीय दावा नहीं किया है। जबकि वह एक ऐसा देश है, जिसने सबसे पहले उस महाद्वीप

की खोज की थी (लेकिन उसने ये दावे करने का अधिकार सुरक्षित रखा है), और वह किसी अन्य देश के दावों को मान्यता नहीं देता है। सोवियत संघ ने 1960 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

ताइवान का दावा है कि उसके भूभाग में किंग साम्राज्य के सभी भूतपूर्व भूभाग शामिल हैं। रूस और मध्य पूर्व (डपककसम म्ंेज) के देशों के बीच संबंध ऐतिहासिक, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारकों पर आधारित हैं। यह संबंध शीत युद्ध (Cold-War) के समय से लेकर आज तक विभिन्न उतार–चढ़ाव से गुजरे हैं। रूस ने हमेशा मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर ऊर्जा व्यापार, सैन्य सहयोग और भू–राजनीतिक रणनीतियों के संदर्भ में है।

शीत युद्ध के दौरान, सोवियत संघ ने कई अरब देशों (मिस्र, सीरिया, इराक) का समर्थन किया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने के लिए सोवियत संघ ने अरब राष्ट्रवादियों और वामपंथी आंदोलनों का सहयोग किया। 1967 के छह–दिवसीय युद्ध (Six Day War) और 1973 के योम किप्पुर युद्ध (Yom Kippur War) में सोवियत संघ ने अरब देशों को सैन्य सहायता दी।

सोवियत संघ का पतन और रूस का उदय–

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस ने मध्य पूर्व में अपना प्रभाव काफी हद तक खो दिया। 2000 के दशक में व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस ने फिर से मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति मजबूत करनी शुरू की। वर्तमान में रूस और मध्य पूर्व के बीच संबंध क्या हैं। जैसे–सैन्य और राजनीतिक संबंध अगर हम देखें तो, जैसे–सीरिया संघर्ष (Syria Conflict):–2015 में, रूस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल–असद (Bashar al-Assad) को बचाने के लिए सैन्य

हस्तक्षेप किया। रूस ने सीरियाई सेना को आधुनिक हथियार, वायु सेना का समर्थन और सैन्य सलाहकार प्रदान किए। इसके बदले में, रूस को टार्टस (Tartus) में नौसैनिक अड्डा और हमीमिम (Hmeimim) में वायुसेना अड्डा मिला। जैसे– ईरान से संबंधः–रूस और ईरान रणनीतिक सहयोगी हैं, विशेष रूप से सीरिया और अफगानिस्तान के मामलों में। रूस ने ईरान को परमाणु समझौते (JCPOA) में समर्थन दिया। दोनों देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जैसे–सऊदी **अरब और खाड़ी देशः–**रूस और सऊदी अरब के बीच हाल के वर्षों में ऊर्जा सहयोग बढ़ा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच सीरिया और ईरान के मुद्दे पर मतभेद भी हैं। 2019 में, पुतिन ने सऊदी अरब का दौरा किया और कई रक्षा एवं तेल समझौतों पर हस्ताक्षर किया।

ऊर्जा और आर्थिक संबंध–

रूस और मध्य पूर्व दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक हैं। इनमें कई संगठन भी हैं, जैसे–ओपेक् (OPEC+) गठबंधन। रूस और सऊदी अरब ने 2016 में

OPEC+ समूह बनाया, जिससे तेल उत्पादन पर नियंत्रण रखा जा सके। इस गठबंधन का मकसद तेल की कीमतों को स्थिर रखना और वैश्विक बाजार में संतुलन बनाए रखना है। अब जैसे **–रूस–कतर संबंधः–**कतर दुनिया का सबसे बड़ा स्छळ (लिक्विफाइड नैचुरल गैस) निर्यातक है और रूस भी इसी उद्योग में बड़ी भूमिका निभाता है। दोनों देश ऊर्जा बाजार में सहयोग कर रहे हैं।

हथियारों की बिक्री और रक्षा सहयोग–

रूस मध्य पूर्व के कई देशों को हथियार बेचता है, जिसमें मिस्र, अल्जीरिया, ईरान और तुर्की शामिल हैं। तुर्की ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से S–400 मिसाइल प्रणाली खरीदी। मिस्र और अल्जीरिया ने भी रूस से अत्याधुनिक सैन्य उपकरण खरीदे हैं। अब जैसे–रूस और इजरायल के बीच संबंध–रूस और इजरायल के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध अच्छे हैं। रूस में बड़ी संख्या में यहूदी प्रवासी रहते हैं जो इजरायल में भी बसे हैं। हालांकि, सीरिया और ईरान को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ तनाव रहता है। रूस ने सीरिया में इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखा है। रूस और तुर्की के बीच संबंध पर हम ध्यान केंद्रित करें तो–रूस और तुर्की के बीच जटिल संबंध हैं। 2015 में तुर्की ने एक रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया था, जिससे तनाव बढ़ गया था। लेकिन बाद में दोनों देशों ने अपने संबंधों में सुधार किया और आर्थिक तथा सैन्य सहयोग बढ़ाया। रूस ने तुर्की को S–400 मिसाइल सिस्टम बेचा, जिससे तुर्की और नाटो (NATO) देशों के बीच तनाव पैदा हो गयङ्ग

चुनौतियाँ और भविष्य–

अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबावः– अमेरिका और यूरोप रूस के मध्य पूर्व में बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं। रूस पर प्रतिबंधों के कारण कुछ मध्य पूर्वी देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

सीरिया और लीबिया में संघर्षः–

रूस ने सीरिया में सफलता हासिल की, लेकिन लीबिया में उसे पश्चिमी देशों और तुर्की की चुनौती का सामना करना पड़ा।

ऊर्जा प्रतिस्पर्धाः–

रूस, सऊदी अरब और कतर ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं।भविष्य में गैस और तेल की कीमतों को लेकर इन देशों के बीच मतभेद हो सकते है।

निष्कर्ष–

रूस और मध्य पूर्व के संबंध बहुआयामी हैं, जिनमें सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग शामिल हैं। रूस ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सीरिया युद्ध, ओपेक् गठबंधन और हथियार निर्यात जैसी रणनीतियाँ अपनाई हैं। हालांकि, अमेरिका, यूरोप और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण रूस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भविष्य में रूस की मध्य पूर्व में भूमिका बनी रहेगी, लेकिन उसे कई कूटनीतिक और आर्थिक बाधाओं से जूझना पड़ेगा।

संदर्भ–ग्रंथ–सूची–

1. **https%//en-m-wikipedia-org/wiki/Middle_East**
2. **WIKIPEDIA – Russian and Middle East**

3. **https%//www-britannica-com/place/Middle&East**
4. **RUSSIA AND THE MIDDLE EAST% VIEWPOINTS< POLICIES< STRATEGIES %& FYODOR LUKYANOV-**
5. **BRITANNICA Russia and Middle East**
6. **https%//www-worldatlas-com/webimage/countrys/me-htm**

मध्य-पूर्व के भविष्य की संभावनाएं

Dr. Vidya Srivastava
[Assistant professor]
Department of defence and strategic studies
Dr Ashok smarak P-G-college] Ambedkar Nagar

यदि हम मध्य–पूर्व के भविष्य की संभावना पर चर्चा करें, तो हम पाएंगे कि मध्य–पूर्व में अराजकता आज भी है और पुरानी व्यवस्था टूट रही है। क्षेत्र के कई देशों में सुन्नी अरब विद्रोह कर रहे हैं। वे आज दुनिया में अपनी दयनीय स्थिति, स्वतंत्रता का अधिकार और समृध्दि की कमी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बदलाव के लिए बेताब बढ़ती जनसंख्या में लोग इस्लामवादी आंदोलन की ओर मुड़े हैं लेकिन उनकी जीत को लगातार विफल किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा था, कि इसका परिणाम चरमपंथ की ओर झुकाव और पूरे क्षेत्र में कट्टरपंथी समूहों का उदय रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम एक सुन्नी मुस्लिम समस्या है। एक शुरुआती बिंदु के रूप में, इसका मतलब यह है की क्षेत्र के लोगों की यह तय करने की अनुमति देना कि उन पर कौन शासन करता है क्योंकि केवल एक सामान्य राजनीतिक जीवन ही कट्टरपंथी इस्लाम को पोषित करने वाले वैचारिक और आर्थिक दलदल को खत्म कर सकता है। खासकर क्षेत्र के दो प्रमुख देश पहला–मिस्र और दूसरा–सऊदी अरब मिस्र–सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधिपत्य पर और सऊदी अरब–धार्मिक और वित्तीय महाशक्ति में इस रास्ते के लिए सुन्नी मुस्लिम, दुनिया और पश्चिम के बीच और दुनिया के मौजूदा नेताओं

और उनके नागरिकों के बीच संबंधों के एक मौलिक पुनर्संतुलन की आवश्कता है। आइये बात करते हैं गाजा की, गाजा में निरंतर युद्ध विराम मानवीय सहायता और आर्थिक तथा राजनीतिक पुनर्निर्माण की उम्मीदें क्षेत्र में बढ़ते क्रोध, गुस्से और शत्रुता की चिताओं से मिलती हैं। अगर इन बातों पर विचार किया जाए तो अब तक का सबसे खराब संभावित परिणाम परिदृश्य दो हैं। एक व्यापक युद्ध होगा जिसके विनाशकारी परिणाम न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि संभावित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी होंगे। अल्पावधि में कल्पना की जा सकने वाली सर्वाधिक अच्छी स्थिति यह होगी कि इजरायल की थकावट बढ़ेगी। हमास के अधिकांश हिस्से का विनाश की संभावना है जिसके परिणामस्वरुप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित फिलिस्तीन और अरब अभिनेताओं के साथ सीमित समझौता होगा। 07 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के 9 महीने के ठीक बाद भी मध्य पूर्व बेहद अस्थिर और नाजुक स्थिति में है। गाजा युद्ध आज भी बिना किसी समाधान के जारी है और लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच और भी ज्यादा विनाशकारी संघर्ष छिड़ने का खतरा बढ़ रहा है इस स्थिति को और भी जटिल बना रहा है।

''मध्य–पूर्व में चल रहे संघर्ष ने पहले ही भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। फिलिस्तीनी क्षेत्र आर्थिक पतन के करीब हैं, अगर हम वास्तविक समीक्षा करें, तो पायेंगे कि जहाँ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकुचन हुआ है वहीं 2024 की पहली छमाही में गाजा की अर्थव्यवस्था 86 प्रतिशत तक सिकुड़ गई और पश्चिमी तट अभूतपूर्व वित्तीय और निजी क्षेत्र के संकट का सामना कर रहा है। संघर्ष प्रभावित लेबनान में, दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है और संघर्ष की दिशा के अनुसार ही इसका आकार तय होगा। मध्य पूर्व की

बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को सहायता देने के लिए कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति पर सहयोग करना आदि। अगर हम सांस्कृतिक विनियमन की बात करें तो शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के मध्य संपर्क को बढ़ावा देना।

प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव–

मौसम में परिवर्तन और तापमान :–

IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change (1988) का अनुमान है कि 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा। अगर हम सर्दियों के महीना की बात करें तो इस महीने के दौरान वार्मिंग की अनुमानित दरें कम है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो इस क्षेत्र में गर्मियों के महीनों के दौरान अत्यधिक तापमान में वृद्धि का अनुभव होने की संभावनाएं हैं, जिससे वाष्पीकरण शीतलन सीमित हो जाएगा। परिणामस्वरूप Middle East North Africa क्षेत्र में गर्मी की चरम सीमाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। "मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री" द्वारा प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार 1970 की दशक में और रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय 2016 के मध्य क्षेत्र में बहुत गर्म दिनों की संख्या दोगुनी हो गई है।

आइये अब इसके कई क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करें यदि हम अपना ध्यान भारत मध्य पूर्व के संबंध पर दें तो भारत सक्रिय रूप से मध्य– पूर्व के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना निवेश आकर्षित करना और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना है।

मध्य–पूर्व में इजरायल और हमास के बीच बिना किसी उकसावे के युद्ध ने समुदाय में बहुत तबाही मचाई है, जिसकी कोई समयसीमा नहीं है। संघर्ष तब शुरू हुआ जब हमास ने 07 अक्टूबर 2024 को दो सौ इजरायली लोगों को बंधक बना लिया। 9 महीने हो चुके हैं और 33,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संघर्ष को रोकने के लिए कई बार की गई बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला और युद्ध का माहौल पड़ोस, लेबनान तक फैल रहा है। लेबनान में पूर्ण पैमाने पर युद्ध की घोषणा, वास्तव में, तीसरे विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त करती है क्योंकि इस्लामी ताकतें इजरायल की रक्षा के लिए पूरी ताकत से एकजुट हो रही हैं। मध्य–पूर्व में मौजूदा स्थिति के कारण कई विकास रुक गए हैं और लाखों लोग खाद्य सुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है। हौथी

विद्रोहियों ने अपने रास्ते में कंटेनर जहाजों को हाईजैक करके के लिए उन पर हमला किया। इसके परिणामस्वरूप शिपिंग शुल्क में वृद्धि हुई और मध्य पूर्व में महंगाई बढ़ी। चूंकि मध्य पूर्व अपने तेल भंडारों के लिए जाना जाता है, इसलिए ईरान, सीरिया, इराक और अन्य देशों में युद्ध का और विस्तार प्रतिबंधों को आकर्षित करेगा और तेल की कीमतों में वृद्धि करेगा। जैसा कि "आईडीएफ के एक अधिकारी ने कहा, हमास कोई जिम्मेदार सैनिकों वाला संगठन नहीं है, यह लोगों के दिलों की भावना है'' जिसे सशस्त्र आक्रमण से मिटाया नहीं जा सकता। इसी तरह, लेबनान में, हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसकी जनता पर गहरी पकड़ है। लेबनान पर इजरायल का हमला और अधिक विनाश करेगा और भू–राजनीति को अस्थिर करेगा। इसी तरह, रूस और यूक्रेन के बीच एक और संघर्ष चल रहा है जिसमें युद्ध विराम के कोई संकेत नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र को इन कार्रवाइयों का संज्ञान लेना चाहिए और निर्दोष लोगों पर अकारण आक्रमण को रोकना और व्यवसाय को आकर्षित करना और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना है।

''शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय और इजरायली शिक्षाविदों के बीच बेहतर संबंधों में बाधा डालने वाला एक मुद्दा पैसा है। दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को इस प्रकार के आदान–प्रदान का समर्थन करने के लिए जुटाया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी मुद्दे पर बोलते हुए, यह उल्लेख किया गया कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति में गिरावट आई है। यह बताया गया कि इजराइल के लिए फिलिस्तीनी मुद्दा गौण है और मुख्य मुद्दा नहीं है। इजराइल भारत द्वारा फिलिस्तीनियों को एकतरफा दृष्टिकोण अपनाने में समर्थन देने पर कुछ हद तक चिंतित हो सकता है। हालाँकि भारत संयुक्त राष्ट्र में कार्य करना चाहता है, इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे संयुक्त राष्ट्र को ''नैतिक रूप से दिवालिया संस्था'' के रूप में देखते

हैं। यरुशलम के प्रश्न पर विचार–विमर्श करते हुए, वक्ता ने बताया कि भारत को पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी के रूप में फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करते समय इस मुद्दे पर इजराइल की संवेदनशीलता को पूरी तरह से समझना चाहिए। इजराइल यरुशलम को इजराइल की शाश्वत राजधानी के रूप में देखता है। यह शहर यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए धार्मिक महत्व भी रखता है। यह इजराइल के लिए कोई मामूली मुद्दा नहीं है इसलिए, भारत को इस प्रश्न पर इजराइलियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए।''

मध्य–पूर्व में चल रहे संघर्ष ने पहले ही भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। फिलिस्तीनी क्षेत्र आर्थिक पतन के करीब हैं, जहाँ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकुचन हुआ है। 2024 की पहली छमाही में गाजा की अर्थव्यवस्था 86 प्रतिशत तक सिकुड़ गई और पश्चिमी तट अभूतपूर्व वित्तीय और निजी क्षेत्र के संकट का सामना कर रहा है। संघर्ष प्रभावित लेबनान में, दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है और संघर्ष की दिशा के अनुसार ही इसका आकार तय होगा। इस बीच, जॉर्डन और मिस्र जैसे अन्य पड़ोसी देश पर्यटन प्राप्तियों और राजकोषीय राजस्व में गिरावट से प्रभावित हुए।

''हिजबुल्लाह की स्ट्राइक क्षमताओं से इजरायल को होने वाले जोखिम को देखते हुए, लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान में समय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इजरायल ने चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों के अपने विकास का उपयोग एक बहु–क्षेत्रीय बल को डिजाइन करने के लिए किया, जो एक कमांड ढांचे के तहत और एक परिभाषित मिशन की दिशा में सामरिक स्तर पर साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युध्द, वायु, सेंसर, सूचना प्रसंस्करण, स्ट्राइक और जमीनी तत्वों को एक

साथ संचालित करता है।2 इसने बेरूत के घनी आबादी वाले उपनगरों और दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के गढ़ों में हवाई हमलों का एक निरंतर अभियान चलाया।

इन हमलों में हिज्बुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह, हिज्बुल्लाह के हथियारों के भंडार, लॉन्चिंग साइट्स और लेबनान–सीरिया सीमा पर रणनीतिक क्रॉसिंग सहित कई उच्च–स्तरीय नेताओं को निशाना बनाया गया। इजराइल द्वारा तेजी से की गई कार्रवाई के सामने, हिज्बुल्लाह अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने में असमर्थ था, विशेष रूप से पारंपरिक सैन्य रणनीति की ओर मुड़ना, जहाँ वह इजराइल में मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्च कर रहा था ताकि इजराइल द्वारा लेबनान में हजारों हिज्बुल्लाह ठिकानों पर हमला किए जाने के दौरान निरोध बनाए रखा जा सके।

संघर्ष के दौरान ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को सीधे समर्थन न देना पूरी तरह से उसकी अग्रिम रक्षा रणनीति के अनुरूप था। ईरान के लिए, 'प्रतिरोध की धुरी' में उसके सहयोगी, विशेष रूप से हिजबुल्लाह की अग्रिम हमला करने की क्षमता, ईरान की परमाणु सुविधाओं पर इजरायल के हमले और दक्षिण लेबनान में भविष्य के इजरायली दुस्साहस के खिलाफ निवारक के सीमित उद्देश्य की पूर्ति करती थी। न तो हमास और न ही हिजबुल्लाह को इजरायल के साथ पूर्ण संघर्ष में शामिल होने से बलिदान होना था।

आगे का रास्ता–

यहाँ पर सभी पक्षों के मध्य कूटनीतिक संपर्क और बात को बढ़ाना ताकि उन्हे हिंसा से रोका जा सके तथा कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजा जा सके। दीर्घकालिक सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए द्वि–राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इजराइल–फिलिस्तीन मुद्दों का समाधान ढूढना। भारत देश के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए शुध्द सुरक्षा प्रदाता और मध्यस्थ के रूप में उभरने का अवसर मिल रहा है। क्षेत्र में विभिन्न गैर–पारम्परिक खतरों से सुरक्षा के लिए भारतीय नौ सेना (आपरेशन संकल्प) और संयुक्त राज्य अमेरिका (आपरेशन प्रॉसपेरिटी गार्जियन) व्दारा अदन की खाड़ी, अरब सागर और सोमालिया के पूर्वी तट के क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा अभियान चलाए गए हैं।

निष्कर्ष–

भारत को इस क्षेत्र में अपने व्यापक हितों जैसे ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा भारत इस क्षेत्र में अपनी सभ्यतागत साख का उपयोग विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने और अपनी भू–राजनीतिक और भू–आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तटस्थ पक्षों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ने के लिए कर सकता है। देखो अगर हम मध्य पूर्व के एक देश सीरिया की बात करें या इसकी तुलना में अधिक तीव्र सांप्रदायिक क्षेत्रीय और जनजातीय मतभेदों के कारण राज्य खुद हिंसक रूप से विभाजित हो सकता है और अरब प्रायव्दीप को सऊदी से पहले की अराजकता की स्थिति में वापस ला सकता है। अन्य खाड़ी देश के बह जाने का खतरा है। ईरान क्षेत्र में पश्चिम का नया मुख्य सहयोगी बनकर उभर रहा है

संदर्भ–ग्रन्थ–सूची–

- **IDSA REPORT**
- **The Hindu – keyword – The middle east-**
- **Britannica – Future prospects of Middle East-**
- **https%//www-bbc-com/news/articles/clylzÛ1Ûz2yo**
- **WIKIPEDIA& Future prospects of Middle East**
- **https%//www-idsa in/india&israel&bilateral&relations&current&status& and&future**

जलवायु परिवर्तन: मध्य पूर्व की चुनौतियाँ

Dr- Ajeet Kumar Mishra
[Assistant professor]
Department of Geography]
Shri Lal Bahadur Shastri Degree College]
Gonda.

आईए हम सर्वप्रथम जलवायु परिवर्तन का केंद्रित होकर अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान तथा मौसम विज्ञान के मनीषियों के अनुसार धरती दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के संबंध में शैक्षिक समूह के बीच एक सशक्त आम सहमति बन गई। जलवायु परिवर्तन के कारण "भौतिक तथा मानवीय" दोनों है। औद्योगिक क्रांति के उपरांत भूमंडलीय तापवृद्धि का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है। मानव गतिविधियों जैसे औद्योगिक प्रक्रम, जीवाश्म ईंधन, का भूमि उपयोग में बदलाव इन गैसों की बनने का मुख्य कारण है। निसंदेह पृथ्वी और गर्म होती जा रही है अधिकांश अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान वृद्धि से भूमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है तथा मानव स्वास्थ्य गतिविधि क्षमता एवं जनसंख्या विस्तार पर प्रभाव पड़ता है। ''जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन 1800 के दशक से, मानवीय गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रही हैं, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला, तेल और गैस) के जलने के कारण, जो गर्मी

को रोकने वाली गैसें पैदा करते हैं।" संयुक्त राष्ट्र से "21वीं सदी के पहले दशकों में जलवायु परिवर्तन के कई प्रभाव देखे गए हैं, 2024 1.60 °C (2.88 °F) के साथ रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होगा, जब से 1850 में नियमित ट्रैकिंग शुरू हुई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं को इस सदी की

सबसे बड़ी चिंता के रूप में पहचाना गया है। यह विषय भविष्योन्मुखी, प्रासंगिक और बहु–विषयक है, जिसमें कई हितधारक शामिल हैं। यह मामला न केवल ग्रह के स्वास्थ्य को बल्कि राष्ट्रों और व्यक्तियों के स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। यह लेख बहस और चर्चा के तहत मुद्दों को समेकित करने का प्रयास करता है और कुछ के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है जैसेः इसके शमन के लिए धीमी प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा विज्ञान, अर्थशास्त्र, ऊर्जा, राजनीति, सैन्य निहितार्थों के लिए इसके निहितार्थ आर्कटिक का सैन्यीकरण और, साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और समानता पर भारत की सैद्धांतिक स्थिति। यह लेख अधिक से अधिक सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक

कूटनीति और रणनीतिक संचार को फिर से देखने और बढ़ावा देने का तर्क देता है।'' ''मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) में जलवायु परिवर्तन एमईएनए क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन और क्षेत्र के देशों की प्रतिक्रिया, अनुकूलन और शमन रणनीतियों को संदर्भित करता है। 2018 में, एमईएनए क्षेत्र ने 3.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) का 8.7: उत्पादन किया। जबकि वैश्विक आबादी का केवल 6: हिस्सा यहां है।'' ''मध्य पूर्व हरित पहल (एमजीआई) सऊदी अरब के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय प्रयास है। जिसका उद्देश्य क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग करना है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाकर और उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाकर, एमजीआई जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रभाव को बढ़ा सकता है, साथ ही क्षेत्र के लिए दूरगामी आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है।

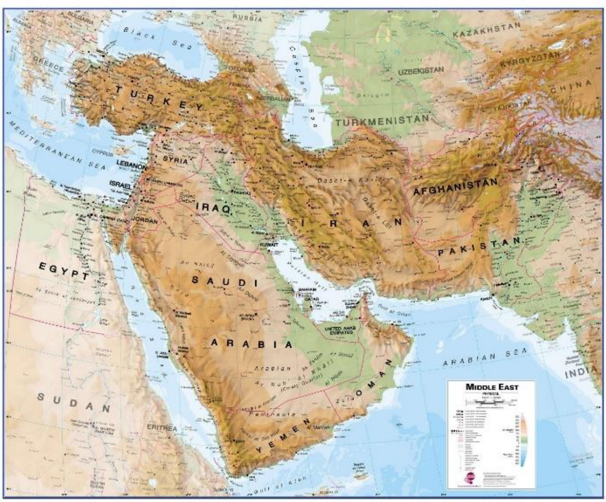

एमजीआई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, महामहिम क्राउन प्रिंस ने नवंबर 2022 में घोषणा की कि सऊदी अरब एक समर्पित एमजीआई सचिवालय की स्थापना और मेजबानी करेगा और एमजीआई परियोजनाओं और शासन का समर्थन करने के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करेगा।'' जलवायु परिवर्तन की कोई सीमा नहीं होती–

इस क्षेत्र में धूल भरी आंधी का आर्थिक प्रभाव प्रतिवर्ष 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए एक गठबंधन की आवश्यकता है। जो पूरे क्षेत्र में प्रासंगिक हितधारकों को एकजुट करेगा और उनका समर्थन करेगा। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में बढ़ते तापमान के प्रभाव पहले से ही आजीविका और अवसरों पर असर डाल रहे हैं। Saudi & Middle East Green Initiatives - ENDORSING COUNTRIES

Algeria, Bahrain, Brazil, Chad, Djibouti, Egypt, Greece, India, Iraq, Italy, Jordan, Kuwait, Libya, Morocco, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Tanzania, Tunisia, United Arab Emirates, United Kingdom, Yemen

यदि हम मध्य पूर्व की वास्तविक परतों की परताल करें तो, जनवरी 2021 तक, यूनिसेफ वेबसाइट ने 20 देशों के निम्नलिखित समूह को MENA (Middle East North Africa) क्षेत्र से संबंधित बताया है : 'अल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, मिस्र, ईरान (इस्लामिक गणराज्य), इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब, फिलिस्तीन राज्य, सूडान, सीरियाई अरब गणराज्य, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। अन्य में इजराइल भी शामिल है।

मनुष्यों द्वारा उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की पहचान IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change-1988) और अधिकांश जलवायु वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के प्राथमिक चालक के रूप में की है। पिछले तीन दशकों में, MEANA (Middle East & North Africa) क्षेत्र ने अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को तीन गुना से अधिक कर दिया है और वर्तमान में प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत से ऊपर उत्सर्जन कर रहा है, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले शीर्ष दस देशों में से अधिकांश मध्य पूर्व में पाए जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन का इराक पर प्रभाव–

आईए जानते हैं, की जलवायु परिवर्तन का इराक पर कैसे प्रभाव पड़ता है? इराक में, जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय प्रभाव बढ़े हैं, जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी, भूमि क्षरण और पानी की कमी। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य, आजीविका, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्र के सतत विकास के लिए कई जोखिम पैदा करता है। पारिस्थितिक कारक, संघर्ष, कमजोर शासन और जलवायु परिवर्तन को कम करने की बाधित क्षमता के संयोजन ने इराक को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए विशिष्ट रूप से जोखिम में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें जलवायु परिवर्तन के लिए 5वां सबसे कमजोर देश बताया है। बढ़ता तापमान, तीव्र सूखा, घटती वर्षा, मरुस्थलीकरण, लवणीकरण और धूल के तूफानों का बढ़ता प्रचलन ऐसी चुनौतियाँ हैं। यदि हम इराक से संबंधित लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें तो हम पायेंगे कि जिनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, भूमि से विस्थापन, आर्थिक संघर्ष और संसाधनों की कमी शामिल हैं। बढ़ते तापमान, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, भूमि क्षरण और सूखे ने कृ षि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है , जिससे पैदावार

कम हुई है और कृषि योग्य भूमि का नुकसान हुआ है। इन प्रभावों के कारण कृषि पर निर्भर ग्रामीण आबादी प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक अवसरों में कमी के कारण शहरी केंद्रों की ओर जा रही है। 2022 में, इराक ने 40 वर्षों में सबसे खराब सूखे का अनुभव किया है। जिसके कारण 69,000 लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ। शोध में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विस्थापन के जोखिम के लिए सबसे मजबूत भविष्यवक्ता हैंः पानी से संबंधित मुद्दे, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी, और उनकी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता। MENA मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र का संक्षिप्त नाम है। इस क्षेत्र में आमतौर पर लगभग 19 देश शामिल माने जाते हैं, लेकिन परिभाषा को बढ़ाकर 27 तक किया जा सकता है।

विश्व बैंक ने MENA के भाग के रूप में 21 देशों को शामिल किया है और उनकी 2020 की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर, इस क्षेत्र में विश्व की लगभग 6 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries-1960) के आंकड़ों के अनुसार, MENA क्षेत्र में विश्व के आधे से अधिक तेल भंडार तथा विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का दो–पांचवां हिस्सा मौजूद है। क्षेत्र के पर्याप्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन के कारण, MENA वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

महासागर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव (Effect of Climate Change on the ocean)

आईपीसी की पांचवी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित कार्बन उत्सर्जन के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि का

90% विश्व के महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है वायुमंडल द्वारा इसका मात्र एक परसेंट अवशोषित किया जाता है। समुद्र स्तर में वृद्धि के तात्कालिक प्रभाव में सतही जल में लवणीय जल का अतिक्रमण गंभीर तूफान की तीव्रता में वृद्धि तटीय भूमि में आप लवण एवं बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि शामिल है। समुद्र जल स्तर में वृद्धि ताजे जल की आपूर्ति लवली कारण के माध्यम से खाद उपजो कृषि योग्य भूमि की हानि के माध्यम से और भौतिक सुरक्षा यानी की सड़क अवसान और सफाई व्यवस्थाओं जैसी तटीय और संरचना को छत की माध्यम से कुछ संकटग्रस्त करती है जिसके परिणाम स्वरुप निम्न समुद्र तल वाले कई छोटे द्वितीय राष्ट्रों से लोगों का विस्थापन होता है। मध्य पूर्व में अधिकांश वर्षा उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं के कारण होती है या उसी से संबंधित होती है। ग्रीष्म ऋतु लगभग पूरी तरह शुष्क होती है, जिसमें विषम समकालिक स्थितियों के कारण कभी–कभार बारिश होती है।

पृथ्वी के वायुमंडल पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों के पर्यावरण में भारी बदलाव किए हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित है। इसने वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, तीव्र गर्मी की लहरें, कम और अनियमित वर्षा और जल संसाधनों में सामान्य गिरावट के रूप में रूप लिया है। ये सभी लगातार और लंबे समय तक सूखे, रेगिस्तानीकरण और गहन और आवर्ती (एसडीएस) को जन्म दे रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों ने पृथ्वी के वायुमंडल में (जीएचजी) के उत्सर्जन को बढ़ा दिया है। सभी भविष्य के अनुमान विशेष रूप से (आईपीसीसी) मॉडल और उत्सर्जन परिदृश्यों का उपयोग करने वाले संकेत देते हैं कि इस सदी के अंत तक मध्य पूर्व में बढ़ते तापमान के साथ सर्दियों की

वर्षा में सराहनीय कमी आएगी, जो दोनों ही सूखे और रेगिस्तानीकरण में वृद्धि के लिए प्रेरक हैं। इराक इस क्षेत्र के देशों में से एक है और इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, इसकी निर्भरता ज्यादातर पड़ोसी देशों से आने वाले सतही जल संसाधनों पर है, लंबे समय तक उपेक्षा और खराब भूमि प्रबंधन ने इसे क्षेत्र के अन्य देशों के बीच सबसे अनिश्चित और अस्थिर स्थिति में डाल दिया है। मॉडलिंग अध्ययनों से पता चला है कि इराक अब अत्यधिक सूखे और अकाल, वनस्पति आवरण क्षेत्रों के बढ़ते नुकसान, कृषि भूमि पर रेत के टीलों के बढ़ते अतिक्रमण, गंभीर और लगातार (एसडीएस) के अलावा पीड़ित है। इन नकारात्मक नतीजों और उनके शमन के लिए न केवल स्थानीय स्तर पर समाधान की आवश्यकता है, बल्कि क्षेत्र के सभी देशों से सामूहिक सहयोग और काम की आवश्यकता है। मध्य पूर्व में मौसम की स्थिति के भविष्य के रुझान की जांच करने के लिए, सबसे पहले वर्तमान में प्रचलित जलवायु परिस्थितियों और उनके पीछे सभी मजबूर करने वाले कारकों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ाता है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र को अति–शुष्क, अर्ध–शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्य पूर्व में अधिकांश वर्षा उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं के कारण होती है या उसी से संबंधित होती है। ग्रीष्म ऋतु लगभग पूरी तरह शुष्क होती है, जिसमें विषम समकालिक स्थितियों के कारण कभी–कभार बारिश होती है। सर्दियों में वर्षा बड़े पैमाने पर भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है जो उत्तरी अटलांटिक दोलन (एनएओ) से जुड़े होते हैं और अक्टूबर और मई की वर्षा लाल सागर गर्त प्रणाली का परिणाम होती है जो तीव्र वर्षा और बाढ़ का कारण बन सकती है, हालांकि यह तीव्र रेत के तूफानों के लिए भी

जिम्मेदार होती है। ''मध्य पूर्व में भविष्य में जलवायु परिवर्तन की अपेक्षित प्रवृत्तियाँ।''

ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा स्थितियों में, जो मुख्य रूप से (जीएचजी) उत्सर्जन में वृद्धि के परिणामस्वरूप होती है, सभी अनुमान विशेष रूप से (आईपीसीसी) मॉडल और उत्सर्जन परिदृश्यों का उपयोग करने वाले अनुमान संकेत देते हैं कि मध्य पूर्व में इस सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि के साथ सर्दियों की वर्षा में सराहनीय कमी आएगी, जो दोनों ही सूखे और रेगिस्तानीकरण में वृद्धि के लिए प्रेरित हैं। इस क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन के इतिहास के अध्ययन, जो केवल प्राकृतिक चालकों के कारण हैं, जलवायु स्थितियों के उलट होने का सुझाव देते हैं और निकट भविष्य में इस क्षेत्र में सूखे में वृद्धि की भावी प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। इसकी पुष्टि प्रारंभिक और मध्य–होलोसीन के दौरान जलवायु स्थितियों की तुलना वर्तमान समय की स्थितियों से की गई है, जो प्राकृतिक और मानवजनित दोनों तरह के जलवायु परिवर्तन बल चालकों का उपयोग करके और मॉडल और वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण मॉडल से जुड़े आदर्श सिमुलेशन का उपयोग करके किया गया था। निष्कर्ष यह था कि प्रारंभिक और मध्य–होलोसीन अवधि के दौरान उत्तरी यूरोप, भूमध्यसागरीय और मध्य पूर्व क्षेत्रों में वर्षा, जैसा कि पैलियोक्लाइमेट प्रॉक्सी (विशेष रूप से वनस्पति) के अध्ययन से प्राप्त हुआ था, आज की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न थी, दक्षिणी यूरोप, भूमध्यसागरीय और मध्य पूर्व अधिक आर्द्र थे, और उत्तरी यूरोप आज की तुलना में सूखा था। लेकिन यूरोप के लिए वर्षा और तापमान की स्थितियों में उलटाव का संकेत दिया गया था। उत्तरी यूरोप के लिए वनस्पति पुनर्निर्माण ने ठंडी सर्दियाँ, गर्मियाँ और अधिक उपलब्ध नमी का सुझाव दिया।

संदर्भ–ग्रंथ–सूची–

1. भौगोलिक मॉडल–माजिद हुसैन और रमेश सिंह पृष्ठ न. 249.

2. United Nation Official Website

3. कॉपरनिकस कार्यक्रम

4. Wikipedia – Climate change in middle east-

5. जिव, बी., सारोनी, एच. और अल्परट, पी. (2004) पूर्वी भूमध्य सागर के ग्रीष्मकालीन शासन को नियंत्रित करने वाले कारक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, 24, 1859–1871. https%//www-interscience-wiley-com

1- https%//rmets-onlinelibrary-wiley-com/doi/epdf/10-1002/joc-1113

2- https%//doi-org/10-1002/joc-1113^^

भारत-इजराइल संबंध अतीत से वर्तमानः चुनौतियाँ और संभावना

सतीश कुमार दूबे,

शोधार्थी–रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग,

जी.एस.पी.जी.कॉलेज, सुलतानपुर।

इजराइल से संबंध स्थापना का प्रश्न भारत की विदेश नीति और राजनय के इतिहास में एक अव्दितीय मिशाल प्रस्तुत करता है। 14 मई 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना के लगभग 44 वर्षों के पश्चात भारत ने 90 के दशक में इजराइल देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना करता है और उनका परिवर्ती विकास सामान्य रूप से पश्चिम एशिया और विशेष रूप से इजराइल के प्रति भारत की परंपरागत नीति में आये महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, कृषि आदि क्षेत्रों में करीबी संबंध विकसित हुए।

दोनों देशों के संबंध पारस्परिक जरुरत के आधार पर विकसित हो रहा हैं। भारत के लिए इजराइल उन्नत तकनीकि की प्राप्ति के एक बड़े स्त्रोत के रुप में उभरा है। जिसमें रक्षा,कृषि,जलसचंयन,उड्डयन सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भारत इजराइल की तकनीकि को प्राप्तकर रहा है। चीन को इजराइल का व्यापारिक साझेदार माना गया है जबकि भारत को इजराइल का सामरिक साझेदार माना गया है। ईरान कारक के रुप में भारत इजराइल संबंधों के विकास में एक कमजोर कड़ी माना गया है। इजराइल

ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कटु आलोचक है और इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। भारत गणराज्य और इजराइल राज्य के बीच संबंध आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंधों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। इजराइल ने नई दिल्ली में अपना दूतावास और मुंबई और बंगलूरू में अपना वाणिज्यिक दूतावासों के साथ इजराइल भारत में एक मजबूत राजनयिक उपस्थिति बनाए रखता है। इसके विपरीत भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व तेल अवीव में अपने दूतावास के माध्यम से है। भारत और इजराइल के मध्य व्दिपक्षीय संबंधों में राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, कृषि और सांस्कृतिक पहलू शामिल है। भारत–इजराइल दोंनों व्दिपक्षीय संबंधों को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करते है।

इजराइल और भारत भले ही एक वर्ष के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की हो या फिर 1950 में भारत ने इजराइल को राजनयिक रूप से इजराइल को एक देश की मान्यता दी हो, परन्तु भारत और इजराइल के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। शुरुआती संबंधों को भारत और इजराइल के मध्य शीत युध्द के युग की जटिल भू–राजनीति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जबकि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा होने की वजह से सोवियत ब्लाक और अरब दुनिया के साथ गहरा संबंध बनाये रखता था। दूसरी तरफ, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और NATO का सहयोगी था। भारत और इजराइल के मध्य संबंधों में गर्मजोशी तब आने लगी जब 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान और 2001 के भुज भूकंप के बाद आपदा राहत के दौरान इजराइल ने खूफिया सहायता प्रदान की। भारत इजराइल के प्राथमिक व्यपारिक साझेदारों मे से एक है। रणनीतिक रूप से, इजराइल–भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्यौगिकी और विशेषज्ञता प्रदान करता है। इसने भारत की

रक्षा क्षमताओं को मजबूत आधार प्रदान किया है। जैसे उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली और बराक–8 प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली जैसे 2 बिलियन के सौदे जैसे समझौते ने भारत के रक्षा तैयारियों को बढ़ाया है। भारत और इजराइल के मध्य आर्थिक रूप से व्दिपक्षीय व्यापार में काफी वृध्दि हुई है, जो सालाना लगभग 6 बिलियन तक पहुँच गया है। भारत इजराइल से प्रौद्योगिकी और नवाचारों का आयात करता है। फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारतीय (STARTUP) और संयुक्त उद्दमों में इजराइली निवेश भारत में आर्थिक विविधीकरण और रोजगार सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर भारत और इजराइल के मध्य आर्थिक और वाणिज्यिक व्यापार की गणना करें तो इन दोनों के मध्य कोविड–19 महामारी से पहले के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 जनवरी तक लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इजराइली कंपनियों भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूर संचार, रियल एस्टेट, जलप्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान और विकास केन्द्र या उत्पादन इकाईयाँ स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिए इजराइल के साथ भी बातचीत कर रहा है।

रक्षा

भारत – इजराइल से हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। जिसका एक वर्ष में तकरीबन 40 प्रतिशत का योगदान देता है। पिछले कुछ वर्षों इजराइली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है। जिसमें से फाल्कन AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एण्ड कंट्रोल सिस्टम)

हेरॉन, सर्चर–2, हारोप ड्रोन से लेकर बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक–रियक्शन विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल है।

दोनों देशों ने 2022 में औद्योगिक खोज और विकास (RESEARCH & DEVELOPMENT) और नवाचार निवेश के दायरे को बढ़ाया जिसमें अक्षय ऊर्जा एवं ICT जैसे क्षेत्रों के शिक्षा तथा व्यवसायिक संस्थाओं की भागीदारी वृध्दि शामिल है। दोनों देश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग समय के साथ बराबर बढ़ता जा रहा है। प्रौद्योगिकी साझेदारी, सुरक्षा सहयोग, राजनीतिक सुरक्षा इजराइल और भारत के मध्य रणनीतिक संबंधों के मुख्य स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने संयुक्त वक्तव्य में साझा हितों, आपसी सहयोग एवं सद्भाव को बढ़ावा देने की बात कही। संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का उल्लेख नहीं किया गया। दोनों नेता ने पिछले कुछ वर्षों में भारत–इजराइल व्दिपक्षीय संबंधों को मजबूती के लिए एक–दूसरे के द्वारा चर्चा की गई।

इन क्षेत्रों में 9 समझौते हुए हैं–

1. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग।
2. तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग।
3. हवाई परिवहन समझौते में संशोधन पर प्रोटोकॉल।
4. फिल्म सह–उत्पादन पर समझौता।
5. होम्योपैथिक औषधियों से जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग।
6. अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग।
7. इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट इन इजराइल।

8. मेटल–एयर बैटरियों के क्षेत्र में सहयोग।

9. संकेन्द्रित सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग।

भारत ने इजाइल की जो रक्षा कंपनिया है उनको 'मेंक इन इंडिया' में संयुक्त उत्पादन के लिए आमंत्रित किया। इजराइल यदि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश करता है तो इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत होगी। जो इजराइल से हथियार के आयात पर खर्च होता है यह हमें ज्ञान होना चाहिए कि रूस के पश्चात इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्त्ता है। भारत ने इजराइली कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में भारत की उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का लाभ उठाने के लिए संयुक्त उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया।

भारत और इजराइल के प्रगाढ़ होते संबंधों से भारत–फिलिस्तीन संबंध प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन भारत के रुख में बड़ा बदलाव नहीं आया है। हाल ही में जब अमेरिका ने यरूशलम को इजराइल की राजधानी स्वीकार करने का विवादास्पद बात की। जब संयुक्त राष्ट्र में बयान दिया तो भारत सहित 128 देशों ने इसका विरोध किया जबकि केवल नौ देशों

नें ही इसके पक्ष में वोट किया और 35 देश अनुपस्थित रहे। अमेरिका के फैसले को अमान्य घोषित किया गया। जब चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के मद्दे नजर भारत ने जुलाई 2020 में इजरइल से अतिरिक्त हथियार खरीदने की योजना की घोषणा की। इजराइल और भारत दोनों के रक्षा मंत्रियों ने व्दिपक्षीय संबंधो को मजबूत करने पर चर्चा की है। जहाँ भारतीय रक्षा क्षेत्र में इजराइली रक्षा कंपनियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में रुचि व्यक्त की गई है।

भारत–इजराइल संबंधो में नवीनतम घटना चक्र

इजराइली राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा, MAD–मैगन डेविड एडोग(हिब्रू में इसका अर्थ है रेड स्टार आफ डेविड) और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी (IRC) ने जुलाई 2017 के दौरान एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य IRCS के प्रथम प्रत्युत्तरकर्त्ता कौशल में सुधार और उन्नयन करना था। भारत को इजराइल ने सैन्य उपयोग के लिए रडार और निगरानी उपकरण बेंचे है और यह भारत के आतंकवाद विरोधी बलों को उग्रवाद विरोधी प्रशिक्षण भी देता है। 10 मई 2017 को भारतीय नौ सेना के तीन युद्धपोत हाइफा बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह पर पहुँचने पर इन जहाजों, आईएनएस मुंबई, आईएनएस त्रिशुला और आईएनएस आदित्य ने इजराइली नौ सेना के साथ नौसेना अभ्यास में भाग लिया। भारत ने अपनी पश्चिमी एशिया नीति में सामरिक स्वयत्ता की नीति का प्रदर्शन है। पश्चिमी एशिया के राजनीतिक–सामरिक समीकरण में कई ध्रुव हैं। अब भारत की नीति कई ध्रुव के साथ संबंध न होकर सभी के साथ स्थिति के अनुरुप संबंध विकसित करने और स्वयत्ता बनाये रखने की है। भारत–ईरान के मध्य रक्षा सहयोग को इजराइल अपनी सुरक्षा चिंता के विरोध में देखता था। उसे भय था कि भारत,

इजराइल रक्षा सहयोग में भारत को दी जाने वाली प्रौद्योगिकी कहीं ईरान के हाथ न लग जाए। इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में भारत ने ईरान से अपने संबंधों को रक्षा क्षेत्र में कम अवश्य किया है, लेकिन ऊर्जा जरूरतों में अफगानिस्तान मध्य एशिया में ईरान के माध्यम से पहुँच बनाने और इस नजरिये से चाबहार पोर्ट का विकास करने और अफगानिस्तान पर सहयोग जारी रखा है। वस्तुतः भारत और ईरान दोनों को एक–दूसरे की जरुरत है। ईरान, भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ईरान, भारत की ऊर्जा जरुरत को पूरा करता है। दोनों देशों में गैर–ऊर्जा व्यापार भी बढ़ा है। ईरान के माध्यम से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी पहुँच बनाना चाहता है। इसी दृष्टि से ईरान में चाबहार पोर्ट का विकास के लिए 100 मिलियन डॉलर के निवेश की योजना बनाई है।

2009 में भारत ने गैस पाइप लाइन से अपने को बाहर रख लेने के बाद ईरान–पाकिस्तान–भारत गैस पाइप लाइन अब अतीत का मुद्दा बन चुका है। अफगानिस्तान में दोनों देशों के साझा सामरिक हित हैं। दोनों ही तालिबान के विरोधी हैं। इस प्रकार भारत ने इजराइल को समझाने की कोशिश की है कि भारत का ईरान से संपर्क इजराइल के राष्ट्रीय हितों उसकी सुरक्षा चिंताओं के विपरीत नही है। भारत–इजराइल सामरिक संबंधों में पाकिस्तान कारक नकारात्मक भूमिका निभा सकने की संभावित क्षमता रखता है। 2 जून 2013 में इजराइली समाचार पत्र 'हारेत्सृ में छपी एक खबर के अनुसार एक ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पाकिस्तान और चार अरब राज्यों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है।3 इजराइल ने पाकिस्तान को इजराइली सैन्य तकनीक के हस्तांतरण के कथित समाचार का तत्काल खंडन किया। 4 इजराइल व्दारा पाकिस्तान के हथियार आपूर्ति करने की उक्त खबर भारत

इजराइल सामरिक साझेदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह सच है कि इजराइल, पाकिस्तान में राजनीतिक संपर्क बढ़ा रहा है और इसी क्रम में 2005 में पाकिस्तान और इजराइल के विदेश मंत्रियों की तुर्की के इस्तांबुल में बैठक हुई थी और पाकिस्तान यह पूरी कोशिश करेगा कि उसका इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हो जाए, क्योंकि इससे इस्लामिक जगत में इजराइल की स्वीकार्यता पाकिस्तान के औचित्य का भाव बढ़ायेगी।

भारत की इजराइल समर्थक नीति का आशय यह नहीं है कि भारत पश्चिम एशिया के अन्य महत्वपूर्णकर्त्ताओं की अवहेलना कर रहा है। भारत जो है वो अपनी पश्चिम एशिया नीति में उसे एक संतुलन दिखाई देता है। इसलिए भारत किसी एक कर्त्ता के साथ संबंद्ध होने की बजाए बहुमुखी संबद्धता की नीति पर बल दिया है, जो कि भारत की बहु–बेक्टर उन्मुख नीति की ओर संकेत करता है। जो भारत सामरिक से संबंधित स्वायत्ता की नीति है, वह भी देखने को मिलती है। भारत ने विदेश नीति निर्माण एवं राजनय में सामरिक स्वायत्ता पर बल दिया है। यहाँ सामरिक स्वायत्ता का आशय बाहरी दबाव के बिना वं राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए विदेशनीति के निर्णय निर्माण में स्वतंत्र धारा का अनुसरण करना है।

संदर्भः–

1. **Narain D. Baatra, "Complicated relationship : India needs both Israel & Iran."**
2. **अनूप कुमार गुप्ता," पाक-इजराइल संबंधों का मतलब"**
3. **Aluf Benn," Israel Selling Military wares to mideast countares, Britain says."**

4. **Aluf Benn and Gili Cohen,‘‘Following Haaretz report Israel denies selling arms to pakistan.’’**
5. **Pakistan Military technology row threatens Israel Strategic relationship with India.”the telegaph.**
6. **The Hindu Israel – India latest developments.**
7. **The Economic Times – India and Israel relations in news**

रूस-यूक्रेन युद्ध का भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव

सुजीत सिंह, (शोध छात्र),

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा

रूस–यूक्रेन युद्ध से पूरी दूरी दुनिया प्रभावित है भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है दिल्ली मे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के दीक्षांत समारोह मे वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि "रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया मे ऊर्जा संकट को भी हवा दी है, जिसके परिणामस्वरूप भारत भी काफी हद तक प्रभावित है द्यक्योंकि युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति मे व्यवधान उत्पन्न हुआ। जिसके कारण ऊर्जा आयात कि मूल्यों मे काफी वृद्धि हो गई है रूस और यूक्रेन के मध्य लगातार युद्ध जारी है, अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध मे खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है द्य जिसके परिणामस्वरूप बड़ी शक्तियों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रूस–यूक्रेन युद्ध के प्रभावों के कारण दुनिया को डॉ भागों मे विभाजित करने की प्रयास लगातार जारी है हालांकि भारत ने इस युद्ध मे गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति जारी रखी है साथ ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रूस और यूक्रेन को सलाह दी है द्यकि "वे बात–चीत के माध्यम से विवादों का समाधान करे, क्योंकि युद्ध किसी समस्या को हाल करने का विकल्प नहीं है" हाल ही मे रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अपनी रूसी समकक्षों को बात–चीत समस्या हल करने की सलाह दी राजनाथ सिंह ने कहा "जब किसी भी क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा होता है तो उससे विश्व परिदृश्य मे कई तरह से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, रूस–यूक्रेन संकट के

कारण विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देशों मे खाद्य संकट पैदा हो गया है हालांकि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए खाद्य संकट भारत मे नहीं है गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान अब तक दोनों देशों को जान–माल की काफी नुकसान हो चुका है अमेरिका के शीर्ष जनरल बुधवार को अनुमान लगाया कि युद्ध मे रूस कि सेना के मारे गए घायल सैनिकों की संख्या 1000,000 से अधिक हो गई है वही यूक्रेन की सेना को भी सायद इतना ही नुकसान झेलना पड़ा है इसके साथ ही उन्होंने बताया की युद्ध के दौरान अब तक लगभग 40,000 यूक्रेनी नागरिक मारे गए लाखों यूक्रेनी नागरिक दूसरे देशों मे शरण ली द्य यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए है इस जंग का अंत कब होगा, ये भी नजर नहीं आ रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल है अप्रेल के महीने मे विश्व व्यापार संगठन (W.T.O) ने रूस–यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस वर्ष वैश्विक व्यापार वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 4.7 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत कर दिया है।

तत्कालीन परिस्थितियों मे सबसे महत्वपूर्ण है रूस–यूक्रेन जंग को रोकना व शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाना अपरिहार्य हो गया है इस जंग से केवल रूस और यूक्रेन प्रभावित नहीं हो रहे है वल्कि वर्तमान वैश्विकृत दुनिया इस स्थानीय जंग के प्रभावों को वैश्विक बना रही है, लंबे समय से जारी कोविड–19 महामारी के गहरे और नकारात्मक प्रभावों से निपटते हुए दुनिया विकास के रास्ते पर अग्रसर थी परंतु इस जंग ने दुनिया का ध्यान पूरी तरह बाँट दिया है हालांकि, यह आश्चर्य की बात थी कि जो रूस, जंग की शुरुआत में ही यूक्रेन के संचार व्यवस्था को प्रभावित कर सकता था उसने वैसा नहीं किया बल्कि अपने हमलों में बेहद चयनात्मक रूख अपनाया. जबकि उन्होंने सैन्य कमान और

नियंत्रण प्रणाली को हैक कर लिया था लेकिन उन्होंने नागरिक बुनियादी ढांचे को काफी हद तक निशाना नहीं बनाया. इसे लेकर एक थ्योरी यह कहती है कि रूस ने यूक्रेन जंग में आसान और जल्द जीत की उम्मीद की थी और वो उस नेटवर्क को व्यवस्थित बनाए रखना चाहते थे जिससे कि वो इसका इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर सकते थे।

पिछले महीने एक रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि सैनिक ऑपरेसन से एक साल पूर्व ही रूस ने डिजिटल हमला शुरू कर दिया था। रूसी साइबर हमलावरों ने 2021 के अंत तक कई यूक्रेनी ऊर्जा और आईटी सेवा देने वाले संस्थानों तक सेंधमारी कर ली थी. जनवरी में रूसी आक्रमण से पहले, शोधकर्ताओं ने यूक्रेनी सिस्टम में व्हिस्परगेट नामक एक मालवेयर पाया था. यह 2017 के पहले के साइबर हमले को बताता है जिसने हजारों सिस्टम में डेटा को नष्ट कर दिया था. जंग के साथ ही इन टारगेट को विनाशकारी वायरस से निशाना बनाया गया. हालांकि, जब रूस का हमला 23 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल के बीच तेज हुआ तब इस कंपनी ने पाया कि यूक्रेन के टारगेट पर 37 विनाशकारी साइबर हमले किए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई हमलों को रूसी सेना के काइनेटिक ऑपरेशन के साथ तालमेल बिठा कर किया गया था।

रोसेन का मानना था कि अमेरिकी सरकार ने इसे "रक्षात्मक" साइबर ऑपरेशन के रूप में इस्तेमाल किया और रूसी संचार प्रणाली पर निशाना साधा. रूस की 3 जी नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया जिससे रूस की जमीनी सेना और उनके कमांड के बीच की बातचीत गोपनीय नहीं रह सकी. हालांकि जनरल नाकासोन ने यह खुलासा करने से इंकार कर दिया कि यह अमेरिकी ऑपरेशन किस तरह का था

लेकिन उन्होंने दावा किया कि फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन, "आक्रामक, रक्षात्मक, और जानकारी" आखिरकार अमेरिका की सुरक्षा हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था।

यूक्रेन की बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रपति जेलेंस्की की विश्व नेताओं के साथ संवाद कायम करने और रूसी हमले के बीच खुद को यूक्रेन की एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित करने की क्षमता में थी. जेलेंस्की अपनी ऑलिव ग्रीन टी–शर्ट में वीडियो के जरिए विश्व नेताओं और संसदों से बात करते रहे और सोशल मीडिया पर निरंतर मैसेज भेजते रहे, जिसकी भूमिका यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने में काफी रही. एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इन्फॉर्मेशन वारफेयर का मुकाबला करने का एक बड़ा प्रयास यूक्रेन की सरकार द्वारा ही किया जा रहा है, जिसकी सहायता के लिए 3 लाख यूक्रेन के आईटी पेशेवर खुद से दिन रात जुटे हुए हैं हालांकि, एक सच्चाई यह भी है कि 16 जून को बर्गेनस्टॉक में आयोजित शांति सम्मेलन यूक्रेन के लिए बहुत लाभदायक नहीं था, बल्कि एक झटके की तरह था. इस शांति सम्मेलन में यूक्रेन को ग्लोबल साउथ और एशिया के बड़े देशों का समर्थन हासिल नहीं हो पाया था. भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों ने इस सम्मेलन के आखिर में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. इस देशों द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने की वजह यह थी कि इस शांति प्रक्रिया में रूस शामिल नहीं था. यही कारण है कि रूस के मुद्दे पर ज्यादातर पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल करने के बाद यूक्रेन ने अब ग्लोबल साउथ और एशियाई देशों की ओर रुख किया है और इस मुद्दे पर इन देशों का समर्थन हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन द्वारा दूसरा शांति सम्मेलन

ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित किया जा सकता है जिस तरह से हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चीन की यात्रा की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंच रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कीव रूस के साथ जंग को रोकने की कवायद में जुटा है और इसके लिए एक मजबूत व सक्षम मध्यस्थ की तलाश कर रहा है। यूक्रेन के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की मुख्य सलाहकार एलिना हीत्सेंको के मुताबिक जी7, रूस और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के राजनीतिक संबंध और नजदीकी बीजिंग की तुलना में अधिक है। जाहिर है कि पश्चिमी देशों द्वारा चीन को जहां एक विस्तारवादी देश माना जाता है, वहीं ग्लोबल साउथ के राष्ट्र चीन को अपना वर्चस्व कायम करने वाला देश मानते हैं. इसके अलावा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि चीन पिछले एक दशक में रूस का सबसे बड़ा साझीदार बनकर उभरा है। ये सभी परिस्थितियां वर्तमान में रूस–यूक्रेन टकराव को रोकने के लिए नई दिल्ली को एक भरोसेमंद एवं उपयुक्त मध्यस्थ बनाती हैं. एलिना हीत्सेंको ने आगे कहा कि भारत में रूस–यूक्रेन के बीच शांति बहाली की किसी भी प्रक्रिया में ग्लोबल साउथ के देशों को शामिल करने की क्षमता है प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं. जैसे कि हो सकता है कि पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के जरिए भारत–रूस रिश्तों को लेकर जी7 की गलतफहीम की दूर करना चाहते हैं। इसके अलावा, हो सकता है कि पीएम मोदी अपनी इस यूक्रेन यात्रा के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता बेहद महत्वपूर्ण है और वो किसी भी दबाव में बदलने वाली नहीं है। मोदी की इस यात्रा के पीछे एक और वजह भी हो सकती है, जो काफी अहम भी है, यानी रूस–यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने और दोनों पक्षों के बीच शांति की

बहाली के प्रयासों में भारत की भूमिका. दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में भारत की दिलचस्पी बढ़ रही है, इसके साथ ही भारत यूरोप की सुरक्षा से जुड़े मसलों में सक्रीय भूमिका निभाना चाहता है। ऐसे में भारत इस युद्ध का समाधान निकालने में मध्यस्थ बनने की पेशकश कर सकता है। जहां तक कीव की बात है, तो वो पीएम मोदी की इस यात्रा को यूक्रेन की संप्रभुता के लिए भारतीय समर्थन के रूप में देख रही है। इसका कारण है कि पीएम मोदी की यह यात्रा यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हो रही है. यूक्रेन द्वारा इसे नई दिल्ली की ओर से एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रूस–यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से पहले भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था. पीएम मोदी की इस यात्रा के पीछे इस द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का भी मकसद है और यह तभी संभव हो सकता है जब यह युद्ध समाप्त हो और शांति की बहाली हो. ऐसे में उम्मीद है कि यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी इस युद्ध की समाप्ति और स्थाई रूप से शांति स्थापित करने के समाधानों पर चर्चा करेंगे. जाहिर है कि इन दिनों वैश्विक स्तर पर रूस–यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को बातचीत के माध्यम से समाप्त करने के बारे में चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसी चर्चाओं के पीछे बड़ी वजह अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को इस मुद्दे पर अमेरिकी जनमानस का मिला जबरदस्त समर्थन भी है। कहने का मतलब है कि अगर अमेरिकी चुनावों में ट्रम्प की जीत होती है, तो रूस–यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को बातचीत के जरिए समाप्त करने में अमेरिका अपनी सशक्त भूमिका निभाएगा रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े हुए ढाई साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इसे समाप्त करने के प्रयासों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन की यह आधे दिन की यात्रा बेहद

महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का यह यूक्रेन दौरा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की हदों को जाहिर करता है। यह दौरा बताता है कि भारत दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में किसी एक के पक्ष में नहीं खड़ा है। इसे साबित करने के लिए ही पीएम मोदी रूस की यात्रा के बाद पोलैंड से ट्रेन पर सवार होकर यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं. तमाम वैश्विक नेताओं द्वारा पोलैंड से यूक्रेन तक ट्रेन के जरिए यात्रा करने को ''आयरन डिप्लोमेसी'' के रूप में भी जाना जाता है। यूक्रेन रेलवे के सीईओ ओलेक्सांद्र कामिशिन ने ''आयरन डिप्लोमेसी'' शब्द का पहली बार उपयोग किया था। जाहिर है कि युद्ध की वजह से हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद है और रेलगाड़ी के जरिए ही विश्व के तमाम नेता कीव पहुंचते हैं और जताते हैं कि वे यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं. जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की ट्रेन यात्रा का सवाल है, तो वे शांति पर चर्चा के लिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं. हालांकि, देखा जाए तो रूस–यूक्रेन युद्ध में हाल–फिलहाल में एक नया घटनाक्रम जुड़ा है और यूक्रेनी सेनाओं ने रूस के कुर्क्स इलाके पर कब्जा कर लिया है। इन ताजा हालातों के बीच यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए क्या संदेश लेकर पहुंचे हैं और वे उनसे क्या अपील करेंगे।

सन्दर्भः–

1. **दैनिक जागरण 10 नवंबर 2022**
2. **दैनिक जागरण 10 नवंबर 2022**
3. **https://www.orfonline.org/hindi/research/the-russia-ukraine-war-hybrid-warfare**

4. **https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/expert-speak-in-the-quest-for-a-lasting-peace-modi-s-visit-to-kyiv**

5. **https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/expert-speak-in-the-quest-for-a-lasting-peace-modi-s-visit-to-kyiv**

6. **https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/expert-speak-in-the-quest-for-a-lasting-peace-modi-s-visit-to-kyiv**

7. **https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/expert-speak-in-the-quest-for-a-lasting-peace-modi-s-visit-to-kyiv**